

लाल किले में

१८५८ और १९४५-४६ के  
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुक-  
दमों की एक सुनहरी मंजी

सम्पादक

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

भूमिका

महात्मा भगवानदीन जी

मा र वा ङी प बिल के श न

४० ए, दलमान रोड

नई दिल्ली (१)

प्रकाशकः—

मारवाड़ी पब्लिकेशन्स  
होप सर्कस, अलवर.

मुद्रकः—

जगन्नाथप्रसाद शर्मा  
भानु प्रिंटिंग प्रेस,  
धरमपुरा, दिल्ली ।

विक्रेताः—

मारवाड़ी पब्लिकेशन्स  
४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली (१)

मूल्य २॥॥

शक व्यय के साथ २॥॥—)

पी० पी० मे २॥॥३) शर्ष पड़ेगा ।

## पढ़िये

“लाल किले में” किताब में है क्या,—यह आपके जी में जरूर आयेगा। नाम ही अनोखा है। यह कोई कहानी या उपन्यास नहीं; पर, उस जैसा दिलचस्प जरूर है। फिर, अपने मुल्क वालों की एक दिल से की गई कोशिशों क्यों मनचीता फल न ला सकी,—उमरी बात भी तो इसमें है।

शाहजहां ने शाहजहानाबाद—दिल्ली—में जब शाहजहांगढ़ लालकिले—की नींव डाली थी, तब उसको ख्याल न था कि उसको अपने ही किले में अपने एक बेटे और अपनी एक बेटी के हाथों कैदी बनाया जायगा। उसे यह भी पता न था कि उसके खानदान का एक बादशाह कुछ खास सिपाहियों की फौजी अदालत के सामने मुजरिम के कटहरे में खड़ा होकर घायन देगा। ताजमहल में लेटी हुई उसकी रूह में क्या क्या इनकलाब हुये होंगे, कौन जाने? बहादुर शाह को ही यह कब मालूम था कि मुजरिम की हैसियत से दिया हुआ उसका सीधा-सादा घायन इतनी छिपी हुई गरमी रखता है कि मरने के बाद उसकी कब्र में की खाक उसीके मुल्क के एक फर्द के हाथ पड़कर उसके मुल्क का रंग बदल देगी। फिरंगी को अगर यह पता होता, तो वह बहादुर शाह की कब्र रंगून में न बना कर सार्द्वेरिया के दूर उत्तर में कहीं बनाता।

पढ़ने वालों को इस किताब में डूबते सूरज के समय की दर्दभरी आँखें और उगते सूरज के समय के उम्मीदभरे तराने—दोनों ही पढ़ने और सुनने को मिलेंगे।

बहादुर शाह की हार में मुल्क हारा था। पर, बहादुर शाह की क़त्त की खाक माथे पर लगाये आजाद हिन्द फौज की हार में मुल्क की जीत हुई है और शानदार जीत हुई है। फौजें हारी हैं सही, पर न उनका दिल हारा है, न आत्मा।

दिल्लन-सहगल-शाहनवाज के बयान मुजरिम के बयान नहीं हैं, उमंगों भरे दिलों की एक स्वर में गूँज हैं। यह हार है, पर अभिमन्यु और पुरु जैसों की याद दिलाने वाली होने से फाविल कद्र है। उगते हुये सूरज में तेजी भले ही न हो, तेजी की उम्मीद तो रहती ही है। तभी तो वह आँख और मन दोनों की भली लगती है।

जनरल डायर कब से आकर शाह नवाज-सहगल-दिल्लन के साथियों से सीखे कि बहादुर किसे कहते हैं और बहादुर अदालत के सामने कैसे बोलते हैं ? उसने निहत्थों पर गोली चला कर नाम कमाया था। हमारे दिल्लन-सहगल-शाहनवाज विदेशियों की अदालत में शेर के से दिल लिये हुये दहाड़े थे।

इस किताब में पढ़ने वाले पढ़ें और देखें कि किस तरह नाउम्मीदी जय उम्मीद में बदल जाती है, तो गिरती हुई आवाज भी गूँज बन जाती है।

‘जयहिन्द’ के कारनामे और करामात पढ़िये, समझिये, अपनाइये और आजाद होने की उमंगें जी में भर कर इस किताब की असली कीमत चुकाइये।

४० ए, हनुमान रोड ... }  
नई दिल्ली (१)  
जलियानवाला दिवस १९४६ }

—भगवानदीन

## जय हिन्द

“नई दिल्ली, के. वायसराय भवन में गरीबों और दुःखियों के लिये अस्पताल बनाया जायगा।”

यह घोषणा महात्मा गान्धी ने नमक सत्याग्रह के फल-स्वरूप हुये गान्धी-ईरविन-समझौते के बाद कराची कांग्रेस में की।

और—

“नई दिल्ली के वायसराय भवन पर राष्ट्रीय झण्डा फहराना और पुराने ऐतिहासिक लाल किले में विजय महोत्सव मनाना हमारा निश्चित लक्ष्य है।”

यह घोषणा आजाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति और आजाद हिन्द फौज के सेनापति नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने २५ अगस्त १९४४ को रंगून में की थी।

दोनों घोषणाओं के शब्दों में अन्तर है; किन्तु इन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना में कोई अन्तर नहीं है। दोनों का दृष्टिबिन्दु अपने देश की यह आजादी है, जिसके लिये लड़ी जाने वाली लड़ाई में दिहो के लाल किले को अनायास ही विशेष महत्व मिल गया है। इससे भी बड़े बड़े किले देश में अन्य कई स्थानों पर हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व भी कुछ कम नहीं है; किन्तु देश की आज़रूत की आजादी की लड़ाई में उनको इतना महत्व नहीं मिल सका। यह महत्व दिहो के लाल किले को

केवल उन ऐतिहासिक मुकदमों के ही कारण नहीं मिला, जिनकी एक भांकी इस किताब में दी जा रही है; किन्तु उन घटनाओं के भी कारण मिला है, जिनकी चर्चा प्रायः सभी आन्दोलनों के दिनों में होती रही है। समाचारपत्रों में ही नहीं, किन्तु केन्द्रीय असेम्बली तक में जब-तब उनकी गूंज सुनने में आती रहती है। हमारे ये आन्दोलन हमारी आजादी की लम्बी लड़ाई के छोटे-मोटे मोर्चे ही हैं। इन मोर्चों में बनाये गये वे बंदी, जो आम तौर से भयानक समझे जाते हैं, इसी लाल किले में रखे जाते हैं। वहां उन पर की जाने वाली ज्यादतियों की जांच की मांग तो पिछले दिनों में भी की गई थी। अगस्त १९४२ का मोर्चा १९५७ की क्रान्ति की याद दिलाने वाला था। इसलिये इन दिनों में इस लालकिले में राजबन्दियों का रखा जाना और उनको लेकर उसकी विशेष रूप से चर्चा होना स्वाभाविक ही था। कैसा यह संयोग था कि आजाद हिन्द सरकार और आजाद हिन्द फौज के रूप में हुई महान् क्रान्ति के वीर उपासक भी बंदी बना कर इसी लालकिले में लाये गये और उन पर चलाये गये मुकदमे के नाटक की रंगभूमि भी इसी में तय्यार की गई। सरकार ने कुछ भी क्यों न सोचा हो, किन्तु इस रूप में हुई इतिहास की पुनरावृत्ति देश में नये जीवन, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा, नई चेतना और नये जीवन का संचार कर गई। इस प्रकार की गई भारी भूल का सरकार को जय पना चला, तब इस नाटक की रंगभूमि बदल दी गई। लालकिले के स्थान में छावनी में मुकदमे होने लगे और बंदी बनाये गये लोगों को भी वहां तबदील कर दिया

गया। लेकिन, तीर कमान से छूट चुका था। लालकिले के नाम से हुई चर्चा अपना काम कर गई।

दिल्ली के छोटे से सूबे में आज भी उस स्वतन्त्र शासन का कहीं नाम भी नहीं है, जिसका श्रीगणेश 'स्वराज्य' या 'आजादी' के नाम पर अन्य सूबों में कभी का किया जा चुका है। देश की किस्मत का फैसला भले ही दिल्ली में क्यों न होता हो, किन्तु उसका कुछ भी लाभ दिल्ली को नहीं मिलता। यहां स्थानीय स्वशासन के नाम पर चार-पांच म्युनिसिपैलिटियां हैं। उनमें केवल एक का चुनाव होता है और उसका प्रधान तो डिपुटी कमिश्नर ही होता है। बाकी कमेटियों की तरह इसका काम भी सरकार के एक महकमे की भाँति चलता रहता है। चीफ कमिश्नर इस सूबे के ब्रह्मा-चिप्पु-महेश यात्री सभ कुछ हैं। इसीलिये यहाँ की हकूमत इतनी दकियानूसी, प्रतिगामी, अनुदार और असहिष्णु है कि जरा सी भी लोक-जागृति और मतस्वातन्त्र्य उसे सहन नहीं है। जिन चीजों का अन्य प्रान्तों में छापना और बेचना जुर्म नहीं माना जाता, उन्हें भी यहाँ सहन नहीं किया जा सकता। आजाद हिन्द सरकार, आजाद हिन्द फौज और नेताजी के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों में दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित होकर विक रही हैं; किन्तु दिल्ली की हकूमत ने दस-बारह दिनों में ही हमारी 'जयहिन्द' पुस्तक को जल करके उसको छापने वाले प्रेसों से जमाने भी माँग ली। ऐसा किसी भी दूसरे सूबे में नहीं हुआ। फिर भी उस पुस्तक का जो स्वागत हुआ, उसमें हमें बहुत बल और उत्साह मिला। उसकी अठारह-उन्नीस

हजार प्रतियाँ हाथों-हाथ निकल गईं, अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद करने की माँग हुई और बम्बई से विशेष संस्करण के प्रकाशन का आग्रह किया गया। चोर बाजार में १॥) की पुस्तक की कीमत ६) तक पहुँच गई।

दिल्ली की सरकार के इस कठोर और अनुदार रुख को देखते हुए इस पुस्तक में अपनी ओर से प्रायः कुछ भी न लिख कर केवल सरकारी कागजों में दर्ज चीजों को अपने ढंग से दे दिया गया है। मुकदमों की रखी कानूनी कार्यवाही को रोचक कहानी का रूप देकर आम जनता के काम की चीज अवश्य धना दिया गया है। इसीसे कानूनी दृष्टि से इस किताब का इतना महत्व नहीं आँका जाना चाहिये। इतिहास और राजनीति की दृष्टि से इन मुकदमों का जो मौलिक महत्व है, उसमें कमी नहीं आने दी गई है। आजाद हिन्द फौज के मुकदमे में श्री भूलाभाई देसाई ने जो लम्बी पहस की थी, वह लगभग स्वतः में चार सौ पृष्ठों की बड़ी पुस्तक है और हमारे सरीखे गुलाम राष्ट्रों के अपनी आजादी के लिये किये जाने वाले युद्ध के जन्मसिद्ध अधिकार के पक्ष में की गई बहुत ही जोरदार और जबरदस्त पहस है। हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास में यदि आजाद हिन्द फौज का मोर्चा एक सुनहरी अध्याय है, तो श्री देसाई की यह पहस उस अध्याय का एक अमर पृष्ठ है। अंग्रेजी में सिर्फ इसी को लेकर कई पुस्तकें कई स्थानों से प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रान्तीय भाषाओं में भी उसका अच्छा सम्मान हुआ है। हिन्दो में उस पर कुछ भी ध्यान दिया नहीं गया। इस किताब में भी



उसके साथ पूरा न्याय कर सकना संभव न था। उससे इसका आकार प्रकार-बहुत बढ़ जाता और उसकी कीमत भी इतनी बढ़ जाती कि आम जनता के लिये वह सुलभ नहीं रहती। इस बारे में अन्यत्र दी गई एक सूचना की ओर हम अपने सहृदय पाठकों व एजेण्टों का ध्यान आप्रह के साथ आकर्षित करते हैं। उनसे यथेष्ट प्रोत्साहन मिलने पर हम उसको अलग एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं। हमारे पाठक और एजेण्ट उस पर पूरा ध्यान देने की कृपा अवश्य करें।

इस पुस्तक के सम्बन्ध में दो एक बातों की चर्चा करनी आवश्यक है। महात्मा भगवानदीनजी ने भूमिका में बिलकुल ठीक ही लिखा है कि “पढ़ने वालों को इस किताब में डूबते हुये सूरज के समय की दर्दभरी आहें और उगते हुए सूरज के समय के उम्मीदभरे तराने दोनों ही पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। फिर आपने इस किताब का कितना सुन्दर खाका इन शब्दों में खींच दिया है कि “बहादुर शाह की हार में मुल्क हारा था, पर बहादुर शाह की कब्र की खाक माथे पर लगा कर मैदान में उतरने वाली आजाद हिन्द फौज की हार में मुल्क की जीत हुई है। फौजें हारी हैं सही, पर न उनका दिल हारा है और न आत्मा।” सारी किताब में इसी सूत्र की व्याख्या की गई है और यही चित्र कुछ बड़े रूप में वेश किया गया है। हिन्दुस्तान के अन्तिम सम्राट अबुल मुजफ्फर सिराजुद्दीन मुहम्मद बहादुरशाह गाजी, इसमें सन्देह नहीं कि, केवल नाम के बादशाह रह गये थे। अंग्रेजों से सालाना मिलने वाले १८ लाख रुपये पर वे अपना गुजारा

चलाते थे। देश की असली हकूमत तब अंग्रेजों के ही हाथ में थी। लेकिन, बुझते हुए उस दिये की लौ से, दूसरे दिये जरूर जलाये जा सकते थे और गुलामी के घोर अन्धकार में कभी न कभी आजादी का प्रकाश अवश्य फैलाया जा सकता था। इसीलिये १८५७ की क्रान्ति के दुर्भाग्यवश विफल हो जाने के बाद इस दिमटिमाते हुए दिये को एक दम बुझा दिया गया और उस राजवंश का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। इतना ही नहीं,—१८५७ की क्रान्ति को मुस्लिम पड्यन्त्र बताकर भारतीय राष्ट्रीयता के विरोध में रचे गये उस भीषण पड्यन्त्र का सूत्रपात भी उसी समय कर दिया गया था, जिसका दुष्परिणाम पृथक निर्वाचन के रूप में सामने आकर आज पाकिस्तान का भयानक रूप धारण कर चुका है। हिन्दू-मुसलमान में फूट डालकर शासन करने की दुर्नीति तभी अपनाई जा चुकी थी। बादशाह के मुकदमे में की गई सरकारी वकील की बहस इसी जहर से भरी हुई है। आजाद हिन्द फौज के मुकदमे में भी यह खेल खेलने की कोशिश की गई। यह दिखाने का यत्न किया गया कि मुसलमान जनता तथा मुसलमान युद्धवन्दी आजाद हिन्द फौज में स्वेच्छा से भरती न हुए थे और भांसी की रानी रेजीमेण्ट में एक भी मुस्लिम महिला शामिल न हुई थी। लेकिन, यह खेल सफल न हो सका। मच तो यह है कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता की चट्टान पर खड़ी की गई आजाद हिन्द फौज कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों द्वारा रचे गये इसी पड्यन्त्र के विरुद्ध एक सफल और सक्रिय विद्रोह था। उसको देशभक्ति और देशसेवा की अजेय और अदम्य भावना

को अन्त में न केवल सरकारी वकील और जज एडवोकेट को ही, किन्तु सरकार को भी स्वीकार करना पड़ गया। इन दोनों मुकदमों को एक साथ इस किताब में पेश करने का यही मुख्य नैतिक पहलू है। हमारे पाठकों का भी इस पर ध्यान जाये बिना न रहेगा।

बादशाह की आयु तब ८२-८३ वर्षों की थी, जब उन पर मुकद्दमा चलाया गया था। 'बादशाह' रहते हुये भी उनकी हालत लालफिले में कैद रहने वाले 'नजरबन्द' की-सी थी। शायरी लिखवाने में वह मस्त रहते थे। आज भी उनकी पत्नी खीनत महल के हाथ की लिखी हुई उनकी कवितायें मिलती हैं। शासन, फौज या सरकार से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कामों में वह कुछ भी दिलचस्पी न लेते थे। फिर भी उन पर मुकद्दमा चलाया गया। उसका वास्तविक कारण उनका कोई अपराध न था; किन्तु विशुद्ध गहरे राजनीतिक हेतु से ही वह चलाया गया था। शुरू में उनको सजा देने का भी ऐसा कोई विचार न था, किन्तु अन्त में उनको आजीवन कैद की सजा देकर सख्त पहरे में कलकत्ता भेज दिया गया और कहा गया कि कलकत्ता जाने पर ही आगे के स्थान की सूचना दी जायगी। वहां पहुंचते ही उनको बारशिप (लड़ाई के जहाज) पर सवार करके रंगून पहुंचा दिया गया। ८७ वर्ष की आयु में १८६२ में वहां ही उनका देहावसान हो गया। इस स्थिति और इस धुड़ापे में अपने सर्वथा निर्दोष होने का बादशाह ने जो बयान दिया, उसको हमने 'दीनता की पुकार' नाम दिया है। महात्मा भगवानदीनजी ने उसको "इबते

हुये सूरज के समय की दर्दभरी आहें" कहा है। लेकिन, आजाद हिन्द फौज के अफसरों की आयु २७-३० वर्ष के ही आस-पास है। उन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध लड़ने के अभियोग को बहादुरी के साथ स्वीकार किया है। सरकारी पक्ष की दृष्टि में वह 'राजद्रोह' था और अभियुक्तों की दृष्टि में वह थी देशसेवा, जो उत्कृष्ट देशभक्ति की ऊंची एवं पवित्र भावना से प्रेरित हो कर ही की गई थी। इसी लिये उनकी भावना, कल्पना और आकांक्षा को भूमिका में महात्माजी ने 'उगते हुये सूरज के समय के उम्मीदभरे तराने' कहा है। इस दृष्टि से यह किताब केवल दो मुकदमों की एक मांको न हो कर निराशा एवं हताशा लोगों को आशा का वह सन्देश देने वाली है, जिससे प्रेरित हो कर आजाद हिन्द फौज ने बहादुरशाह की कब्र की खाक माथे पर लगा कर इम्काल के मोर्चे की ओर पूर्य किया था। स्वतन्त्र भारतमाता के चरणों में माया नवा कर अपने को कृतकृत्य करना उसका एकमात्र लक्ष्य था। जिन लोगों ने मलाया और बर्मा में संफटोपन्न देशवासियों को निराशा में आशा, अन्धकार से प्रकाश और मृत्यु से जीवन की ओर जाने का राजमार्ग दिखाया था, उनका जीवन-कार्य हमारे लिये भी आशा का जीता-जागता सन्देश है। सरकारी कागजों के आधार पर ही क्यों न हो, इस पुस्तक में भी आजाद हिन्द सरफार, आजाद हिन्द फौज और नेताजी के कार्य का पूरा व्योम आ गया है। 'जयहिन्द' की ध्वनी से हुआ अभाव कुछ अंशों में

तो इससे पूरा हो ही गया है। इसी दृष्टि से इसका सम्पादन और प्रकाशन किया गया है।

‘माहेश्वरी’ बम्बई के सम्पादक श्री निरंजन जी शर्मा तथा ‘प्रभात’ जयपुर के श्री सतीशजी विशालंकार ने इसके सम्पादन में जो सहायता की है और “हिन्दुस्तान” नई दिल्ली के भाई केदारनाथ जी शर्मा से जो प्रेरणा और सहायता मिली है, उसके लिये उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रगट करना आवश्यक है।

मारवाड़ी पब्लिकेशन्स  
४० ए, हनुमान रोड  
नई दिल्ली (१)  
३० अप्रैल १९४६

—सत्यदेव विशालंकार

## एक नज़र में

पढ़िये	५
जयहिन्द	७
एक नज़र में	२६
१८५७ के बाद	
१. अभियोग	३७
२. दीनता की पुकार	२०
३. मुस्लिम पहचान	२५
४. फैसला	४३
१८५५-५६ में	
१. अदालत में	४४
२. अभियुक्त	४५
३. अभियोग	४८ (क)
४. सरकारी वकील का वक्तव्य	४६
५. सरकारी गवाह	६२
६. देशभक्ति बनाम राजभक्ति	८६
७. आजाद हिन्द सरकार और फौज की स्थिति	११०
८. आजादी के लिये युद्ध का अधिकार	१३६
९. देशभक्ति की विजय	१७३

## १८५७ के बाद

: १ :

### अभियोग

१८५७ में हुई राज्यक्रान्ति को कुचलने के लिये जो अनेक उपाय काम में लाये गये थे, उनमें सबसे बड़ा उपाय आजाद-हिन्द के अन्तिम बादशाह मुहम्मद बहादुर शाह पर लाल किले में चलाया गया मुकद्दमा था। इतिहास की छानबीन करने वाले इस सम्बन्ध में जिन नतीजों पर पहुँचे हैं, उनकी चर्चा करने का यह स्थान नहीं है। सरकारी कागजों में दी गई कार्यवाही के अलावा यहाँ और कुछ भी दिया नहीं गया। २७ जनवरी १८५८ को एक सैनिक अदालत के सामने, जिसमें पाँचों जज युरोपियन थे, यह मुकद्दमा चलाया गया था। अदालत के प्रधान का नाम था—लेफ्टिनेण्ट फर्नल दाइल, अन्य सदस्यों के नाम थे—मेजर पामर, मेजर रैडमाण्ड, मेजर साय्यरस और फत्तान रायनी। दुभाषिये का काम श्री जेम्स मुर्फी ने किया था। सरकारी वकील थे—मेजर एफ० जे० हैरियट। दिल्ली के लाल किले के

दिवानखास में अदालत की कार्यवाही की गई थी । बादशाह पर चार अभियोग लगाये गये थे । उनमें कहा गया था कि अभियुक्त ने :—

(१) ब्रिटिश सरकार के पेंशनर होते हुये भी दिल्ली और उसके आस-पास १० मई से १ अक्टूबर १८५७ के बीच अनेक कमीशन-प्राप्त अफसरों और सिपाहियों को हत्या करने और राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये सहायता की और भड़काया था ।

(२) अपने पुत्र मिर्जा मुग़ल को, जो ब्रिटिश सरकार की एक प्रजा था और अन्य प्रजाजनों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने और युद्ध करने के लिये प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया ।

(३) ब्रिटिश सरकार की प्रजा होते हुये और राजभक्ति की कुछ भी पर्या न करते हुये दिल्ली में ११ मई १८५७ को या उसके आसपास राज्य के विरुद्ध बगावत की, अपने को हिन्दुस्तान का राजा और सम्राट घोषित किया, विश्वासघात करके शहर पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया, अपने पुत्र मिर्जा मुग़ल, मुहम्मद वस्ति खां आदि बागियों के साथ मिल कर घोषा दिया, दरा किया, पट्टयन्त्र रचा, बगावत की, विद्रोह किया और राज्य के विरुद्ध युद्ध किया । हिन्दुस्तान में से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये दिल्ली में सेनायें इकट्ठी की और उनको जहाँ-तहाँ लड़ाई पर भेजा ।

(४) १६ मई १८५७ को या उसके आस-पास दिल्ली के राजमहल ( किले ) में ४६ युरोपियनों की, जिनमें अधिकांश



स्त्रियाँ और बच्चे थे, वदमाशी के साथ हत्या करने या कराने में सहायता दी। सिपाहियों को युरोपियन अफसरों और अंग्रेजों की, जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल हैं, हत्या करने के लिये उत्साहित तथा प्रेरित किया। इसके लिये उनको नौकरी व तरफ़ी आदि का लालच दिया। देसी नरेशों के नाम हुक्म जारी किये कि वे अपने इलाके में आने वाले ईसाइयों और अंग्रेजों की हत्या करें।

## दीनता की पुकार

बादशाह ने सफाई में दिये गये बस्तन्य में कहा था कि विद्रोह होने के दिन तक मुझे उसका कुछ भी पता न था। सवेरे चजे के लगभग विद्रोही फौजियों ने आकर मेरा महल घेर लिया। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था कि वे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई गोलियों को अपने मुंह से खोलें। ऐसा करना उनके धर्म के विरुद्ध था। इस पर उन्होंने मेरठ में सत्र युरोपियनों को मार डाला। मैंने महल की खिड़कियों के दरवाजे बन्द कर लिये। किसी तरह फौजियों को वहाँ से हटाया गया। महल की सेना के कमाण्डर मि० फ्रेजर ने मुझ से कहा कि वह उपद्रव को शान्त करने का यत्न करेगा। मि० फ्रेजर ने मुझ से दो गन और दो पालकियाँ माँगीं। वे पालकियों में दो अमेज स्त्रियों को महल में छिपाने के लिये भेजना चाहते थे। लेकिन, पालकियाँ पहुँचने से पहिले ही उन तीनों की हत्या कर दी गई।

थोड़ी ही देर में चारों ओर से महल घेर लिया गया । मुझे कैदी बना कर मुक्त पर पहरा बिठा दिया गया । मार दिये जाने के भय से मैं अपने कमरे के अन्दर चुपचाप चला गया । शाम तक वे तोयखाने से कुछ और अंग्रेज स्त्री-पुरुषों को कैदी बना कर ले आये और उनको मार देने का उन्होंने निश्चय किया । मैंने उस समय उनको मारने से बचा लिया । दो बार और भी मैंने उनकी रक्षा की । लेकिन, तीसरी बार उन्होंने मेरे हजार मना करने पर भी उनको मार ही दिया । मैंने इसके लिये कोई हुक्म न दिया था । मेरे नाम का इसके लिये वुरुपयोग जरूर किया गया । लेकिन, मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरे अंगरक्षकों ने भी इसमें भाग लिया । उन्होंने ऐसा मिर्जा मुगल के कहने पर किया होगा । हत्याकाण्ड के बाद भी मुझे उसका कुछ भी पता नहीं दिया गया । मैंने फौजर और उसके साथियों को मारने का भी कोई हुक्म नहीं दिया । मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इनको या किसी को भी मारने का हुक्म नहीं दिया । मुकुन्दलाल और दूसरे गवाहों ने जो कुछ भी कहा है, वह बिल्कुल झूठ है । हत्याकाण्ड के बाद विद्रोही सैनिक मेरे पास आये और बोले कि हम मिर्जा मुगल, मिर्जा खैर सुलतात और अबुल बकर को अपना अफसर बनाना चाहते हैं । मेरे इनकार करने और चुप रहने पर भी मिर्जा मुगल को सेनापति बना दिया गया । मैं इतना साधारण था कि जिन फागजों पर विद्रोही लोग चाहते, मेरे हस्ताक्षर जबरन करवा लेते और मोहर भी लगवा लेते थे । कुछ खाली लिफाफों पर भी मोहरें लगा ली गई थीं । उनका मननाना उपयोग किया जाता

था। जो भी कोई मनचाहा हुकम जारी कर देता था। उसके लिये मुझसे पूछना तो दूर रहा, मुझे उनका पता तक न दिया जाता था। मेरा सेक्रेटरी भी इसमें दखल न दे सकता था। मेरे सामने मेरे नाम से जो कुछ कहा जाता था, मैं उसका भी विरोध नहीं कर सकता था। मेरे नौकरों पर अंग्रेजों का साथ देने का सन्देह किया जाता था। मेरे हकीम अहसान उल्लाह, महबूबअली खां और बेगम जिन्नत महल को तो मारने की धमकी दी गई थी। हकीम का तो एक दिन मकान भी छूट लिया गया और उसको कैदी बनाकर मारने की धमकी दी गई। मुश्किल से उसको बचाया गया। लेकिन, वह अन्त तक कैद में रहा। मेरे नौकरों तथा साथियों को और बेगम जिन्नत महल के पिता शमशीर उल्लाह को भी कैदी बना लिया। मुझे गद्दी से उतार कर मिर्जा मुगल को बादशाह बनाने की घोषणा कर दी गई थी। बेगम जिन्नत महल को भी कैद में बन्द करने के लिये मुझसे मांगा गया। उनकी अपनी अदालतें थीं और वे आपस में फैसला करके नया काम करते थे। स्वच्छा से वे शहर में लूट-पाट मचाते और धन बटोरते थे। यह सब बिद्रोही सिपाहियों ने किया। मैं उनके हाथों में कैद था। लाचार और मरने से भयभीत होकर ही मैंने जो उन्होंने चाहा, वही किया। मैं इस जीने से तंग आगया था। मेरे अफसर भी जान से हाथ धोने के भय से निराश हो गये थे। मैंने गरीबी का जीवन-वित्ताने का निश्चय करके वेशमूषा बदल कर फकीर या पीर बनने का विचार किया। कुतुब साहिब जाकर मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता था और वहां से मक्का। लेकिन,

फौजियों ने मुझे ऐसा भी न करने दिया । सरकारी तोपखाना और खजाना उन्होंने ही लूटा था । मैंने लूटपाट में कुछ भी हिस्सा न लिया । उन्होंने बेगम जिन्नत महल के मकान को भी लूटने की कोशिश की । मैं उनके साथ होता, तो वे ऐसा क्यों करते ?

अथीसिनियन क़ब्ज़ार मुमत्से मक्का हज़ करने के लिये जाने की छुट्टी लेकर विदेश गया था । मैंने उसको ईरान या वहां के यादशाह के नाम पत्र देकर नहीं भेजा । यह मनपड़न्त फहानी है । महम्मद दरवेश की जो अर्जी पेश की गई है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिये । फौजी तो इतने चांगी हो गये थे कि वे मुमत्से सलाह तक न करते थे और मेरे प्रति कुछ भी सम्मान प्रगट न करते थे । वे दीवानख़ास, दीवानख़ाम और अन्य स्थानों में भी जूते पहने हुये चले आते थे । अपने मालिकों की हत्या करने वाले फौजियों पर मैं क्या भरोसा कर सकता था ? मुझे भी उन्होंने अपना कैदी बना लिया था । जब कि मेरे पास न तो फौज थी, न खजाना था और न बारूदखाना या तोपखाना ही था, तब मैं उनका विरोध कैसे कर सकता था ? मैंने उन्हें कभी भी किसी प्रकार की सहायता नहीं दी । मैंने तो तुरन्त आगरा में लैफ्टिनेण्ट गवर्नर के पास सब बातों की सूचना तक भेज दी थी । फौजियों ने मेरा जलूस भी जवरन निकाला था । जो थोड़े बहुत नौकर मेरे पास थे, उनको मैंने अपनी रक्षा के लिये ही रख छोड़ा था । मौला पाकर द्रिज कर मैं हुमायूँ के मकबरे पर चला गया । जीवन-रक्षा की भीख मांग कर मैं वहां से लौटा और मैंने अपने

को सरकार के हाथों में सौंप दिया । यागी फौजी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे । मैं उनके साथ नहीं गया ।

यह सब मैंने खुदा को हाजिर-नाजिर जान कर सच-सच कह दिया है । इसमें लेशमात्र भी झूठ नहीं है ।

: ३ :

## मुसलिम पड़्यन्त्र

सरकारी वकील ने अपनी लम्बी यहस शुरू करते हुये कहा— मैं उन सब कारणों पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिनसे इतनी भयानक बगावत, जिसे संसार के इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है, हुई और जिसमें एक धर्म के विरुद्ध सारे लोग एक हो गये; हालांकि इस देश के निवासी हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के विरुद्ध उसने कुछ न किया था। मुझसे इसमें भूल होना संभव है कि मैं एक धार्मिक आन्दोलन को राजनीतिक रंग दे रहा हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों ने उन विदेशियों को, जो उनसे रंग-रूप, आचार-विचार तथा रहन-सहन आदि में सर्वथा भिन्न थे, अपने देश से खदेड़ कर अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश में कितने भीषण अत्याचार किये। हमें देखना यह है कि इतनी भीषण बगावत क्यों हुई, क्यों इतने विमत्स हत्याकाण्ड हुए और इन सबका

बीजारोपण कहाँ से हुआ ? इन प्रश्नों का कोई साफ जवाब हमारे पास नहीं है। कारण यह है कि यहाँ की घटनाओं का सम्बन्ध बाहर की बातों के साथ है। फिर भी हमें गर्व है कि हम सचार्द के बहुत पास पहुँच गये हैं। दिल्ली में बहुत पहिले षड्यन्त्र रचे जा रहे थे। इस नाममात्र के बादशाह को धर्मान्ध मुसलमान अपने धर्म का पीर मान कर अब भी पूजते थे। वह फरोहों की आशा और आकांशा का केन्द्र बना हुआ था। वे उसको इतनी प्रतिष्ठा और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे कि न केवल मुसलमान, किन्तु जिनका मुसलमानों के साथ कुछ भी मेल न था, वे भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गये।

घटनाओं का विवरण पेश करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मई १८५७ के अन्त में मेरठ में ८५ फौजियों पर फौजी अदालत में इसलिये मुकद्दमा चलाया गया कि उन्होंने गोलियों को लेने से इनकार कर दिया था। उनको सजा सुनाई गई और ६ मई की सुबह परेड पर उन्हें हथकड़ियाँ पहिना दी गईं। १० मई की शाम को ६॥ बजे बगावत शुरू हुई। कप्तान टिटलर के कहने के अनुसार इन छत्तीस घण्टों में इसके लिये तय्यारी की गई। मेरठ से दिल्ली का रास्ता पाँच घण्टे का है। रविवार की शाम को मेरठ के लोग दिल्ली आये और सोमवार के लिये तय्यारी कर गये। यह निर्णय काफी पहले कर लिया गया था कि यदि चर्बी वाली गोलियों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, तो दिल्ली और मेरठ के फौजी मिलकर बगावत का भयंकर फट्टा देंगे। लेकिन, इस समय दिल्ली या मेरठ में कहीं भी चर्बी वाली गोलियाँ न थीं। अभ्यास



के लिये जो गोलियाँ बनाई जाती थीं, उनको फौजी स्वयं बनाया करते थे। यदि उनमें चर्बी काम में लाई गई होती, तो धार्मिक आधार पर उन्होंने उनको बनाने से इनकार कर दिया होता। फिर, मुसलमानों में जात-पात का कोई भ्रमेला भी तो नहीं है। ये सूअर को छूने पर धर्म के विगड़ने की धात नहीं करते। खानसामों का काम करते हुए ये रोज उन प्लेटों को उठाते, धोते और काम में लाते हैं, जिनमें वह सामान खुले तोर पर परोसा जाता है, जिसके लिये गोली के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। फौजी मुसलमानों के भाईचन्द अफसरों के घर में गाय या सूअर का मांस बनाने या परोखने में कभी कुछ भी आपत्ति नहीं करते। अचरज तो यह है कि इन गोलियों के बारे में कभी किसी ने कुछ पूछताछ या जांच भी तो नहीं की। अदालत में पेश किये गये कैदी के सामने जब मेरठ या दिल्ली में इन्हीं गोलियों से यूरोपियन अफसरों को गोली के घाट उतारा गया, तब किसी भी मुसलमान या हिन्दू ने उनके इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं की। किसी दरखास्त में भी इन गोलियों के बारे में कभी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। जिन तीन फौजों ने सबसे पहले बगावत का भण्डा फहराया, उनमें एक भी चर्बी वाली गोली न थी। यदि वस्तुतः उनकी यही शिकायत थी, तो वे स्तोफा देकर काम छोड़ सकते थे। लेकिन; जो भयानक काम उन्होंने किये, उसके लिये इन गोलियों को लेकर असली या नकली कोई भी कारण न था। उनके लिये तो निश्चय ही कोई ठोस या गम्भीर कारण होना चाहिये था। इस विद्रोह और हत्याकाण्ड के लिये पड़्यन्त्र बहुत समय

से रचा जा रहा था। अंग्रेजी राज को पलटने की कल्पना एव ही क्षण में नहीं की जा सकती थी। इस पट्टयन्त्र के लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर भी उसका प्रारम्भ जिस रूप में हुआ उससे उसका साफ साफ पता चल जाता है। विद्रोह की चिनगारी सुलगाने के लिये तो चर्बी वाली गोलियों की बात अवश्य उठाई गई किन्तु उससे पहिले या बाद में उनकी चर्चा भी नहीं की गई। ८५ फौजियों को सजा देने पर कोई रोष प्रकट नहीं किया गया। उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई। सारी फौजें नियन्त्रण में रह कर राजभक्ति से काम करती रहीं। दिल्ली में पट्टयन्त्र के पक जाने के बाद बगावत का मण्डा फहराया गया।

इस अदालत में पेश कैदी का सम्बन्ध इस पट्टयन्त्र के साथ सबसे पहले तब प्रगट होता है, जब बागी फौजें मेरठ से दिल्ली आकर अपने फौ दिल्ली के किले में उसके सामने पेश करती हैं। इसीसे यह भी पता चलता है कि दोनों में पहिले से ही गाँठ-शाँठ हो चुकी थी। उसके नौकरों ने उसकी आँखों के सामने अपने हाथ यूरोपियनों के खून में रंगे थे। उनमें दो तो नवयुवा महिलायें थीं। सफेद थालों वाले इस बूढ़े आदमी ने अपनी शिक्षा, अपने घराने की राजकीय प्रतिष्ठा और सुख-शान्ति के एकान्त जीवन का कुछ भी विचार न कर इन जंगली कामों में साथ दिया। खुले आम दर्जनों लोगों के सामने दिन दिन की रोशनी में उस किले में ये हत्याएँ की गई थीं, जिस पर कम्पनी की हकूमत में भी तैमूर घराने के अन्तिम बादशाह का ही पूरा अधिकार था। इकीम अहसान उल्लाहखाँ

की गवाही से यह प्रगट है कि कैदी की जानकारी में यह सब किया जा रहा था। उन दिनों के समाचारपत्रों में भी यह सब प्रगट किया गया था। गवाहों ने भी स्वीकार किया है कि मि० फ्रेजर, कप्तान इगलस, मि० हटकिनसन, मि० जैनिंग्स और दो अमेज औरतों की हत्या करने वाले कैदी के अपने नौकर थे। इकीम अहसान उल्लाखान की गवाही से यह भी प्रगट है कि इन हत्याओं की खबर मिलने पर कैदी ने क्या किया ? उसने इनको रोकने के लिये कुछ भी नहीं किया। हत्यारों को कुछ भी सजा नहीं दी गई, किसी को बरखास्त नहीं किया गया और न कोई जांच-पड़ताल या पूछताछ ही की गई। उन सबको नौकरी में रखकर वेतन बराबर दिया जाता रहा।

तोपखाने की घटनाओं का वर्णन करते हुये सरकारी वकील ने बताया कि सवेरे ६ बजे बागी फौजों के दिल्ली पहुँचने के एक ही घण्टा बाद तोपखाने पर कब्जा करने और वहाँ पर मौजूद युरोपियनों को कैद करके किले में लाने की जो कोशिशों की गई, उनसे प्रगट है कि यह सब उद्देजना या आवेश में आकर नहीं किया गया, बल्कि ठंडे दिमाग से पहिले ही सोच-समझ कर किया गया था। अन्यथा, यह सारा काम इतनी खूबी और तेजी के साथ नहीं किया जा सकता था। बादशाह ने उसमें हाथ डालते हुये उसके परिणाम पर विचार किये बिना ही अपना जीवन और अपना सर्वस्व खतरे में नहीं डाल दिया था। तोपखाने पर कब्जा करने के लिये उसने एकाएक ही अपनी फौजे रवाना नहीं कर दी थी। उसको यह भी पता होना चाहिये

था कि दूसरे स्थानों की फौजें क्या करने वाली हैं ? आम जनता में भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थीं। पश्चिम से पानी की एक बाढ़ के आने और बादशाह के सिवाय उसमें बाकी सब कुछ वह जाने की भी अफवाह उड़ाई गई थी। राजपुरोहित हसन असफरी ने इसका यह अर्थ लगाया था कि ईरान के बादशाह की ताकत के सामने सारे युरोपियन खत्म कर दिये जायेंगे और यहां का ताज बादशाह के सिर पर रखा जायगा। सिर्फ इन और ऐसी अफवाहों के पीछे इतना भीषण सैनिक विद्रोह यों ही खड़ा नहीं हो सकता था और हजारों की किस्मत यों ही खटाई में नहीं डाली जा सकती थी। तोपखाने पर तुरन्त किये गये आक्रमण से यह साफ है कि यह काम अकेले फौजियों का ही न था। बादशाह की अपनी फौज ने यह सब जिस ढंग से किया था, उससे प्रगट है कि उसमें किसका हाथ था ? बिना किसी सूचना, आदेश और निश्चित योजना के बादशाह की फौजें यह सब नहीं कर सकती थीं। भले ही राजा को ११ मई को होने वाली घटनाओं का पहिले से पता न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महल के प्रभावशाली लोगों को इस सबकी जानकारी जरूर थी। अंग्रेजों की हत्या की कल्पनामात्र से राजकुमार जवान वख्त को अत्यधिक प्रसन्न होने का आरंभ तब ही क्या था ? विद्रोह का सम्बन्ध केवल सिपाहियों ही के साथ न था और न उसका श्रीगणेश ही केवल उनसे हुआ था। उसका सम्बन्ध सारे महल और सारे शहर के साथ था। बादशाह भी विद्रोह की इस लहर में धूँस गया। उसको आशा तो यह थी

कि वह हिन्दुस्तान की गद्दी का एक बार फिर मौलिक बना दिया जायगा; किन्तु उसको असहाय बना कर दूरी-भूटी किशती के एक टुकड़े की तरह एक किनारे पर छोड़ दिया गया।

तोपखाने के हाथ से निकलने के बाद युरोपियनों के लिये पहला काम अपनी जान बचाना हो गया। इसी दृष्टि से दिल्ली को चौबीस घण्टों में ही खाली कर दिया गया था। बादशाह उसके बाद इस सारे नाटक का सूत्रधार बन गया। सभ्यता की विरोधी जंगली ताकतें इस नाटक को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखने लगीं। ११ मई की दुपहर को बादशाह दीवानखाना में आकर एक घुरसी पर बैठा। फौजी और अन्य अफसर उसके सामने उपस्थित हुये और उसने एक एक करके उन सबके सिर पर हाथ रखा। कैदी के वकील गुलाम अब्बास का कहना है कि यह समरोह सेना की राजभक्ति को स्वीकार कर उनको उनकी नीकरी का भरोसा दिलाने के लिये किया गया था। उसी दिन शहर में बादशाह को सत्ता कायम होने की घोषणा की गई थी और २१ तोपों की सलामी भी दी गई थी।

लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के एजेण्ट और स्थानापन्न कमिशनर मि० साण्डरस ने बताया है कि कैदी के पड़दादा शाह आलम ने मराहटों की कैद में रहते हुये १८०३ में अंग्रेजों द्वारा उनके परास्त किये जाने पर उनकी शरण में आने की दरखास्त दी थी। उसे स्वीकार कर लिया गया था। तब से दिल्ली के नाममात्र के ये बादशाह अंग्रेजों के पेंशनयाप्त हैं। तब से इस परिवार के साथ कोई भी जुगई न करके सदा भलाई ही की गई। शाह

आलम को गद्दी से उतार कर उसकी आंखें भी निकाल ली गई थीं। उसके साथ अत्यन्त अपमानास्पद व्यवहार किया जाता और उसको कठोर नजरबन्दी में रखा जाता था। लार्ड लेक ने इन मुसीबतों से उसका उद्धार किया। उसको प्रतिष्ठा और पेंशन दी गई। उसको उत्तराधिकारियों के साथ भी वैसे ही व्यवहार किया गया। लेकिन, उन्होंने आंस्तीन के सांप की तरह उन्हींको डस लिया, जिन पर वे आश्रित थे।

सूबेदार मुहम्मद बख्त खां के नाम जारी किये गये बादशाह के हुक्म को, जो उसके अपने हाथ का लिखा हुआ बताया गया था, पेश करते हुये सरकारी वकील ने बचाव में दिये गये बयान की समीक्षा की। बादशाह के अपने को निर्दोष बताने को निराधार ठहराते हुये उसने कहा कि उसके बयान का गवाहियों से समर्थन नहीं होता। उन दिनों के समाचार-पत्रों से यह साफ है कि मिर्जा मुगल को प्रधान सेनापति बना कर इस ऊँचे पद पर बिठाया गया था। मौखिक गवाहियों के अलावा पत्र-व्यवहार के रूप में प्राप्त लिखी गवाहियों से भी यह सिद्ध है कि दिल्ली में अपने पिता के बाद विद्रोहियों का दूसरा मुख्य नेता उसका पुत्र मिर्जा मुगल ही था। नजफगढ़ के पुलिस अफसर मोलवी जफर-अली की दरखवास्त पर कैदी ने अपने हाथों से हुक्म लिख कर अपने पुत्र मिर्जा मुगल को वहां सेनायें भेजने का आदेश दिया है। खुर्जापुर के नवाब के पुत्र अमीर अली खां के १२ जुलाई के पत्र पर भी बादशाह ने अपने हाथों से पेन्सिल से लिख कर हुक्म जारी किया है।

सब मुसीबतों और चिन्ताओं से मुक्त करके बादशाह को लाखों पौण्ड की पेन्शन दी जा रही थी। इस नाते से, भक्ति का प्रदर्शन और कर्तव्य का पालन न करते हुये इस यागी ने अपनी भलाई करने वालों की सरकार को चलटने और नष्ट करने का प्रयत्न किया। इस लड़खड़ाते हुये यूदे ने अपने जर्जर हाथों से मूर्खतापूर्ण विद्रोह और हत्याओं के करने वालों को प्रोत्साहन दिया। अपने को बादशाह घोषित करने के लिये शहर में ११ मई की दुपहर को ३ बजे डोंडी पिटवाई। आधी रात में २१ तोपें दागी गईं। मिर्जा मुगल को प्रधान सेनापति बनाकर शहर में उसका जलूस निकाला गया। १ जुलाई को सूबेदार मुहम्मद बख्त खां को गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति बना दिया गया। इस पर दोनों में ईर्ष्या भी पैदा हुई। लेकिन, जल्दी ही सुलह हो गई। दोनों ने बादशाह के साथ मिल कर फौजों का नियन्त्रण करना शुरू किया। १२ जुलाई को मुहम्मद बख्त खां ने शहर में एक हुक्म जारी करके अंग्रेजों से सम्बन्ध रखने या उनको रसद पहुंचाने आदि के बारे में सख्त चेतावनी दी और विद्रोह में साथ देने वालों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर देने का भरोसा दिलाया। ६ सितम्बर १८५७ को बादशाह ने शहर के कोतवाल के पास एक हुक्म भेज कर उसको यह आदेश दिया कि शहर में डोंडी पिटवा कर यह मुनादी करा दी जाय कि यह धर्म-युद्ध है। सब लोगों के लिये, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, चाहे वे शहर के हों या गाँवों के, चाहे वे हमारे से नापज होकर दुश्मन के साथ ही क्यों न मिल गये हों, चाहे

जैसे अंग्रेज सेना में ही क्यों न हों, चाहे वे पूर्विये, सिख, पहाड़ी या नेपाली ही क्यों न हों, यह आवश्यक है कि वे अपने धर्म के प्रति सच्चे रहें और अंग्रेजों तथा उनके नौकरों को मार-भगायें। यह भी सुना दी जाय कि जो आज अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उन्हें हरने का कोई कारण नहीं है। शत्रु का साथ छोड़ने के बाद उनको पूरा संरक्षण दिया जायगा। यह भी ऐलान कर दिया जाय कि दुश्मनों पर हमला करके जो भी सम्पत्ति जो कोई भी छूटेगी वह उसी को दे दी जायगी और उसके अलावा भी उसको बहुत-सा इनाम दिया जायगा। इनके बाद और सुवृत्त पेश करने की जरूरत नहीं है।

किले का महल में ४६ युरोपियनों की हत्या के बारे में, जिनमें अनेक सिक्खों और पृथ्वी भी, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। सब बातें अदालत के सामने आ चुकी हैं। वे इसली भयानक हैं कि उनको सहज में भुलाया नहीं जा सकता। केवल यह दिखाना पानी है कि इस खूंखार हत्याकाण्ड में इस कैदी का कितना गहरा हाथ है और बंदमोर्शी से किये गये इस हत्याकाण्ड में वह किस प्रकार सहायक हुआ है। उनकी गिरफ्तारी, उनको कैद में रखने के स्थान, वहां दी गई भीषण यातनायें, शुरू से ही उनके साथ किया गया अतिशय कठोर व्यवहार और उनके सिर पर लटका हुआ, उनका दुर्भाग्यपूर्ण अन्त, — यह सब कितना भयानक था! इक्कीम अहसान, उल्ला खां ने इन बातों पर काफी प्रकाश डाला है। उसने बताया है कि बादशाह ने उनको कैद में रखने के लिये रसोईघर (बावर्चीखाने) का खूब निवेष्ट



किया था। उसमें स्त्री-पुरुष और बच्चे सब एक साथ-बन्द-कर दिये गये थे। मैंने उस स्थान को स्वयं देखा है। वह स्थान ४० फीट लम्बा, १२ फीट चौड़ा और केवल १० फीट ऊँचा है। वह पुराना, गन्दा और पुता हुआ भी नहीं है। न उसमें फर्श है, न खिड़की है और न हवा तथा रोशनी जाने का दूसरा ही कोई अवन्ध है। केवल एक दरवाजा लकड़ी का है। भीमती आल्डवेल ने बताया है कि हम सिपाहियों के दर से उस दरवाजे को भी बन्द करने को मजबूर होते थे। इससे हम हवा और रोशनी से सर्वथा वंचित हो जाते थे। हमें बन्दूक और फिरच का दर बचाकर मुसलमान या गुलाम होने को धमकाया जाता था। बादशाह के अङ्गरक्षक तो यहां तक कहा करते थे कि हमारी बोटी बोटी काट कर कुचों और चीलों को खिला दी जायगी। भोजन भी बहुत खराब दिया जाता था। केवल दो मार बादशाह की ओर से कुछ अच्छा भोजन भेजा गया था। यह है वह बदला, जो इस घागी ने उस पर और उसके परिवार पर अंग्रेजों द्वारा खर्च किये गये लाखों रुपयों और राजमहल में रहने की सुविधा का दिया। गवाहों के अलावा इसके अनेक दाय के लिखे हुए ऐसे हुक्म भी हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि बादशाह ने कैद का यह स्थान स्वयं तय किया, उसके अपने सरासरी आदमी वहां पहरों पर रहने थे, वही उनको रही खाना देता था और फिर उनसे मुसलमान बनने को कहा जाता था। उसने उनको पचाने की कोशिश तो क्या, इच्छा तक नहीं की। उसने उनके प्रति साधारण दया या सहानुभूति तक का व्यवहार नहीं

किया। उनको यातनायें देने वालों को कभी टोका या रोका नहीं गया। उनको भोजन या पानी देने वाले को उलटी सजा दी जाती थी। गुलाब चपरसी ने अपने वयान में बताया है कि बादशाह या उसके लड़के मिर्जा मुगल के हुक्म के बिना यह हत्याकाण्ड हो नहीं सकता था और हत्याकाण्ड के समय उसके शिकार युरोपियनों को बादशाह के अंगरक्षकों ने चारों ओर से घेरा हुआ था। एक साथ तलवार उठाई जाती और तब तक चलती रहती, जब तक कि कैदी की जान न ले ली जाती थी। पत्रकार खुशीलाल का भी यही कहना है कि यह हत्याकाण्ड बादशाह के हुक्म से ही किया गया था। अपने मकान के छज्जे पर खड़ा होकर मिर्जा मुगल वह सब देख रहा था। बादशाह के सेक्रेटरी मुकुन्दलाल की गवाही से भी इस सब का समर्थन होता है। उसने बताया है कि मिर्जा मुगल के साथ बागी सिपाही इसके लिये हुक्म मांगने आये। मिर्जा मुगल और बसन्त अलीखां भीतर गये और बीस मिनट बाद भीतर से निकलने पर बसन्त अलीखां ने बादशाह के हुक्म के मिलजाने का झूठे से ऐलान किया। इस पर बादशाह के अंगरक्षक उनको बाहर लाये और फौजियों ने उनकी हत्या की। १६ मई की कोर्ट डायरी में भी यह दर्ज है कि दीवानखास में बादशाह का दरबार लगा। ४६ युरोपियन कैदी थे। फौजी उनको मारना चाहते थे। बादशाह ने उनको उनके सिपुर्द यह कहते हुए कर दिया कि फौजी जैसा चाहें, वैसे बर्ताव उनके साथ करें। इसके बाद वे तलवार के घाट उतार दिये गये। दरबार में हाजरी रुकधी

थी । राजाओं, नवाबों, अफसरों आदि ने बादशाह के प्रति सम्मान प्रकट किया ।

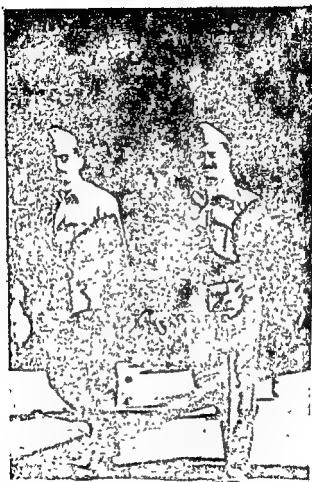
कच्छ भोज के राजा रावभाजा, जैसलमेर के राजा रणजीतसिंह और जम्मू के राजा गुलाबसिंह को बादशाह की ओर से भेजे गये पत्रों को पेश करके सरकारी वकील ने बताया कि उनको युरोपियनों की हत्या करने के लिये किस प्रकार प्रेरित किया गया था । अभियोगों के सम्यन्ध में अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि अब यह अदालत के हाथ में है कि वह कैदी को राज्य से च्युत बादशाह की प्रतिष्ठा भोगने दे अथवा इतिहास के सबसे बड़े पापियों में उसकी गणना होने दे । अदालत को निर्णय करना है कि तैमूर राजघराने का यह अन्तिम बादशाह बापदादाओं के इस विशाल राजमहल से निकाला जायगा कि नहीं ? आपका निर्णय वर्तमान और भविष्य के लिये भी यह बता देगा कि बादशाह के साथ भी पाप करने के बाद किस प्रकार पापी का सा व्यवहार किया जाता है और राजघराने की पुरानी शान एक दिन में सदा के लिये कैसे धूल में मिल जाती है ।

विद्रोह के सामान्य कारणों और पहिले से रचे गये षडयन्त्र पर प्रकाश डालते-हुये सरकारी वकील ने कहा कि फलकत्ता से पेशावर तक फैली हुई छावनियों में गोली पर लगाई गई धर्बी को लेकर इतना भयानक और भीषण विद्रोह हुआ कि एक नहीं फैल सकता था । आपस के गुप्त-सम्मोते और पहिले की तैयारी के बिना यह सम्भव ही न था । इसी का नाम है

पड़्यन्त्र । उसके लिये गोलियों के मामले से चिगारी का काम लिया गया । भले ही हम यह नहीं पता लगा सके कि इस पड़्यन्त्र के पीछे किनका हाथ था, किन्तु यह स्पष्ट है कि मुसलमानों में असन्तोष घर करता जा रहा था और इससे उन लोगों ने काम उठाया, जो ऐसे मौके की खोज में थे । अवध के ब्रिटिश शासन में मिला लिये जाने से भी मुसलमानों में असन्तोष बढ़ा होगा । जाटमल ने गवाही में कहा है कि इस विद्रोह से मुसलमानों में तो जरूर आनन्द की लहर फैल गई, किन्तु हिन्दुओं को इससे दुःख हुआ । इसको मुस्लिम पड़्यन्त्र ही कहा जाना चाहिये, भले ही हिन्दू और मुसलमान कौजी सब इसमें शामिल थे । विद्रोह से एक-दो मास पहिले सेनाओं में निजी पत्रों का आना-जाना बहुत बढ़ गया था । इससे तथा उस समय की अन्य परिस्थितियों से यह प्रगट है कि भीतर ही भीतर कुछ गोलमाल बहुत तेजी से चल रहा था । इसी समय इस विस्फोट के होने के अनेक कारण थे, जिनमें अवध का ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाना, युरोपियन सभ्यता का फैलना, लोगों को अज्ञान के अंधकार में रखकर धर्मजीवी लोगों द्वारा खेड़ी की गई स्वार्थ की दीवारों का तेजी से गिरना और उन धर्मों का नष्ट होना, जो नैसर्गिक विज्ञान की साधारण-सी रोरानी भी सहन नहीं कर सकते थे । विधवाओं के पुनर्विवाह को भी धर्मान्व लोगों की भावनायें उमाड़ने में काम में लाया गया । जात और छूत-व्रात के कारण पहले हिंदुओं में परस्पर और हिंदुओं तथा मुसलमानों में भी आंगरेजों में कितना ही भेदभाव क्यों न रहा हो;

लेकिन, अंग्रेज सेनाओं में सत्र के एक साथ रहते से यह भेदभाव मिट गया। सेना ऐसा हथियार है कि उसको पैना करने वाले के विपरीत भी उसके प्रयोग होने में देर नहीं लगती। अंग्रेजों के साथ ऐसा ही हुआ। वे हिंदू भी, विगड़ गये, जो हिन्दुओं के मुसलमान बनाये जाने पर भी कभी आवेश में न आते थे। इस पद्धति की कितने समय से तयारी की जा रही थी,—यह इसी से प्रगट है कि सीरी कम्बार को दो वर्ष पहले ईरान और कुस्तुनतुनिया पत्र देकर यहां से सहायता प्राप्त करने के लिये भेजा गया था और उसको इस समय तक लौट आने के लिये कहा गया था। मुसलमानों में अनेक अफवाहों में एक यह भी फैलाई गई थी कि प्लासी की १७५७ की लड़ाई के ठीक सौ बरस बाद अंग्रेजी राज यहां से मिट जायगा। धर्मांध मुसलमानों को भड़काया गया कि इनका पुराना वैभवं फिर से कायम हो जायगा। बहुत-सी अफवाहें फैला कर यादशाह को भी यह विश्वास दिला दिया गया था कि ईरान का सम्राट फिर से हिंदुस्तान का ताज उसके सिर पर रख देगा। उसके लिये हर रोज बहुत सी दान-दक्षिणा दी जाकर विरोप प्रचार का पूजापाठ किया जाता था। मुहर्रम पर यह सत्र विरोप रूप से किया गया था और अंग्रेजों के लिये बददुआयें मांगी गई थी। फौजों में भेजी गई चपातियों की चर्चा करते हुये सरकारी वकील ने कहा कि इनका इद्देश्य हिन्दुओं और मुसलमानों के भाईचारे को सुट्टा बना कर उनको एक धर्म और एक खान-पान के बन्धन में बांधना था। आटे में हड्डियों का घूरा मिलाने

की भी झूठी अफवाह उड़ाई गई थी। लेकिन, इस सबका भेद खुलने पर हिन्दू फौजियों ने मुसलमानों को कोसना शुरू कर दिया। हिन्दुओं ने सामूहिक रूप से न तो इसमें भाग लिया और न ब्राह्मणों या पुरोहितों ने वैसी अफवाहें ही फैलाई थीं। न उनका कोई राजा ही था, जिसको वे दिल्ली के तख्त पर फिर से बिठाते और न वे अपने धर्म का तलवार के जोर पर प्रचार ही करना चाहते थे। इसलिए इसे मुस्लिम पढ़यंत्र ही कहना चाहिये। उन दिनों के समाचारपत्रों में भी तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं। ईरान, फ्रांस, टर्की और रूस के हिन्दुस्तान पर हमला करने के किस्से-कहानियां समाचार-पत्रों में जनवरी १८५७ से ही प्रकाशित होती शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती होने की भी बातें उड़ाई गई थीं। रूस के चार लाख सैनिकों और बहुत से गोला-बारूद से ईरान की मदद करने को भी समाचार फैलाये गये थे। राजमहल और शहर में भी ये खबरें बहुत पाव से पड़ी जाती थी। इसी से सभी समाचार-पत्री ने काबुल में अपने सम्वाददाता रखे हुये थे। गिराहियों में भी इसकी खुली चर्चा होती थी और कहा जाता था कि उत्तर से एक लाख रूसी सैनिक शीघ्र ही हिन्दुस्तान पर हमला करने वाले हैं, जिससे कम्पनी की हकूमत नष्ट हो जायेगी। मुल्ला-भौलवियों की सपनों में घड़ी गई कहानियों, दरबार में रचे गये पढ़यंत्रों और समाचार-पत्रों में उड़ाई गई खबरों का एक साथ होना साधारण बात नहीं है। मुसलमानों में स्वामिमान की भावना का पैदा करना, उनकी धर्मान्धता को प्रोत्साहन देना, धर्म-युद्ध के लिये उनको उमाड़ना



अज्ञान ही ओर जाने हुये—बीर. आन. स्ट. क. फर्गुसन  
ज'दरसात ओर मिलिटी मेकटरी मेका प्रेमन स सदगल ।

और अंग्रेजों के लिये उनमें घृणा पैदा करना भी अकारण ही न था। यह भी पत्रोंमें प्रकाशित किया गया था कि पांच सौ ईरानी सिपाही दिल्ली में छिपे हुये हैं और तीन सौ ने हिन्दुस्तान पर हमला कर दिया है। सादिक खां नाम के एक आदमी ने जामा मसजिद पर ईरान के बादशाह का एक ऐलान भी चिपकाया था। इस पर एक ओर तलवार और दूसरी ओर दाल बनाई गई थी। विद्रोह से पन्द्रह दिन पहिले मजिस्ट्रेट के पास एक गुमनाम दरखास्त भेजी गई थी, जिसमें बताया गया था कि फारसी गेट जल्दी ही अंग्रेजों के हाथों से छिन लिया जायगा। सैनिक दृष्टि से इसका उस समय बहुत अधिक महत्व था। लोगों के विचारों का इससे पता चलता है। कैदी के प्रति लोगों में जो धार्मिक और राजनीतिक श्रद्धा थी, उसीसे उसने लाभ उठाया और इस विद्रोह के लिये रचे गये पड़यन्त्र के लिये वह स्फूर्ति और प्रेरणा बन गया।

इस विद्रोह के लिये मुसलमानों में विशेष उत्कण्ठा थी। मिर्जा तक्री बेग ने अंग्रेजों की नौकरी में होते हुए भी पेशावर में ब्रिटिश राज के शीघ्र नष्ट होने की खबरें उड़ाईं। दिल्ली के तोपखाने के करीम बख्श ने भी अंग्रेजों की नौकरी में रहते हुए शहर-उधर फौजों में फारसी में पत्र भेज कर गोलियों में चर्बी लगाने की बात फैलाई। तोपखाने पर हमला होने पर यह दागी फौजों से मिला हुआ था। ऐसी और घटनायें देने की जरूरत नहीं है। यह प्रगट है कि १८५७ की भीषण दुर्घटनाओं के पीछे मुसलमानों की गुप्त हुरकतें और पड़यन्त्र था। राजद्रोह का लग्ना जाल बहुत पहले से फैलाया जा रहा था। कैदी ने अपने



प्रति मुसलमानों की अन्ध श्रद्धा से लाभ उठा कर अपने दो इस पड़यन्त्र का मुखिया बना लिया था। हिन्दुओं को चर्ची की। जिस बात पर बहकाया गया था, अम्बाला की छावनी में मुसलमान सिपाही त उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसी किसी बात पर मुसलमानों ने हिन्दुओं का कमी भी साथ न दिया होता। हिन्दुओं को बाद में इसके लिए पछतावा भी हुआ और उन्होंने माफी माँग कर अंग्रेजों का साथ भी देना चाहा। आदि से अन्त तक यह सारा खेल मुसलमानों का रचा हुआ था। एक मुसलमान मोलवी ने सपने देखने और चमत्कार दिखाने का ढोंग रचा, बादशाह और उसके साथी भी। मुसलमान ही थे, ईरान और तुर्की के मुसलमान बादशाहों के पास मुसलमान राजदूत को ही भेजा गया था, अंग्रेजी राज के नष्ट होने की भविष्यवाणियाँ भी मुसलमानों ने गढ़ी थी और उसके स्थान पर मुसलमानों का राज ही कायम किया जाने वाला था। खूनी हत्याकाण्ड करने वाले भी सब मुसलमान ही थे। मुसलमानों के लिए ही इसे धर्मयुद्ध का नाम दिया गया था। मुसलमानी समचारपत्रों ने आग चारों ओर फैलाई और मुसलमान सिपाहियों ने ही पहिली चिंगारी सुलगाई। हिन्दुओं का हाथ इसमें कहीं भी दीख नहीं सकता। उन्होंने तो इसको दबाने का ही काम किया।

इस प्रकार इसको “मुसलिम पड़यन्त्र” बताते हुए अन्त में सरकारी वकील ने लोगों को जबरन ईसाई बनाये जाने की अपवाह का उल्लेख किया और इस बारे में सुनवाई की गई आरा-  
 ढाओं को निराधार बताया।

: ४ :

## ‘फैसला’

६ मार्च १९५८ को अदालत ने यह फैसला दिया कि अदालत के सामने जो गवाहियाँ-पेश की गई हैं, उनको देखते हुए उसकी यह सम्मति है कि दिल्ली के भूतपूर्व बादशाह कैदी मुहम्मद यहादुर शाह पर जो अभियोग लगाए गए हैं; उन सब में वह दोषी सिद्ध हो गया है।”

इस फैसले के अनुसार माण्डले में अंग्रेजों की कैद में नजरबन्द रह कर अपनी शेष आयु हिन्दुस्तान के अन्तिम बादशाह ने पूरी की। वहाँ ही उसकी समाधि बनाई गई। उसी पर उपस्थित होकर देश के महान् क्रांतिकारी नेता श्रीसुभाषचन्द्र बोस ने उस महान् उद्योग का सूत्रपात किया था, जिसका अन्तिम पटाक्षेप फिर इसी लाल किले में हुआ और उस गौरव-पूर्ण एवं वीरतापूर्ण कहानी के अन्तिम पटाक्षेप की एक जाँकी आगे पृष्ठों में दी जा रही है।

प्रति मुसलमानों की अन्ध श्रद्धा से लाभ उठा कर अपने दो इस पंडयन्त्र का मुखिया बना लिया था। हिन्दुओं को चर्ची की जिस बात पर बहकाया गया था, अम्बाला की छावनी में मुसलमान सिपाही तब उसका मजरा उड़ाते थे। ऐसी किसी बात पर मुसलमानों ने हिन्दुओं का कमी भी साथ न दिया होता। हिन्दुओं को बाद में इसके लिए पछतावा भी हुआ और उन्होंने माफी माँग कर अंग्रेजों का साथ भी देना चाहा। आदि से अन्त तक यह सारा खेल मुसलमानों का रचा हुआ था। एक मुसलमान मौलवी ने सपने देखने और चमत्कार दिखाने का ढोंग रचा, बादशाह और उसके साथी भी मुसलमान ही थे, ईरान और तुर्की के बादशाहों के पास मुसलमान राजदूत को ही भेजा जाता था मुकद्दमा भी लम्बे होने की मुद्दियाँ किहीं अधिक हैं। यह मुकद्दमा लाल किले में १५ नवम्बर को शुरू हुआ। इस सैनिक अदालत में सात जज थे, जिनमें चार अंग्रेज और तीन हिन्दुस्तानी थे।

सरकारी वकील थे भारत सरकार के एडवोकेट जनरल सर नोरोथान, पी० इंजिनियर और लैफ्टिनेंट कर्नल पी० वल्श। सफाई के वकीलों में हिन्दुस्तान के पहिली चोटी के सुप्रसिद्ध वकीलों और बैरिस्टरों के साथ दिल्ली के भी अनेक वकील थे। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री भूलाभाई जे० देसाई, डा० बैलाशनाथ काटजू, रा० व० वट्टीदास, श्री आसिफ अली, कुंवर सर दिलीपसिंह, वक्शी सर टेकचन्द और श्री वी० एन० सेन के नाम उल्लेखनीय हैं।

: २ :

## अभियुक्त

आजाद हिन्द फौज के तीन अफसरों को बतौर अभियुक्त के इस अदालत में पेश किया गया था। उनके नाम व संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार हैं :—

**कप्तान साह नवाज खाँ**

आपका जन्म २४ जनवरी १९१४ को रावलपिण्डी में हुआ। देहरादून के सैनिक विद्यालय में आपकी शिक्षा हुई। रावल नारफौक रेजीमेण्ट की पहली बटेलियन में भरती हुये। बारह मास बाद पंजाब रेजीमेंट में इलेम भेज दिये गये। फरवरी १९३६ में आपको स्थायी रूपसे कमिशन अफसर बनाया गया। अगस्त १९३६ में उसकी एक पलटन का कमाण्डर बना दिया गया। १३ जनवरी १९४२ को 'कप्तान' बना कर आपको स्वदेश के बाहर मोर्चे पर भेजा गया। १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुर में आपको युद्धबन्दी बना लिया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना और संगठन में आपने प्रारम्भ से ही विशेष हिस्सा लिया और

युद्धबंदी हिन्दुस्तानी सैनिकों तथा अफसरों को उसमें शामिल होने के लिये विशेष रूप से प्रेरित किया। पहली सितम्बर १९४२ को आप उसमें सेकण्ड लैफ्टिनेण्ट बनाये गये। ६ सितम्बर को मेजर, १५ अक्टूबर को लैफ्टिनेण्ट कर्नल और २६ नवम्बर को कैप्टेन ट्रेनिंग स्कूल के कमान-अफसर बनाये गये और सदर मुकाम में भेज दिये गये। १० अप्रैल १९४३ को आपको डाइरेक्टोरेट आफ मिलिटरी च्युरो में भेज दिया गया। १८ अप्रैल को आप जनरल स्टाफ के चीफ नियुक्त किये गये। जुलाई १९४५ में नेताजी सुभाष बाबू उनके सिंगापुर आने पर नं० १ गुरिल्ला रेजीमेण्ट का संगठन के नाम पर किया गया। आप उसके कमाण्डर नियुक्त किये गये। १९४५ के शुरू में आप नं० २ डिविजन के डिविजनल कमाण्डर नियुक्त किये गये। अक्टूबर १९४३ में आप फौज के साथ घर्मा आये। २१ फरवरी १९४५ को आपने युद्ध के मोर्चे पर प्रस्थान किया। १६ मई १९४५ को आप पेगू में गिरफ्तार किये गये। आजाद हिन्द सरकार के मन्त्रिमण्डल में भी आप सम्मिलित थे। मुफ्तमे से रिहाई पाने के बाद से आप नेताजी के सामने की गई प्रतिष्ठा को पूरा करने में लगे हुये हैं।

कप्तान प्रेमकुमार सहगल

२५ जनवरी १९१७ को होशियारपुर में आपका जन्म हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय के टेक्नीकल कालेज की पढ़ाई के बाद आप देहरादून के सैनिक विद्यालय में भरती हुये। १९३६ की पहली फरवरी को आपको कमीशन अफसर बनाया गया। २४ फरवरी १९४० को बल्लू रेजीमेण्ट में भरती हुये।

२७ अक्टूबर को सिंगापुर के लिये रवाना होकर ११ नवम्बर १९३० को वहाँ पहुँचे। १४ फरवरी १९४२ को जापानियों द्वारा युद्धबन्दी बनाये गये। आजाद हिन्द फौज के संगठन में आपका भी मुख्य हाथ रहा। १ सितम्बर १९४२ को आप सेकण्ड लेफ्टिनेण्ट, ६ सितम्बर को कप्तान और १५ अक्टूबर को मेजर बनाये गये। २६ फरवरी १९४३ को आपको डायरेक्टोरेट आफ मिलिटरी व्यूरो में भेजा गया। १७ अप्रैल को आप मिलिटरी सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। फरवरी १९४४ में आप सिंगापुर से रंगून आये। नं० ३ गुरिखा रेजीमेण्ट के तब आप कमाण्डर थे। मनीपुर-अराकान की लड़ाइयों में आपने विशेष हिस्सा लिया और स्वयं सेनओं का नेतृत्व किया। २६ अप्रैल १९४५ को आप गिरफ्तार किये गये। रिहाई के बाद से आपने आजाद हिन्द फौज की डिफेन्स कमिटी का काम संभाला हुआ है। राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में आप संलग्न हैं

### लैफ्टिनेण्ट गुरुवचसिंह दिलन

आप ४ अप्रैल १९१५ को लाहौर जिले के अलगोऊ स्थान में पैदा हुये। पंजाब विश्वविद्यालय के टैकनीकल कालेज, नौगांव के कृष्णा कालेज और देहरादून के सैनिक विद्यालय में आपकी शिक्षा हुई। ३ अप्रैल १९४० को आपको कमिशन अफसर बनाया गया। ३० अप्रैल को आप पंजाब रेजीमेण्ट में भरती हुये। १५ फरवरी १९४२ को युद्धबन्दी बना लिये गये। आजाद हिन्द फौज के संगठन में आपने प्रमुख भाग लिया। १ सितम्बर १९४२ को आप सेकण्ड लैफ्टिनेण्ट, ६ सितम्बर को कप्तान और

१० अक्टूबर को मेजर बनाए गए ।। रसेद और यातायात विभाग का आपको अफसर इनचार्ज बनाया गया ।। सितम्बर विभाग का आपको अफसर इनचार्ज बनाया गया । सितम्बर १९४४ को आप बर्मा आये । चौथी गुरिल्ला रेजिमेण्ट उर्फ नेहरू ब्रिगेड के आप कमाण्डर नियुक्त किए गए । इम्फाल के मोर्चे पर आपने लड़ाई में सक्रिय भाग लिया । ५ जुलाई १९४५ को आप गिरेफ्तार किए गए । रिहाई के बाद आपने उत्तर भारत का दौरा किया । देश की आजादी के लिए किए गए संकल्प की पूर्ति में आपने अपने को लगा दिया है । . . . . .

: ३ :

## अभियोग

तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य अभियोग फौजी कानून की धारा ४१ के अनुसार यादशाह के विरुद्ध सिंगापुर, रंगून, पोपा, पहांग तथा बर्मा के अन्य स्थानों में सितम्बर १९४२ से २६ अप्रैल १९४५ के बीच युद्ध लड़ना था।

लैफ्टिनेण्ट डिह्लन के विरुद्ध पोपा के आसपास ६ मार्च १९४५ के लगभग हरिसिंह, दुलीचन्द, दर्याबसिंह और धर्मसिंह की हत्या करने के चार अभियोग थे।

फत्तान शाह नवाजखां पर पोपा पहाड़ी या उसके आस-पास २६ मार्च १९४५ के लगभग खजीन शाह और आयासिंह द्वारा की गई मुहम्मद हुसैन की हत्या में सहायक तथा प्रेरक होने का अभियोग था।

पहिले अभियोग में धारा १२१ और बाकी अभियोगों में धारा ३०२ के अनुसार सजा दी जा सकती थी।

अभियुक्तों ने अपने को सब अभियोगों में सर्वथा निर्दोष बताया।



चर्चा करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि लड़ाई जिस उद्देश्य से लड़ी गई, वह गौण है। कानून की नजरों में उससे अपराध कम नहीं हो जाता। राजभक्ति की अवहेलना करते हुए यह अपराध किया गया था। युद्धवन्दी होने पर भी वे इस राजभक्ति से मुक्त नहीं हो सकते थे। आजाद हिन्द फौज के अफसर की हैसियत से उसकी ओर से युद्ध करते हुए उन्होंने यह अपराध किया था। हिन्दुस्तानी सेना के सिपाहियों और अफसरों से यह सेना निम्न प्रकार संगठित की गई थी—

( १ ) सदर मुकाम,

( २ ) हिन्दुस्तानी फील्ड ग्रुप,

( ३ ) शेरविल गुरिल्ला ग्रुप,

( ४ ) स्पेशल सर्विस ग्रुप,

( ५ ) इण्डेलिजेंस ग्रुप ( भेदिया दल ) और

( ६ ) री-इन्कोर्समेण्ट ग्रुप

शेरविल गुरिल्ला ग्रुप में गान्धी गुरिल्ला रेजिमेण्ट, आजाद गुरिल्ला रेजिमेण्ट और नेहरू गुरिल्ला रेजिमेण्ट शामिल थी। सुभाषचन्द्र बोस के सिंगापुर आने पर दो तीन मास बाद नवम्बर १९४३ में नं० १ गुरिल्ला रेजिमेण्ट, जिसको बोस या सुभाष रेजिमेण्ट कहा जाता था, खड़ी की गई। कर्नल शाह नवाजखां इसके कमाण्डर नियुक्त किये गये। बाकी तीन रेजिमेण्टों में गान्धी, आजाद तथा नेहरू को २-३-४ नम्बर दिया गया। इन सबका एक डिब्रिजन बनाया

गया । नं. २ विविजन में युद्धबन्दी और नागरिक शामिल थे । नं. ३ विविजन में केवल नागरिक ही थे, जिनकी भरती मलाया में आजाद हिन्द संघ ने की थी ।

१५ फरवरी १९४२ को सिंगापुर का पतन हुआ । १७ फरवरी को बहुत से युद्धबन्दियों को फरेर पार्क में ले जाया गया । कप्तान एम० एस० कियानी के कमान की दो रेजीमेण्ट भी इनमें थीं । जापानी अफसर मेजर फुजीवारा ने उनके सामने भाषण दिया । भारतीय सेना के कुछ अफसर और कप्तान मोहनसिंह भी उस समय उपस्थित थे । मेजर फुजीवारा को भारतीय सैनिकों को जापानियों की ओर करने के लिये सिंगापुर के पतन से पहिले ही नियुक्त कर दिया गया था । उसके और कप्तान मोहनसिंह के भाषण हुये । कप्तान मोहनसिंह ने कहा कि स्वदेश की आजादी के लिये लड़ने को हम आजाद हिन्द फौज खड़ी कर रहे हैं । तुमको उसमें शामिल होना चाहिये ।

१९४२ की पहली अक्टूबर को आजाद हिन्द फौज खड़ी की गई थी । मार्च १९४२ में कप्तान शाह नवाजशां ने युद्धबन्दी अफसरों के सामने भाषण देते हुए कहा कि कप्तान मोहनसिंह के सदर मुकाम में कान्फ्रेस होकर यह निश्चय किया गया है कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, भले ही हमारा धर्म कुछ भी क्यों न हो, हमें स्वदेश की आजादी के लिये अपरय लड़ना चाहिये । बंगकौक में जून १९४२ में एक बड़ी कान्फ्रेस हुई । इसमें भारतीय सेना की अनेक रेजीमेण्टों के प्रतिनिधि

उनसे आजाद हिन्द फौज में भरती होने को कहा जाता रहा ।

दिसम्बर १९४२ में मोहनसिंह और जापानियों में अनयन शुरू हुई । मोहनसिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया । १० फरवरी १९४३ को आजाद हिन्द फौज के अफसरों की कान्फ्रेंस हो कर एक प्रश्नावली तय्यार की गई । इनमें एक प्रश्न यह था कि क्या आप आजाद हिन्द फौज में भरती होंगे कि नहीं ? इसका नकारात्मक उत्तर देने वालों को १३ फरवरी को रासबिहारी बोस के सामने पेश किया गया । वहां उनको एक विज्ञप्ति दी गई । इसमें अन्य बातों के साथ गांधीजी के तीन सप्ताह के उपवास और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये बाधित करने के आन्दोलन की भी चर्चा की गई थी और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में शामिल होने की अपील की गई थी । जनवरी १९४३ में फिर जोरों से भरती की गई ।

अभियुक्तों ने भी इन सब में हिस्सा लिया । जनवरी-फरवरी १९४३ में कप्तान शाह नवाज ने पोर्ट ब्लेक्सन में जाकर अफसरों, सूबेदारों और जमादारों के सामने भाषण दिया । अप्रैल-मई में वे पोर्ट स्वेटनहम में भाषण देने गये । बिदादरी कैम्प के सिनेमा हाल में जनवरी १९४३ में जापानी अफसर ईबाकुओ और रासबिहारी बोस के सामने लेफ्टिनेण्ट डिल्लन ने भाषण दिया । मार्च १९४३ को मेजर धारे के साथ डिल्लन कितरा और तार्डिंग आये । अभियुक्तों

ने आजाद हिंद फौज में भरती करने, उसके संगठन को सुदृढ़ बनाने और सम्राट की फौजों के विरुद्ध युद्ध करने का हुक्म देने के अलावा स्वयं भी युद्ध में भाग लिया। पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार उन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया। भारतीय सेना के अस्त्र-शस्त्र और वस्त्रियां काम में लाई गईं। उन पर आजाद हिन्द फौज के विल्ले लगा लिये गये।

अगस्त १९४२ में लेफ्टिनेण्ट नाग ने आजाद हिन्द सरकार और फौज का कानून तैयार किया। इसमें २४ फोडे तक मारने की सजा भी शामिल की गई। अगस्त १९४४ में फोडों की संख्या ४५ से ५० तक बढ़ा दी गई थी।

जनवरी १९४३ में एक शासन समिति का संगठन किया गया। इसकी ओर से भाषणों का भी प्रबन्ध किया जाता था। मई १९४३ के करीब "डाइरेक्टोरेट आफ मिलिटरी व्यूरो" कायम किया गया। सहगल मिलिटरी सेक्रेटरी और शाह नवाज जनरल स्टाफ के चीफ नियुक्त किये गये।

२१ अक्टूबर १९४३ को सुभाषचन्द्र बोस का सिंगापुर में भाषण हुआ। उन्होंने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा की। जिन व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई, उनमें शाह नवाजखां का भी नाम था। ३१ अक्टूबर १९४४ को आजाद हिन्द सरकार की युद्ध समिति का संगठन किया गया।

मार्च १९४५ में जब कुछ लोग आजाद हिन्द फौज से ब्रिटिश सेना में मिलने लगे, तब सुभाषचन्द्र बोस ने उनको

गिरफ्तार करने और विद्रोह करने पर गोली तक मारने का हुक्म जारी किया।

मुकद्दमे में पेश की जाने वाली गवाही के बारे में सरकारी वकील ने कहा कि वह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होगी। लिखित गवाही में अभियुक्तों के हस्ताक्षर के बहुत से कागज पेश किये जायेंगे। शाह नवाज के हस्ताक्षरों के कागजों का उल्लेख करते हुए सरकारी वकील ने बताया कि इनमें जापानी सन् का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग करने का आदेश १४ मई १९४३ को निकाला गया था और १९४३ के स्थान में २६०३ लिखने को कहा गया था। युद्ध शुरू होने पर अपने साथ मिलने या आत्मसमर्पण करने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों के साथ व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक योजना शाह नवाज ने तैयार की थी।

कप्तान सहगल ने मिलिटरी सेफ्टरी की हैसियत से ५ सितम्बर १९४४ को एक हुक्म जारी किया था, जिसमें बताया था कि आजाद हिन्द फौज के अफसरों को बहादुरी के लिए पद्म इनाम दिये जायेंगे। विशेष वीरता दिखाने वालों और किसी अंग्रेज या अमेरिकन अफसर को गिरफ्तार करने वालों को 'तगमये शत्रुनाश' देने का पेलान किया गया था।

१९४४ और १९४५ की कप्तान शाह नवाज की छायरियां भी, जो उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं, पेश की जायेंगी। इसमें पता चलता है कि २७ जनवरी १९४४ को कप्तान शाह नवाज ने जापान के सर्वोच्च सेनापति से भारत की ओर अन्तिम कूच करने



लाल क़िस्ते में—चन्द्रा हालत में पहिली आजाद हिन्द फौज  
का संगठन करने वाले और उसके जी० श्री० गो० जनरल मोहन-  
सिंह और मेजर तथा क्वार्टर मास्टर जनरल मुहम्मदसिंह दिल्लग ।

का आदेश प्राप्त किया था। ३० मार्च की डायरी में, जापानियों के इकतर्फा व्यवहार की शिकायत दर्ज है। ४ अप्रैल १९४४ की डायरी में दर्ज है कि कप्तान शाह नवाज ने इम्फाल पर हमला करने का निर्णय किया। ७ और १५ जुलाई १९४४ की डायरियों में राशन की कमी होने, चार गढ़वालों के भूख से मरने और जापानियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने का उल्लेख है। भूख से लोगों के मक्खियों की तरह मरने, आत्मघात करने और जापानियों से कुछ भी सहायता न मिलने का भी उल्लेख किया गया है। ८ अगस्त १९४४ में तो यह भी दर्ज है कि जापानियों ने धीमारों के लिए कुछ भी सहायता न भेज कर उनको आत्म-हत्या तक करने की सलाह दी।

१९४५ की डायरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें २१ फरवरी १९४५ में शाह नवाज के युद्ध के लिये पोग की ओर पूछ करने, नेताजी से मिलने और उनसे सब आदेश प्राप्त करने का उल्लेख है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई १७ तक की डायरी में से अनेक उद्धरण देते हुए सरकारी वकील ने युद्ध के मोर्चे की कुछ घटनाओं, जापान के पराजय और शाह नवाज के गिरफ्तार होने की घटनाओं का उल्लेख किया। १७ मई का उद्धरण यह है कि "१६-१७ मई की रात को सीतापीजिक्स गांव में प्रवेश किया। १५ गज की दूरी से पंजाब रेजीमेण्ट के लोगों ने हम पर बुरी तरह गोलियां दागीं। हमारा पथप्रर्शक मारा गया। मेरा धैला खो गया। रात जंगल में काटी। शाम को ६-५ बजे गिरफ्तार किया जाकर गेज साइलेंस और

सदर मुकाम में लाया जाकर जेल में भेज दिया गया ।”

व.पतान सहगल के हाथ के वागजों, हुक्मों, रिपोर्टों आदि की चर्चा करते हुए सरकारी वकील ने उनमें से कइयों को पढ़ कर सुनाया । आजाद हिन्द फौज के अफसरों और सैनिकों के शत्रु के साथ मिलने की ६ अप्रैल १९४५ की रिपोर्ट और २६ मार्च १९४४ को अफसरों को दिये गये नम्बरों और उनकी रेजीमेण्टों के बारे में जारी किये गये आदेश को पेश करने के बाद उनकी १९४५ की डायरी में से भी कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए गए ।

लैफ्टिनेण्ट दिह्लन के हाथ की रिपोर्टों और युद्ध के मैदान में दिए गए हुक्मों का भी सरकारी वकील ने उल्लेख किया ।

आजाद हिन्द फौज में तीनों के मान-सम्मान और ओहदों का विस्तार के साथ वर्णन करने के बाद सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्तों का युद्ध के साथ जो सम्बन्ध है, उसको देखते हुए अन्तिम दिनों में युद्ध क्याओकापड़ांग और पोपा के आस-पास लड़ा जा रहा था । तब तीनों अभियुक्त लड़ाई के मैदान में थे । वे सम्राट के विरुद्ध सेनाओं का संचालन करते हुए स्वयं भी युद्ध में भाग ले रहे थे । ४ मार्च १९४५ को पांचवीं गुरिल्ला रेजीमेण्ट ने दो जीप मोटरें और एक सैट बेतार के तार का अपने ढाँचे में ले लिया था । दो अंग्रेज फौजी मारे गए थे । इनमें से एक जीप गाड़ी सहगल अपने काम में लाते थे । ५ मार्च की सहगल की डायरी में भी इसका उल्लेख है ।

१६ मार्च १९४५ को लैफ्टिनेण्ट दिह्लन की कमान में



लड़ने वाली चौथी गुरिल्ला रेजीमेण्ट की एक कम्पनी की. अंग्रेज सेना से क्याओफापहांग पर मुठभेड़ हुई। इसमें ६० से १०० तक फौजी थे। इनमें से छः मारे गए और ३५ गिरफ्तार किए गए। अंग्रेज फौज में चार गुरखे मारे गये और छः घायल हुए। इस मुठभेड़ की दिल्ली के हाथ की १८ मार्च की रिपोर्ट है।

इस प्रकार युद्धविषयक पहिले अभियोग का विवेचन करने के बाद हत्याओं और उनमें सहायक होने के अभियोगों की सरकारी वकील ने भीमांसा करते हुए कहा कि सरकारी अभियोग यह है कि कप्तान सहगल ने चारों सिपाहियों को गोली से मारने का हुक्म दिया और लैफ्टिनेण्ट दिल्ली ने उनको ६ अप्रैल १९४५ को गोली के घाट उतार दिया। इस बारे में ६ अप्रैल को लैफ्टिनेण्ट दिल्ली की अपने हाथ की लिखी हुई रिपोर्ट है। २६ फरवरी को इन लोगों ने लड़ाई के मोर्चे पर शत्रु से जा मिलने और उससे सम्बन्ध कायम करने का यत्न किया था। आजाद हिन्द फौज के सिपहसालार की ओर से दी गई मृत्युदण्ड की सजा कप्तान सहगल ने स्वयं लिखी और उस पर ६ अप्रैल १९४५ की तारीख है। लैफ्टिनेण्ट दिल्ली के भी उस पर हस्ताक्षर हैं। अप्रैल १६ के आदेश-पत्र में भी यह दर्ज है कि कप्तान सहगल ने ६ मई को 'मृत्युदण्ड' की सजा दी और ५ अप्रैल की शाम को ७ बजे वह सजा दे दी गई। मौखिक गवाही से यह बताया जायगा कि इन चारों के हाथ पीछे बांध कर ६ मार्च को लाया गया और एक खाई में बिठा दिया गया। लैफ्टिनेण्ट दिल्ली ने मापण दिया और बताया कि अंग्रेजों के

साथ मिलने के लिए कोशिश करने के अपराध में इनको मृत्यु की सजा दी गई है और अब ये गोली के घाट उतारे जायेंगे। उनमें से एक को यादर लाकर लैफ्टिनेण्ट ने फिर एक छोटा-सा भाषण दिया और उसकी प्रार्थना को सुने बिना ही हिदायतुल्ला को गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इस पर उसने गोली दाग दी और वह गिर कर मर गया। दूसरे को भी इसी तरह हिदायतुल्ला ने और तीसरे व चौथे को कालूराम ने गोली से मार गिराया। वे अधमरी हालत में थे कि शेरसिंह को उन पर पिस्तौल से बार करने का लैफ्टिनेण्ट डिह्लन ने हुक्म दिया। पिस्तौल दागी गई। लैफ्टिनेण्ट डिह्लन ने फिर सबको भविष्य के लिए सावधान करते हुये भाषण दिया और चारों की लाशें खाई में गाड़ दी गईं।

कप्तान शाह नवाज पर मुहम्मद हुसैन की हत्या में सहायक होने का आरोप है। इसके सम्बन्ध में लिखित प्रमाण तो नहीं है। पर, मौखिक गवाही से पता चलेगा कि उस पर फौजियों को अंग्रेजों से मिल जाने के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया था। इसके लिए उसको गोली से उड़ाने की सजा दी गई थी। मुहम्मद हुसैन ने माफी मांगी, पर स्वीकार नहीं की गई। खजिनशाह के हुक्म से उसको एक नाले पर ले जाया गया। वहां उसके लिये कवर खोदी जा रही थी। वहां उसकी आंखें बन्द करके उसको पेड़ से बांधा गया। एक सिक्ख, एक मद्रासी और अयासिंह को उस पर गोली चलाने का हुक्म खजिनशाह ने दिया। तीनों की गोली खा कर वह जमीन पर गिर पड़ा। यदि अभियुक्त अपने को निदर्श मानते हैं,

तो यह उनको सिद्ध करना होगा। विद्रोह के काम में विद्रोहियों का साथ देने और दुश्मनी के काम में दुश्मन का साथ देने वाले बागी ही ठहराये जायेंगे। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति उसके घाद किये जाने वाले क़र्यों की घातक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। बागी क़मान के आदेश पर यदि कोई काम किया जाता है, तो उस आदेश का पालन करना भी बग़ावत में ही शामिल है।

आजाद हिन्द फौज के कानून का सहारा लेकर भी अभियुक्त कानूनी दायित्व से बच नहीं सकते। उस कानून से प्राप्त की गई सत्ता को इस देश की कोई भी अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। यह सत्ता मूल से ही गैरकानूनी है। उसके आधार पर काम करने वाले सरकार के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिये दोषी हैं और उनको उसके लिए दण्ड दिया जाना जरूरी है। आजाद हिन्द सरकार के कानून से स्थापित की गई सत्ता का कुछ भी आधार नहीं है। उसके सहारे आदेश देने और उन आदेशों को मानने वाले उसकी आद में अपने को अपराधी होने से बचा नहीं सकते।

## संरकारी गवाह

पहले सरकारी गवाह लेफ्टिनेण्ट कर्मल पी० घाला ने तीनों अभियुक्तों के नौकरी के रिकार्ड वेश किये। उनके कमीशन अफसर बनाये जाने के गजट की प्रतियां भी उसने अवलत में पेश की।

दूसरे गवाह डा० डी० सी० नाग बंगाल के निवासी थे। १९१५ में मेड्युएल होकर आप सिविल सर्जिस में भरती हुए थे। १९३४ में पहिले दर्जे के मजिस्ट्रेट बनाये गये और बाद में कमीशन अफसर बना दिये गये। १९४१ के मार्च मास में आपको सिंगापुर भेजा गया था और जापानियों द्वारा की गई युद्ध-पोषणा के समय आप पेकांग में थे। अपनी लम्बी गवाही में आपने कहा कि मैं १५ फरवरी को सिंगापुर में था। हवाई हमले में गायब हो जा परने मुझे राहरी और बाद में फौजी अस्पताल में भेज दिया गया।

स्वस्थ होने पर नोसून कैम्प में भेजा गया। यहां मैंने लैफ्टिनेण्ट फर्नल चैटर्जी का एक भाषण सुना। हिन्दुस्तानी और जापानी अफसर प्रायः व्याख्यान देने आया करते थे। तब मुझे आजाद हिन्द फौज के सँगठन का पता मिला। इसका उद्देश्य हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के हाथों से आजाद करना था। फनान शाह-नवाजखां से पहली बार मैं नोसून कैम्प में मिला। मैं उनको पहचानता हूँ। मोहनसिंह के कहने पर मुझे विदादरी कैम्प में भेज दिया गया। वहां मुझे आजाद हिन्द फौज का कानूनी महकमा सौंपा गया। मैंने सबसे पहले उसका बिधान तय्यार किया। पंजाब रेजीमेण्ट के श्री के० माथुर मेरे सहायक थे। कई दस्तावेज पेश किये जाने के बाद गवाह बतलाया कि सितम्बर १९४३ के शुरू में आजाद हिन्द फौज में सिपाहियों की संख्या दस हजार थी। उनके पास रायफलें, बंदूकें, पिस्तौलें तथा अन्य शस्त्रास्त्र और गाड़ियां भी थी। यह सब अंग्रेजी सामान था। अंग्रेजी बर्दी पर आजाद हिन्द फौज के बिल्ले लगा लिये गये थे। बहुत से बिल्ले अदालत में पेश किए गए। आगे गवाह ने कहा कि कप्तान मोहनसिंह द्वारा बनाई गई फौज के लिये एक युद्ध समिति बनाई गई थी। श्री रासबिहारी बोस उसके प्रधान थे। छः सदस्यों में कप्तान मोहनसिंह, कनल गिलानी और फर्नल भोंसले फौज के तथा श्री मैन्नन, श्री राघवन और श्री गोहो जनता के प्रतिनिधि थे। दिसम्बर १९४२ में कुछ मतभेद होने पर कप्तान मोहनसिंह को जापानियों ने गिरफ्तार

कर लिया था। इसके बाद एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया। इसके प्रधान थे कर्नल भोंसले और सदस्य थे कप्तान एम० जैड० कियानी, लेफ्टिनेण्ट कर्नल लोकनाथन और मेजर प्रकाशचन्द्र। इसका काम सैनिकों में अनुशासन एवं नियन्त्रण बनाये रखकर उनकी नैतिकता को बनाये रखना था। यह निश्चय किया गया कि कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी के बाद भी फौज का काम जारी रखना चाहिए। अफसरों को भी इसमें शामिल होने के लिये प्रेरित किया गया। मैं फौज में भरती नहीं होना चाहता था। श्री रासबिहारी घोस के कहने पर भी जब मैं सहमत न हुआ, तब मुझे जापानी अफसर मेजर ओगावा को सौंप दिया गया। कैम्प में स्वाम्भ्य विगड़ने पर मैं मई १९४३ में फौज में भरती हो गया और मैंने अपना पुराना काम संभाल लिया। इस समय व्यवस्था कुछ बदली हुई थी। प्रबन्धसमिति की ओर से लेफ्टिनेण्ट कर्नल भोंसले सब व्यवस्था के अध्यक्ष थे। सेना की व्यवस्था कप्तान शाह नवाज, कप्तान सहगल और कप्तान अब्दुल रशीद के हाथों में थी। एम० जैड० कियानी सेना के फर्माएडर थे। फौज की टुकड़ियों के नाम बदल दिए गए थे।

जुलाई १९४३ में श्री सुभाषचन्द्र घोस सिंगपुर आ गये। आते ही फौज का सारा नियन्त्रण उनके हाथों में दे दिया गया और उनको सिपहसालार बना दिया गया। "इस्टियन

इण्डिपेंडेंस लीग" के भी वे प्रधान बनाये गये। २५ अगस्त को उन्होंने निम्न आशय का विशेष आदेश जारी किया :—

“एक हिन्दुस्तानी के लिए स्वदेश की आजादी के निमित्त खड़ी की गई फौज का सिपहसालार बनना प्रसन्नता, अभिमान और गौरव की बात है। जो काम आज मैंने अपने हाथों में लिया है, उसकी गुरुतर जिम्मेवारी से मैं भलीभांति परिचित हूँ। सर्वशक्तिमान् प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अत्यन्त संकट और विपत्ति में भी हिन्दुस्तानियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभा सकूँ। मैं विभिन्न धार्मिक मतों एवं सम्प्रदायों के चालीस करोड़ हिन्दुस्तानियों का अपने को विनीत सेवक मानता हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन इस प्रकार करूँगा कि इन चालीस करोड़ भारतीयों का भाग्य मेरे हाथों में सर्वथा सुरक्षित रहे और मैं प्रत्येक भारतीय का अपने प्रति पूरा विश्वास सम्पादन कर सकूँ। अदम्य राष्ट्रीय भावना और पक्षपातशून्य न्याय के आधार पर ही आजाद हिन्द फौज का गठन संभव है। मातृभूमि की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों तथा आजाद हिन्द सरकार की स्थापना के लिए चालीस करोड़ भारतीयों की शुभ कामनाएँ आवश्यक हैं। हिन्द की आजादी के लिए तत्पर रहने वाली स्थायी सेना के गठन में आजाद हिन्द फौज के फौजियों को महत्वपूर्ण भाग लेना है। अपने इसी पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इसमें शामिल होना है। हिन्द की आजादी इसका एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कुछ करने या मर मिटने की

साथ ही उसकी शक्ति है। विकट संकटों के समय हमारी यह फौज अभेद्य दोवार साबित हो और हमारी प्रगति के मार्ग को यह प्रशस्त एवं निष्फण्टक बनाने वाली सिद्ध हो। हमारा कार्य महान् है। हमारी लड़ाई बहुत लम्बी और मुसीबतों से भरी हुई है। अपने देश की अन्तिम स्वतन्त्रता और न्याय में मेरी दृढ़ श्रद्धा है। संसार की जन-संख्या के पंचमांश चालीस करोड़ इन्सानों का भी आजाद होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी इस आजादी का मूल्य चुकाने को हम कटिबद्ध हैं। संसार की कोई भी ताकत अब हमें अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित नहीं रख सकती। सैनिकों, अफसरो और साथियों! आपकी निरंतर सहायता और अटूट देशभक्ति से प्रेरित होकर ही आजाद हिन्द फौज हिन्द की आजादी के प्राप्त करने में समुचित साधन बन सकती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारी अन्तिम विजय सुनिश्चित है। हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 'चलो दिल्ली' के गगनभेदी जयघोष के साथ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए नई दिल्ली के बायसराय भवन पर राष्ट्रीय मंडा पहराना और प्राचीन ऐतिहासिक लाल किले में विजय महोत्सव मनाता हमारा निश्चित लक्ष्य है।"

दूसरे दिन ६ नवम्बर को अपना ययान जारी रखते हुए गवाह ने कहा कि आजाद हिन्द फौज के सदर मुकाम के शासन विभाग के अध्यक्ष फतान हयीयुररहमान ने मुझे आजाद हिन्द फौज का विधान बनाने को कहा था।



हैदराबाद रेजीमेण्ट के कप्तान दिलसुख ने भी कहा था। इण्डियन आर्मी एक्ट के आधार पर इसको बनाया गया था। कोड़े मारने की सजा देने की धारा ५५ के सम्बन्ध में काफी बहस होने पर गवाह ने बताया कि उसमें समय समय पर तब्दीलियां की जाती रहीं और कोड़ों की संख्या ५० तक कर दी गई। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों के गठन और नाम आदि का ब्यौरा देने के बाद गवाह ने बताया कि उसके सैनिकों की संख्या बालीस हजार तक पहुंच गई थी। उसमें आघे मुद्धवन्दी और आघे मलाया में बसे हुए हिंदुस्तानी थे। सुभाष बोस के सिंगापुर में आने के बाद २४ अक्टूबर १९४३ को केफ बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पांच हजार हिन्दुस्तानी शामिल हुये। तमाम पूर्वीय देशों के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित थे। कुछ जापानी अफसर भी थे। सुभाष बाबू ने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की इस सभा में घोषणा की। फरवरी १९४४ में आजाद हिन्द फौज का सदर मुफाम रंगून में लाया गया और सिंगापुर में भी एक सदर मुफाम कायम रखा गया। ३१ मार्च १९४४ को मैं रंगून आया। मिलिटरी सेक्रेटरी कप्तान सहगल ने मुझे मेमयो जाने का आदेश दिया। १० अप्रैल को मैं वहां पहुंच गया। इस समय आजाद हिन्द सेना मनीपुर और अराकान के युद्ध-क्षेत्र में फैल गई थी। चौथी रेजीमेण्ट अभी मांडले में ही थी। अधिवृत्त प्रदेश के नामजद गवर्नर लेफ्टिनेण्ट चैटर्जी ने मुझे ऐसे प्रदेश के लिये बनाये गये कानून तथा योजनाओं को देखने के लिए कहा।

तब सुभाष बोस भी मेमयो ही में थे। पराजित होने के बाद आजाद हिन्द फौज ने जुलाई १९४४ में माण्डले से लौटना शुरू किया। अप्रैल १९४५ में लड़ाई जोरों पर थी। दूसरी डिविजन पोपा पहाड़ी पर चकावांग में और पहिली डिविजन रंगून-मांडले के मार्ग जियावाड़ी में पिनमाना में बंदी हुई थी। रंगून में छः हजार सैनिक होने पर भी उनके पास शस्त्रास्त्र का अभाव था। रंगून में आजाद हिन्द फौज के प्रवेश करने पर उसका रिकार्ड नष्ट कर दिया गया था। आजाद हिन्द फौज के साथ जापानी अफसरों का सम्बन्ध कायम रखने वाले संगठनों के नाम 'श्वा कोरु फीकन' और 'ठिकरी फिक्यान' थे।

फौज की प्रबन्ध-समिति में मैने फत्तान शाह नवाज खां के साथ काम किया था। शाह नवाज खां जनरल स्टाफ के प्रधान थे। बाद में छापामार दल के सेनापति बना दिये गये थे। फत्तान सहगल सेनाविभाग में थे। वहाँ उनको मेजर बनाया गया। फरवरी १९४५ के अन्त तक उन्होंने मिलिटरी सेक्रेटरी का भी काम किया। उसके बाद 'डी० ए० जी०' का काम भी उनको सौंपा गया। फरवरी १९४५ में उनको दूसरी डिविजन की दूसरी पैदल सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। लैफ्टिनेंट डिप्टन से मेरा परिचय नीसून कैम्प में, मार्च १९४२ में हुआ। सितम्बर १९४२ में वे फौज के सवर मुकाम में चले गये। सड़ और यातायात विभाग के वे अध्यक्ष भी रहे। मई १९४३ में वे त्रिदादरी कैम्प में थे। पहली डिविजन की पहली पैदल सेना के वे अक्टूबर १९४३ में सेनापति नियुक्त किये

गये और जूको मेजर का पद दिया गया। सितम्बर १९४४ में  
छापामार टुकड़ी का सेनापति बनाकर माण्डले भेज दिया गया।

डा० नाग की गवाही के बाद अदालत की कार्यवाही  
मुल्तवी करने के सम्बन्ध में बहस होकर १५ दिन के लिये  
उसे मुल्तवी कर दिया गया।

२१ नवम्बर को सफाई के वकील श्री भूलाभाई देसाई  
द्वारा जिरह किए जाने पर डाक्टर नाग ने फिर बताया कि  
सितम्बर १९४२ से मई १९४५ तक मैं आजाद हिन्द फौज का  
सदस्य रहा। फरवरी १९४३ में दुबारा फौज का संगठन किया गया।  
मैं मई १९४३ में फिर इसमें शामिल हो गया। इसमें मैंने जज  
एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडजेण्ट जनरल के पदों पर  
काम किया। मैं उसके न्यायविभाग का अफसर था। आजाद हिन्द  
फौज का विधान बनाने के बाद मेरा मुख्य काम था—सेना की  
कानूनी व्यवस्था तथा मुकदमों का निरीक्षण करना। कानूनी  
सलाहकार का काम भी मेरे आधीन था। २१ अक्टूबर १९४३ को  
आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार का गठन होने पर मुझे  
केवल कानूनी सलाहकार का काम सौंपा गया था। आजाद हिन्द  
सरकार के कानूनी सलाहकार थे श्री सरकार। वे बंगाल में सिविल  
सर्विस में थे। जापान की युद्ध-घोषणा के बाद की पेनांग और  
सिंगापुर में घटी घटनाओं का चर्च करते हुए गवाह ने  
आजाद हिन्द फौज के विधान बनाने और उसके 'एडवोकेट  
जनरल' के पद पर स्वेच्छा से नियुक्त होने की बात कही।  
गवाह ने कहा कि आजाद हिन्द फौज एक सुसंगठित सेना थी।

उसका सब काम कानून एवं विधान के अनुसार होता था। आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा के समय २१ अक्टूबर १९४३ की सभा में मैं उपस्थित था। 'आजाद हिन्द संघ' की शाखायें मलाया, और बर्मा में प्रायः सब जगह थीं। इस सभा में इन शाखाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पूर्वीय एशिया में २५ लाख हिन्दुस्तानी रहते थे। सुभाष बाबू 'नेताजी' के नाम से प्रसिद्ध थे। अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के मन्त्रियों ने इस सभा में शपथ ली और सबने इस सरकार को मंजूर किया। सुभाष बाबू ने स्वयं घोषणा-पत्र पढ़ा था। वह रिफार्ड में रखा गया था। १९४४ के शुरु में आजाद हिन्द बैंक की स्थापना की गई थी। हिन्दुस्तानियों ने इसके लिये खूब रुपया दिया। अर्थव्यवस्था अर्थविभाग के आधीन थी। पहिले कर्नल चैटर्जी और बाद में श्री राघवन अर्थमन्त्री नियुक्त किये गए थे। सेना को वेतन नियमित रूप से दिया जाता था। अधिकृत प्रदेश की व्यवस्था के लिये "आजाद हिन्द दल" का गठन किया गया था। इसमें सिर्फ नागरिक ही भरती किये जाते थे। अण्डेमान और निकोबार का शासन अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के हाथों में दे दिया गया था। लैफ्टिनेण्ट कर्नल लोकनाथन और बाद में मेजर आलवी वहां के चीफ कमिशनर नियुक्त किये गये थे। जापानी और आजाद-हिन्द फौज में परस्पर मित्रसेनाओं का सम्बन्ध था। अमेरिका और इंग्लैण्ड के विरुद्ध नियमित रूप से युद्ध-घोषणा की गई थी। श्री हाचिया जापान सरकार की ओर से आजाद हिन्द सरकार के

यहां दूत थे। जर्मनी, इटली, जापान, थाईलैण्ड, फिलिपाइन और मंचूकुओ की सरकारों ने इसे स्वीकार किया था। बर्मा सरकार द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया था। बर्मा सरकार की सेना के सेनापति जनरल आंग सान थे। आजाद हिन्द सरकार ने आजाद हिन्द फौज की सहायता से पूर्वीय एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों के जान, माल और सम्मान की रक्षा की थी। सिंगापुर के पतन के बाद हिन्दुस्तानी युद्ध-बन्धियों के लिये नीसून, विवादरी, सिलेटर, धुलार और कांजी में मुख्य कैम्प बनाये गये थे। अस्पतालों का भी प्रबन्ध था, जिनमें एक हजार रोगी रह सकते थे।

आजाद हिन्द फौज के गठन के सम्बन्ध में दिये गये कप्तान मोहनसिंह के एक भाषण की चर्चा करते हुए गवाह ने कहा कि यह भावना शुरू से ही बहुत प्रचल थी कि आजाद हिन्द फौज को जापानियों के आधीन न किया जायगा और जरूरत पड़ने पर उनसे भी लोहा लिया जायगा। उसका मुख्य लक्ष्य अपने देश की आजादी था। सुभाष बोस के रूपमें उनको ऐसा नेता मिल गया था कि उसके रहते वे जापानियों के हाथों में खेल नहीं सकते थे। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं ने मिलकर मित्रता के समान नाते से भाग लिया। फौज के सारे अफसर और शिक्षक हिन्दुस्तानी थे। तिरंगा झण्डा उल्टा झण्डा था। उसके दिल्ले सर्वथा अपने ही थे। सुभाष बाबू के एक भाषण की चर्चा करते हुए गवाह ने कहा कि फौज में भरती होने के लिये किसी पर जोर-जबरदस्ती न की जा कर सब काम स्वेच्छा से होता था।

उनका यह निश्चित मत था कि हिन्द की आजादी हिन्दुस्तानियों के अपने प्रयत्न और बलिदान से ही प्राप्त हो सकेगी। फौज का राष्ट्रीय गीत "बन्देमातरम्" था। वाद में और भी गीत अपनाये गए। सिंगापुर से 'जयहिन्द' या 'आजाद हिन्द' नाम का पत्र भी निकलता था। फौज में लैफ्टिनेण्ट का चेतन ८०), कप्तान का १२५), मेजर का मलाया में १८०), बर्मा में २३०) और कर्नल का ४००) था।

तीसरे सरकारी गवाह के० धारलकर ने २२ नवम्बर को गवाही देते हुए सिंगापुर के पतन के बाद किए गए आत्म-समर्पण और नीसून तथा विदादरी कैम्पों का वर्णन करते हुए कहा कि वहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी किसी को पीटा नहीं गया।

चौथे सरकारी गवाह सूबेदार मेजर बाबूराम ने सिंगापुर के पतन के बाद 'करेर पार्क' की सभा, लैफ्टिनेण्ट कर्नल हार्ट के हिन्दुस्तानी युद्धयन्त्रियों को जापानियों के हाथों में सौंपने, उसके भाषण, मेजर फूजीवारा द्वारा कप्तान मोहनसिंह की 'जी० ओ० सी०' के पद पर की गई नियुक्ति और कप्तान मोहनसिंह के आजाद हिन्द फौज की स्थापना के सम्बन्ध में दिए गए भाषण की चर्चा विस्तार से करने के बाद बताया कि उस समय लोगों में इसके लिए कितना उत्साह था। कप्तान मोहनसिंह ने कहा कि आजादी केवल प्रदर्शनों और नारों से नहीं मिल सकती। मलाया में अच्छी तरह न लड़ने का हम पर दोषारोपण किया जाता है, किन्तु हम लड़ते किन हथियारों से? हमारे पास था क्या?

लैफ्टिनेन्ट डिल्लन और कर्नल शाहनवाज खां से अपना परिचय  
 यताते हुए गवाह ने बिदादरी और बंगकौक में सम्मेलनों में  
 स्वीकृत प्रस्तावों का व्यौरा उपस्थित किया और बताया कि मैं  
 स्वेच्छा से इस फौज में भरती हुआ था। आत्मसमर्पण के  
 समय के सारे शस्त्रास्त्र जापानियों ने हमको दे दिए थे। अभि-  
 युक्तों के वकील श्री देसाई द्वारा जिरह किए जाने पर गवाह ने  
 बताया कि नीसून कैम्प में कप्तान शाह नवाज खां के प्रबन्ध में  
 फौज में भरती होने था न होने वालों को एक-सा ही भोजन  
 दिया जाता और उनके साथ व्यलहार भी एक-सा होता था।  
 व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक थी।  
 उसके लिए २५०० डालर का खर्च किया गया था। बंगकौक  
 सम्मेलन के प्रस्तावों की चर्चा भी गवाह ने की। जज एडवोकेट  
 के प्रश्न का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि आजाद हिन्द फौज  
 का उद्देश्य हिन्द की आजादी होने से मैं उसमें शामिल हुआ  
 था। जब जापानियों ने हिन्दुस्तान पर हमला करने के लिये हमें  
 अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहा, तभी कप्तान मोहनसिंह  
 और जापानियों में ठग गई और कप्तान मोहनसिंह की गिर-  
 प्तारी के बाद उसको भंग कर दिया गया।

पांचवें सरकारी गवाह जमादार अल्ताफ रजाक ने बताया  
 कि मैं छापामार बल में था, जिसके सेनापति कप्तान सहगल थे।  
 आजाद हिन्द फौज के गठन का बखान करते हुए उसने कहा  
 कि जब हमने मोर्चे के लिए प्रयाण किया, तब सुभाष बाबू ने  
 हथारी सेना का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय झंडे की सलामी

के बाद भापण देते हुए कहा कि जिन्हें लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार का संकोच है, वे पीछे हट जायें। यह समारोह मिंगलदान में होने के बाद हम लोग प्रोम और पोपा पहुँचे। कप्तान सहगल भी वहाँ आ गए। नेहरू रेजीमेन्ट के तीन सौ फौजी स्वेच्छा से वहाँ आ पहुँचे थे। लैफ्टिनेन्ट विल्लन को उनका सेनापति नियुक्त किया गया। कप्तान सहगल ने सेना ले भागने के बारे में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को गोली से उड़ा देने का अधिकार हर फौजी को दे दिया गया है और रात को भाग जाने वाले पाँचों अफसरों को गिरफ्तार करने का यत्न किया जा रहा है। सफाई के घकील श्री देसाई द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि युद्ध-चन्द्रियों के कैम्पों में जो अव्यवस्था थी, वह जापानियों के ही कारण थी। कप्तान शाह नवाजगं ने यह साफ कह दिया था कि फौज में जो लोग भरती होना चाहें, वे सर्वथा स्वेच्छा से ही भरती हों। फौज को हट निरपयी, वीर, साहसी और देश की स्वतन्त्रता के लिये सर्वथा न्यौझा करने वालों की ही आवश्यकता है। हमारी कम्पनी के अधिकतर लोगों ने युद्धचन्द्री रह कर मरने की अपेक्षा अपने देश की मुक्ति के लिए मर जाना से बरकर मान कर फौज में भरती होना ही पसन्द किया। गुमान पोस की इन चेतावनी पर कि जो युद्ध-क्षेत्र में आगे न जाना चाहें, पीछे हट जायें,—किसी ने भी पीछे रहना पसन्द न किया।

दोटे सरकारी गणेश गन्तोपसिंह १९४२ में जोधपुर में जापानियों के हाथों युद्ध-चन्द्री बनाये गये थे। १९४२ के सितम्बर



मास में आप आजाद हिन्द फौज में भरती हुये थे। गवाह ने बताया कि वह कप्तान सहगल के कहने पर दूसरी धार खड़ी की गई आजाद हिन्द फौज में भरती हुए थे। उन्होंने साफ ही कहा था कि इसके लिए किसी को भी मजबूर न किया जायगा। सिलेटर कैम्प में भाषण देते हुए कप्तान शाह नवाजखां ने भी देश की आजादी के नाम पर अपील की थी। उन्होंने कहा था कि गुरु गोविन्दसिंह जी का साथ देने वाले भी शुरू में पांच ही साथी थे। हमें भी ठीकै ही साहसी और धीर साथी चाहियें।

सातवें गवाह लैंतनायक गंगाराम नेवार ने बताया कि कप्तान शाह नवाजखां ने उसके कैम्प में आकर देश की आजादी के लिए उपस्थित हुए इस अलम्य अवसर से लाभ उठाने पर जोर दिया।

आठवें गवाह सूवेदार जनरल नूरखां ने बताया कि लैफ्टिनेण्ट डिल्लन ने नीसून कैम्प में भाषण देते हुए कहा था कि जापानियों के धर्म के प्रवर्तक भगवान् बुद्ध भारत में ही पैदा हुए थे। इस लिए जापानियों के साथ मिल कर देश को स्वतन्त्र करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये। गुप्तचरों के दल के संगठन का विवरण बताते हुए गवाह ने कहा कि किस प्रकार जापानियों की सहायता से उसको तय्यार किया गया था और फरवरी १९४४ में एक पनडुब्बी में बिठा कर हिन्दुस्तान भेजा गया था। मार्च में यहां आने पर हमने अपने को ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया।

नौवें गवाह इंचलदार सबासिंह ने बताया कि मैं युद्धबंदी

धनाये जाने के कुछ समय बाद ही फौज में भरती हो गया। लैफ्टिनेण्ट डिह्लन और मेजर धार ने हमारे कैम्प में आकर भाषण देते हुए कहा था कि यह फौज केवल हिन्दुतान की आजादी के लिए ही लड़ेगी। यदि कहीं जापानियों ने हिन्दुस्तान में प्रवेश करने पर हमें धोखा दिया, तो हमें उनसे भी लड़ना होगा। फिर ऐसा समय हाथ न लगेगा। मैं नेहरू रेजीमेण्ट में था। हमारे कमाण्डर पहिले तो मेजर महबूब थे, बाद में लैफ्टिनेण्ट डिह्लन धनाए गए। ईरावदी नदी के किनारे पर चानगू प्रदेश यँ हम रक्षापंक्ति बना कर डट गये थे। भीषण युद्ध हुआ। मैंने अंग्रेजी सेना को आत्म-समर्पण किया था। जिरह करने पर गवाह ने बताया कि स्वदेश की आजादी की भावना से प्रेरित होकर और उसके लिए अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय करके ही मैं आजाद हिन्द फौज में भरती हुआ था।

दसवें गवाह काकासिंह ने नीखून कैम्प में श्री डिह्लन के भाषण देने की बात कही और बताया कि मैं जानता था कि मुझे आजाद हिंद फौज में भरती होने के बाद हिंद की आजादी के लिए लड़ना है।

ग्यारहवें गवाह जमादार मुहम्मद नयाब, बारहवें गवाह हवलदार मुहम्मद सखर और तेरहवें गवाह जमादार मुहम्मद हसन ने भी आजाद हिंद फौज के संगठन पर रोशनी डाली। चौदहवें गवाह हवलदार बलित पहादुर ने बताया कि आजाद हिंद फौज के प्रचार के लिये गुलर कैम्प में

नाटक हुआ करते थे और उसी समय भाषण भी होते थे, जिनमें देश की आजादी के नाम पर अपील की जाती थी। पन्द्रहवें गवाह राइफलमैन रविलाल ने आजाद हिंद फौज के गठन का हाल सुनाते हुए बताया कि हम से कहा गया कि जो इसमें भरती न होंगे, उनको शत्रू समझा जायगा और शत्रुओं का-सा उनके साथ व्यवहार किया जायगा। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मलाया में जापानियों के मुकाबिले में पीछे हटने के समय भोजन-व्यवस्था बहुत खराब थी, शस्त्रास्त्र भी न थे, टैंकों की सहायता न थी और हवाई जहाज भी कुल चालीस ही थे। मुक्त से अक्टूबर-नवम्बर १९४५ में तीनों अभियुक्तों के सम्बंध में ध्यान लिये गये थे। सोलहवें गवाह रामस्वरूप ने कहा कि सिंगापुर का पतन होने से एक दिन पहिले मैं देसी भेस में सेना में से निकल भागा था। कतान मल्लिक के कहने पर मैं आजाद हिन्द फौज भरती हुआ था और गुप्तचरी के काम पर हिन्दुस्तान भेजा गया था। मैं स्वेच्छा से ही भरती हुआ था और उसके उद्देश्य में मेरा हृदय विश्वास था। सत्रहवें गवाह लैसनायक महेन्द्रसिंह ने बताया कि बिदादरी कैम्प के चाद सिलेक्टर कैम्प में भेजे जाने पर मैं स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में भरती हुआ था। जिरह करने पर उसने कहा कि इस फौज का उद्देश्य हिंद की आजादी था और मेरा उसमें विश्वास था। अठारहवें गवाह सिंघाही दिलासासिंह ने बताया कि मैं पहिले आजाद फ्रिगेट नं० ४ बटालियन में था। फिर मुझे बोस ब्रिगेड

संभावना की जा रही थी, जिसमें एक गढ़वाली कंपनी लेने वाली थी। हम अधिक से अधिक खाद्य सामान एकत्र करने में लगे हुए थे। १५ मई १९४४ को शाह नवाज खां के कहने पर मैं फोन पर जब समाचार लेने गया, तब मेजर महयूय ने कहा था कि थोड़े से ही प्रतिनिधि से शाह पर अधिकार कर लिया गया है। अफसरों और फौजियों में वैसा ही साहस और उत्साह घना हुआ है। हमारी बुद्धि भी क्षति नहीं हुई। शत्रु का बहुत-सा सामान हमारे हाथ लगा है। जिरह करने पर गवाह ने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना और फौज के संगठन का विशद वर्णन करते हुए कहा कि हमें हिन्दुस्तानी अफसरों द्वारा ही शिक्षा दी गई थी और फौज में एक भी अफसर जापानी न था। हाका मोर्चे पर कूच करने के समय सुभाष बाबू ने अपने भाषण में कहा था कि "आजाद हिन्द फौज का संगठन जापानियों के लाभ के लिये न करके हिन्द की आजादी के लिये किया गया है। अपनी कमियों के कारण हम जापानियों की सहायता ले रहे हैं। हमारे लिये सुख नहीं, कष्ट ही कष्ट है। हमें देशभक्त फौजी चाहियें। जो आगे नहीं धड़ सकते उनको पीछे हट जाना चाहिए। किसी ने भी पीछे रहना मंजूर न किया। हाका परलम हिन्दुस्तान की सीमा का प्रदेश है। पंजाब हिन्दुस्तान की सीमा से सिर्फ १५ मील दूरी पर है। खाने का सामान त रहने पर हम जङ्गल की पास पर पक्षियों पर गुज़ार करते थे।

थीसबे गवाह हनुमानप्रसाद ने कहा कि मैं नेहरू रेजीमेण्ट की सातवीं बटालियन में नर्सिङ्ग थ्रदंली था। हम दिन में आराम करते और रात को खांदियां खोदते थे। मैं ब्रिगेड के अस्पताल में काम करता था।

इसीसबे गवाह मुनेरभालसिंह ने कहा कि मैंने पोपा क्षेत्र की लड़ाई में भाग लिया था। हमारी दुकड़ी का काम राशु की मोर्चेबन्दी की जानकारी प्राप्त करना था। याइसबे गवाह सिपाही सादुल्लाखां ने जिरह करने पर स्वीकार किया कि मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कोई कायरी आदि न रखता था। मैंने जो भी तिथियां आदि बताई हैं, वे सारी मुझे पहिले ही से बताई गई थीं। मुझे अपना ध्यान भी पहले से बता दिया था। तेईसबे गवाह लॉसनायक मुहम्मद सैयद ने बताया कि मैं आजाद हिन्द फौज में सेफएड लैफ्टिनेण्ट था। कप्तान सहगल के व्याख्यान की चर्चा करने के बाद गवाह ने कहा कि जब हमारी रेजीमेण्ट मोर्चे के लिये कूच करने को थी, तब नेताजी ने कहा था कि हम हिन्द की आजादी के लिये लड़ते हुए जो कष्ट झेल रहे हैं, उनका अन्त निकट ही है। जो कष्ट न झेल सकें, उनको मोर्चे पर नहीं जाना चाहिये। वे पीछे रंगून लौट सकते हैं। भिगतावन में कप्तान सहगल का भाषण हुआ था। उन्होंने युद्ध के मोर्चे की सारी स्थिति हमको समझाई। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि कप्तान सहगल ने कहा था कि जो मोर्चे पर न जाना चाहें अथवा अंग्रेज सेना में मिल

जाना चाहें, वे अभी से सूचित कर दें। उनके लिये समुचित व्यवस्था कर दी जायगी। लेकिन, कोई भी सामने न आया। नेताजी ने हमसे कहा था कि हम चालीस करोड़ खुदापीड़ित और नग्न भारतीयों के प्रतिनिधि हैं। हमें थोड़े भोजन और वेतन से काम चला लेना चाहिये। अपने देश के प्रति हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये। मुझ पर इस उपदेश का बहुत गहरा असर पड़ा था। चौबीसवें गवाह गुलाम-मुहम्मद ने बताया कि मैं फौज में भारी शस्त्रास्त्रों की शिक्षा देने पर नियुक्त किया गया था। सिंगलाउन में कप्तान सहगल ने अपने भाषण में कहा था कि मुझे तुम्हारी फौज का सैनापति होने में गर्व है। हमें नियन्त्रण और अनुशासन का मापदण्ड ऊंचा उठाना है। नेताजी के भाषण का उल्लेख करते हुए गवाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हमारी स्वतन्त्रता का भाग्यनिर्णय इम्फाल की पहाड़ियों और अराकान के मैदानों में होगा। गतवर्ष की तरह इस वर्ष एक भी सैनिक को शत्रु से मिल जाने का कल्पित काम नहीं करना चाहिए। जो आगे न बढ़ना चाहे, वह पीछे हट सकता है। तुम को भूख, प्यास, तंगी और तकलीफ का सामना करना है। मृत्यु पर भी मामना करना है। अब तक हमारा नारा था—“चलो दिम्ची।” अब हमारा नारा होगा—“खून, खून, खून।” इसका मतलब यह है कि हमने चालीस करोड़ के लिए अपना पूरा यशस्वी का निश्चय कर लिया है। शत्रु के खून की भी हम नहीं मरवा देंगे। नागरिकों पर नाग्य यह होगा—“करो सब निज़ावर,

वनो, सब फकीर ।” अन्त में नेताजी ने स्वयं ब्ये नारे लगाये थे—  
 “इन्कलाब जिन्दाबाद” “चलो दिल्ली” और “खून, खून, खून ।”  
 २३०० सैनिकों के एक स्वर के इन नारों से, आकाश गूँज उठा ।  
 क्योंकि पहांग से हमें पोषा भेजा गया था । नं० २ पैदल सेना को  
 पोषा पहाड़ी की रक्षा का भार सौंपा गया था । मोर्चे पर, कर्नल  
 शाहनवाज खां ने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक भाषण दिया  
 और कहा कि हिन्द के नाम को फलङ्कित नहीं करना ।  
 दुगोन क्षेत्र में हमने दुश्मन को मार भगाया । इसी अवसर पर  
 तीन सैनिक भागने के अभियोग में पकड़े गये थे, जिनमें एक  
 मुहम्मद हुसैन था । पेनघिन क्षेत्र में भी हमने दुश्मन को मार  
 भगाया था । लेकिन, शत्रु के हवाई हमले का सामना हम न कर  
 सके । पैदल सेना ने भी हमें घेर लिया था । अन्त में कर्नल  
 सहगल ने मेगिनगांग के तीन ओर पहाड़ियों और एक ओर  
 नदी से घिरे हुए रास्ते से निकलने का आदेश दिया । लेकिन,  
 रास्ता न मिलने से शत्रु से लड़ कर मर मिटने या बेश यदल कर  
 छिपे रहने की अपेक्षा हमने युद्ध-बन्दी बनना स्वीकार किया ।  
 कर्नल सहगल ने आत्मसमर्पण के लिए एक सन्देश भेजा और  
 अंग्रेज अधिकारियों के सामने हमने आत्मसमर्पण कर दिया ।  
 जिरह करने पर गवाह ने कहा कि कर्नल सहगल ने उस सन्देश  
 में यह लिखा था कि यदि हमें युद्ध-बन्दी बनाना स्वीकार न किया  
 गया, तो हम अन्त तक लड़ेंगे । नीसून कैम्प में दिये गये कर्नल  
 शाहनवाज खां के भाषण का उल्लेख करते हुए गवाह ने कहा  
 कि उन्होंने कहा था कि इजरत इमाम हुसैन की तरह मैंने हिन्द

की आजादी के लिए लड़ने का निश्चय कर लिया है। जो कोई भी हमारे देश को घुरी नजर से देखेगा, उसको अन्धा कर दिया जायगा। पोपा में दिये गये भाषण का भी गवाह ने उल्लेख किया। कुछ सैनिकों के शत्रुके साथ मिल जाने की निन्दा करते हुए शाह नवाजखां ने कहा कि हम पर सारे संसार की आँखें लगी हुई हैं। यदि हम इस समय भी आजाद न हुए, तो एक हजार वर्षों तक भी आजाद न हो सकेंगे। पच्चीसवें गवाह अल्लादित्ता ने बताया कि उसको हांगकांग में जापानियों ने बन्दी बनाया था। आजाद हिन्द फौज से भागने वाले मुहम्मद हुसैन को मृत्युदण्ड की सजा कप्तान शाह नवाजखां ने दी थी। छब्बीसवें गवाह ने कहा कि मैं विवादरी कैम्प के अस्पताल में नर्सिंग सिपाही था। मुझे पोपा भी भेजा गया था। मैं अल्लादित्ता और मुहम्मद हुसैन दोनों को जानता हूँ। खजिन शाह ने मुहम्मद हुसैन को गोली मारने के लिए मुझे कहा था। अयासिह ने मुझे राइफल दी थी। मैंने तीन गोलियाँ दागी थीं। संताइसवें गवाह सरदार मोहम्मद ने जिरह में कहा कि मुझे निश्चय नहीं कि गुलाम मुहम्मद मर गया था या नहीं ? गोलियों की आवाज से मैंने उसके मरने की कल्पना कर ली थी। मैंने उसके यदन पर खून के चिन्ह नहीं देखे। अठाइसवें गवाह अब्दुल हफीजखां ने अपने ययान में कहा कि मैं नीसून कैम्प के अस्पताल में था। मुझे वहाँ से नेहरू रेजीमेण्ट की सातवीं बटालियन में भेजा गया था। मैंने लैफ्टिनेण्ट बिहान के आदेश पर चार सैनिकों को गोली से मारे जाते हुए देखा था। उन पर शत्रु से मिल जाने का



आरोप था। गिरफ्तार किये जाने पर उनको मृत्युदण्ड की सजा दी गयी थी। उन्नचीसवें गवाह झानसिंह ने बताया कि चार सैनिकों को जब लैफ्टिनेण्ट डिह्लन के आदेश पर गोली से उड़ाया गया था, तब मैं वहाँ पर उपस्थित था।

६ दिसम्बर को अन्तिम और तीसरे सरकारी गवाह लैफ्टि-  
नैन्ट कर्नल जे० ए० किडसन ने बताया कि मैं १९४५ में घर्मा में  
गुरखा पलटन का कमाण्डर था। अप्रैल १९४५ में हम इरावदी  
के बायें किनारे होते हुये आगे बढ़ रहे थे। मैं मोयांग गाँव से  
६०० गज उत्तर में रुक गया। मुझे पता लग गया था कि गाँव में  
शत्रु सेना आ पहुँची है। एक टुकड़ी गाँव के दक्खिन में भेजी  
गई। गाँव के पूर्व की ओर मुझे अपनी टुकड़ी के नायक के साथ  
कप्तान सहगल मिला। साथ में उनकी फौज के अनेक अफसर  
और सिपाही भी थे। मुझे उनकी ओर से लिखा गया पत्र  
भी दिया गया। उसमें लिखा था कि ५० अफसर और ५००  
सैनिक युद्ध-मन्दी बनाये जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर  
रहे हैं। मैंने सहगल से परिचय प्राप्त किया और उनके भोजन  
का प्रबन्ध किया। कप्तान सहगल ने मुझे बताया कि मैं एक  
ऊँचे और सच्चे ध्येय से लड़ा हूँ। पराजित हो जाने पर  
उसका परिणाम भोगने के लिये भी तत्पर हूँ।

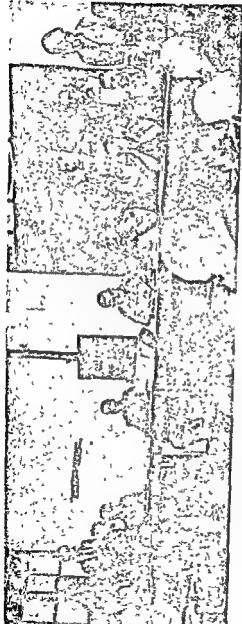
गंगासरण ने जिरह करने पर बताया कि मुझे मोर्चे पर से  
भागने के कारण मृत्युदण्ड की सजा दी गई थी, किन्तु कप्तान  
सहगल ने मेरा यह दण्ड माफ कर दिया था।

शुरू कर दिया। आत्म-समर्पण करने के हुक्म तक मैं अपने स्थान पर डटा रहा। दुरमन से लड़े बिना ही आत्म-समर्पण करने के हुक्म पर मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे यह सैनिक स्वाभिमान के सर्वथा विपरीत प्रतीत हुआ।-

१५-१६ फरवरी की रात को हमें पता दिया गया कि हिन्दुस्तानी अफसर और फौजियों को फरार पार्क में और अंग्रेजों को चांगी में इकट्ठा किया जा रहा है। अफसरों में किये गये इस भेदभाव पर हमें बड़ा अचरज हुआ। १६ फरवरी की सुबह हमारे कमान-अफसर मेजर येट्स मुझ से अलविदा लेने आया। मैं समझ गया कि हमें यन्त्रणायें और यातनायें भोगने के लिए जापानियों के हाथों में छोड़ा जा रहा है।

ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कर्नल ह्यूट ने हमें फरार पार्क में आ कर जापानियों के हाथों में यह कहते हुए दे दिया कि "अब तुम जो जापानियों का हुक्म वैसे ही मानना होगा, जैसे हमारा मानते थे।" उसके बाद मेजर कूजीवारा ने कहना शुरू किया कि "जापानी सरकार की ओर से तुम अब मेरे कब्जे में हो और मैं तुम को जी० ओ० सी० कप्तान मोहनसिंह के हाथों में देता हूँ।" उसने यह भी कहा कि तुम लोगों के साथ युद्ध-ग्रन्थियों का-सा नहीं, भाइयों का-सा व्यवहार किया जायगा। तुम सभ्य, आशा है, उस सेना में भरती हो जाओगे, जो कप्तान मोहनसिंह के नेतृत्व में भारत की आजादी के लिए लड़ने को रूढ़ी की जायेगी। कप्तान मोहनसिंह ने भी इसी आशय का भाषण दिया।

मैं यह सुन कर अवाक रह गया। मैंने सोचा कि क्या हमें



पौडी अदालत के सारे जज अपने स्थानों पर बैठे हुये मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं।

अब अपने ही भाइयों के साथ लड़ना होगा ? पशुओं की तरह हमें जापानियों के हाथों में दे दिया गया था । मैं बड़े असमंजस में पड़ गया । मुझे पूरा निश्चय था कि मोहनसिंह कूट-नीति में जापानियों का मुकाबिला न कर सकेगा और वे हमारा उपयोग अपने लिए करेंगे । मेरी राजभक्ति की भावना भी अभी मुझमें नहीं थी । मैं स्वयं आजाद हिन्द फौज से अलग रहकर दूसरों को भी अलग रहने की सलाह दी । मेरी सलाह यह थी कि जो हमें आजाद भारत में लाने के लिये लड़ रहे हों, हम उसी को गोली

उपयोग न करने दिया जाय और वैसा होने पर उसको नष्ट-  
भ्रष्ट कर दिया जाय। सबको इसमें शामिल होने की आजादी  
दे दी गई। जोर-जबरदस्ती करने वालों को, मैंने कहा कि, सब  
सजा दी जायेगी। मुसलमान अफसरों की एक सभा मसजिद में  
की गई।

दंगकौक सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि चुनने के प्रश्न पर  
फैजान मोहनसिंह से मतभेद होने से मुझे नीसूत कैम्प से  
कुश्वालात्मुर कैम्प में भेज दिया गया। जून में वहां पहुंचने पर  
मुझे मलाया के समस्त कैदियों का कमाण्डर बना दिया गया।  
मेरा काम सब जगह जाना और उनकी शिकायतें जापानी  
सदर मुकाम में पहुँचाना था। जापानी कमाण्डर का यहां भी  
यही भाषण होता था कि हम सब एशिया के लोग आपस में  
भाई-भाई हैं। भारत की आजादी के लिये शीघ्र ही लड़ी जाने  
वाली लड़ाई के हम आपको सैनिक बनाना चाहते हैं। जापानियों  
की सद्भावना पर मुझे सन्देह है। इसलिये मैंने जापानी  
कमाण्डर से साफ साफ कह दिया कि किसी को भी सेना में  
जबरन भरती न किया जायगा। सेरेम्बान में विरुद्ध स्थिति पैदा  
हो गई। वहां फौज में भरती होने से इनकार करने पर बन्दिनों  
के कैम्प के चारों ओर मशीनगनों लगा दी गई थी, कैम्प के  
कमाण्डर लैफ्टिनेण्ट गुलाम मुहम्मद को तनहाई में दे दिया  
गया था और उनको चौबीस घण्टे का नोटिस गोली चलाने के  
लिए दे दिया गया था। मैंने वहां जाकर मुश्किल से स्थिति  
को संभाला। सारे मलाया का दौरा कर जापानियों को

जोर-जबरदस्ती करने से रोका । क्वाँलोलम्पूर में तो मैंने हिन्दुस्तानियों को जापानी कवायद आदि सिखाने से भी बन्द कर दिया, हालांकि रंगून में अंग्रेज कैदियों ने यह सब सीखना शुरू कर दिया था । मैंने हिन्दुस्तानी कैदियों के लिये भोजन आदि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था करवा दी थी । काम साधारण लिया जाना था और वेतन नियम से दिया जाता था । आमोद-प्रमोद, खेल-कूद और सिनेमा देखने को भी सहूलियत कर दी गई थी । मस्जिदों और मन्दिरों में जाकर प्रार्थना करने की भी सहूलियत दे दी गई थी ।

एक बार मेरे बाहर होने पर २३ नान-कमीशान अफसरों को कैद में लेकर उनके कट्टर अंग्रेज-वस्त्रपाती होने से कुछ को गोली से उड़ाने का भी निश्चय कर लिया गया था । मैंने लौटने पर इसका विरोध किया और कमाण्डर होने के नाते से मैंने कहा कि जावानियों को सीधी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । मैंने स्वीका देने की भी धमकी दी । उनमें से पन्द्रह को तो लौटाने को वे तय्यार हो गये । बाकी को उन्होंने गोली से उड़ा देने का निश्चय किया हुआ था । उनका अपराध यही था कि वे अपनी राजभक्ति की राशय पर आमादा थे । मैंने जांच के लिये अदालत बिठाने की मांग की । इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । उस अदालत से वे सब निर्दोष छोड़ दिये गये । इस प्रकार मैंने कभी भी जावानियों की इन्द्रा के सामने मिर नहीं कुछाया और उनको अपना मनमानी नहीं करने दी । अपने देश की प्रतिष्ठा पर मैंने कभी भी आंच नहीं आने दी । उनके जातिगत

पक्षपात का सदैव विरोध किया। किसी को कभी गिरफ्तार नहीं करने दिया। सप्ताह में एक दिन युद्धवन्दी उपवास करके निराश्रितों की सहायता किया करते थे। २० घंटे चावल जापानी कमाण्डर से लेकर हर मास ऐसे लोगों में बांटा जाता था।

सितम्बर १९४२ में मैं सिंगापुर आ गया। यहां आकर पहिला काम मैंने बंदी कैम्पों के निरीक्षण करने का किया। उनके सुख-सुभीते का मैं पूरा ध्यान रखना था। कई बीमारों को अपने पास रखकर अच्छा किया।

जापानियों के गड़बड़ करने पर मैंने आजाद हिन्द फौज को भंग करने के लिये कप्तान मोहनसिर को तैयार कर लिया।

यह जान कर कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर आकर आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथों में लेंगे, मैं दूसरी आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गया। उस समय यह स्पष्ट था कि जापानी हिन्दुस्तान पर जरूर हमला करेंगे। ब्रिटिश सेनायें उनको रोकने में असमर्थ थीं। इसलिये हिन्दुस्तान में लड़ाई की आशंका फैलना निश्चित था। मलाया में जापानियों की लूट और अनाचार को मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह सब मैं हिन्दुस्तान में होने नहीं देना चाहता था। मलाया में असहाय कैदी बने रहने की अपेक्षा हाथ में रायफल लेकर अपने देशवासियों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा करना हमें अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ। जापानियों के विश्वासघात करने पर उनका सामना करने वाले हिन्दुस्तानियों को मैंने बटोरना शुरू किया।

नेताजी के सिंगापुर आने पर मैंने उनको बहुत निकट से देखना शुरू किया। मैं उनसे पहिले कभी मिला न था और न मैं उनके बारे में कुछ अधिक जानता ही था। मैंने उनके अनेक भाषण सुने। मुझ पर जादू का-सा असर हुआ। उनके व्यक्तित्व ने मुझे मोह लिया। अपने देश का सही चित्र उन्होंने हमारे सामने पेश किया। मैंने पहिली बार हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तानी की नजरों से देखा। उनके निःस्वार्थ जीवन, देश के प्रति उनकी एकान्त निष्ठा, उनकी स्पष्टवादिता और जापानियों के सामने मुकने से इनकार करने की उनकी दृढ़ता का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैंने अनुभव किया कि उनके हाथों में देश की प्रतिष्ठा सर्वथा सुरक्षित है। संसार की किसी भी चीज के साथ उसका सौदा करना उनके लिये संभव ही नहीं है। उन्होंने कमजोर और सर्वस्व त्याग के लिये अनिच्छुक लोगों को आजाद हिन्द फौज से अलग हो जाने को कहा। घसमें रहने वालों से उन्होंने कहा कि उनको भूख, प्यास, थकान और मृत्यु तक का सामना करने को तैयार रहना चाहिये। मैंने उन हजारों गरीबों को देखा, जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में रख दिया। उनका सारा का सारा परिवार आजाद हिन्द फौज में भरती होकर स्वदेश के लिये फकीर बन गया। मुझे पता चला कि हमें असली नेता मिल गया। जब उसने फरोड़ों नंगे भूखे, निःशस्त्र और असहाय हिन्दुस्तानियों के नाम से अपील की और उनकी आजादी के लिये अपने



सहायक होने की अपेक्षा वाघक ही सिद्ध हुए। कभी कभी तो मुझे उन पर गोली तक चलानी पड़ी। यह मेरी हायरी में भी दर्ज है। गिरफ्तार किए गए अंग्रेजों के साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया था और मैं अपने सैनिकों के लिए उनसे वैसे ही अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता था। कोई भी वेतनभोगी या जापान के हाथ का खिलौना यनी हुई फौज इतनी मुसीबतें न झेल सकती थी। हमने आजाद हिन्द सरकार की नियमित सेना के रूप में अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए सभ्यतापूर्ण कानून के अनुसार युद्ध किया था। इसलिए मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, जिसके लिए किसी फौजी या अन्य किसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चलाया जाय।

हरण में सहायक होने के अभियोग में भी मैं निर्दोष हूँ। एक नाजुक समय में मुहम्मद हुसैन ने विश्वासघात करने का यत्न किया और उसने दूसरों को भी उसके लिए उत्तेजित किया। यह सफल हो जाता, तो सारा भेद दुश्मन के हाथों में पड़ कर हमारा सर्वनाश हो जाता। आजाद हिन्द फौज के ही नहीं, किंतु सभी सभ्य देशों के फौजी कानून के अनुसार यह असाधारण अपराध है और इसकी सजा है मृत्यु। यह गलत है कि मैंने यह सजा दी थी और मुझ द्वारा दी गई सजा के लिए उसको गोली मारी गई थी।

## २. कप्तान प्रेमकुमार सहगल

कप्तान सहगल में अपने वयान में कहा कि मैं सर्वथा

निर्दोष हूँ और यह मुकद्दमा 'गैरकानूनी' है। ११ नवम्बर १९४० को अपनी बटालियन के साथ कम्पनी, कमाण्डर की हैसियत से मैं सिंगापुर आया और हमें कोटाभास की सुरक्षा के लिये बनाये जाने वाले मोर्चे पर भेज दिया गया। जापानियों के साथ हुई कई मुठभेड़ों में हमने नाम पैदा किया। यद्यपि हम लड़ाई में पीछे हट रहे थे, फिर भी कई बार हम आक्रमण भी कर बैठते थे। एक बार तो हमने पांच सौ जापानियों का सफाया करके बहुत-सा गोला-बारूद छीना था। ३०-३१ जनवरी १९४२ की रात को सिंगापुर आकर हमने उसकी सुरक्षा की कमान संभाल ली। २ फरवरी को जापानी सिंगापुर पर उतर आये। १० फरवरी को हमारी उनसे मुठभेड़ हुई। हमने उनको समुद्र और जंगलों में खदेड़ दिया। हम आस्ट्रेलियन सेना का स्थान लेने जा ही रहे थे कि पहाड़ी पर जापानियों ने हमला बोल दिया। आस्ट्रेलियन भाग खड़े हुए और हमारी सड़क को दोनों ओर से जापानियों ने घेर लिया। हमको भारी नुकसान झेलना पड़ा। याकी बटालियन के सदर मुकाम से अलग हो जाने पर भी मैंने कम्पनी के लोगों को इकट्ठा किया और लड़ाई जारी रख कर हम बटालियन से दुपहर को आ मिले। शत्रु के सारे आक्रमण विफल बना देने पर भी हमें १२-१३ फरवरी को बिदा-दरी लाया गया और यहां हमसे आत्मसमर्पण करा दिया गया।

मलाया में हमारी सेनाओं के पीछे हटने पर लोग प्रायः हमसे पूछा करते थे कि क्या हमें दुश्मन की दया पर छोड़ रहे हो? हमारा

क्या होगा ? वे हमें लूटेंगे, हमारी स्त्रियों को बेइज्जत करेंगे और हमें मार डालेंगे। मैं अपने को असहाय देखकर लज्जित होता था।

भेड़-बकरियों की तरह जापानियों के हाथों में सौंपे जाने की फरार पार्क की घटना से हम सब पर गहरी चोट लगी। हमारी बहादुरी का यह बदला था। हमने समझा कि ब्रिटिश सरकार ने वे सब धन्यस्वयं ही काट दिये और उनकी जिम्मेवारी से भी मुक्त कर दिया, जिनसे उसने हमें अपने साथ बांधा था। इस स्थिति में हमसे राजभक्ति की आशा क्या की जा सकती थी ?

कप्तान मोहनसिंह के आजाद हिन्द फौज के संगठन के लिये किये जाने वाले प्रयोगों में साथ देने पर भी लोगों को जापानियों के बारे में काफी सन्देह और आशंका थी। देश को शीघ्र से शीघ्र स्वतन्त्र देखने की इच्छा होते हुए भी मैंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। मेरे सरीखे दस हजार युद्ध-धन्धियों को तैगाव हवाई अड्डे के कैम्प में भेज दिया गया। भोजन, रहन-सहन और दवा-दारु की व्यवस्था यहाँ साधारण-तया अच्छी ही थी। १९४२ के जून मास में बंगकौंक में हुई कान्फ्रेंस में मुझे भी बुलाया गया था। पर, मैं वहाँ न गया। जून और अगस्त के बीच में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं ने मेरा विचार बदल गया। सबसे मुख्य जापानियों का वेग से आगे बढ़ते जाना था और हिन्दुस्तान पर हमला किया ही जाने वाला था। लन्दन के रेडियो से प्राप्त होने वाले समाचार भी भय पैदा करने वाले थे। हिन्दुस्तान से नयी भरती के सिपाही जो भेजे गये थे, उनसे साफ पता चलता था कि किस प्रकार के आदमी हिन्दुस्तान की

रक्षा के लिए बाकी बचे हैं। सिंगापुर के आत्म-समर्पण से कुछ ही समय पहिले आये हुए अफसरों से भी हमें पता चला था कि हिन्दुस्तान में सेना के पास नयी युद्ध-सामग्री बिलकुल भी नहीं है। सिपाहियों को लकड़ी की बन्दूकों और हलकी मशीनगनों से ही सैनिक शिक्षा दी जाती है और हिन्दुस्तान की सुरक्षा की व्यवस्था प्रायः 'नहीं' के बराबर है। हम में से हर एक यह अनुभव कर रहा था कि जापानियों के आक्रमण को हिन्दुस्तान में कोई भी रोक न सकेगा। यह विचारते ही हम कांप उठते थे। दूसरी बात बम्बई में काँग्रेस का "अंग्रेजो ! भारत छोड़ो" का प्रस्ताव पास करना और उसके बाद हुई चटनायें थीं। लन्दन और दिल्ली के रेडियो के इस धारे में चुप रहने पर भी हिन्दुस्तान में जमीन के भीतर काम करने वाले गुप्त रेडियो और जापानी तथा अन्य धुरी राष्ट्रों के रेडियो उन समाचारों और सरकार की ज्यादतियों की खबरें सब ओर फैलाते ही थे। उनसे १८५७ की क्रान्ति के बाद की-सी भयाक्रान्त स्थिति का पता चलता था। इनकी सचाई में सन्देह करने का कोई कारण न था। अपने घर वालों के धारे में भी गहरी चिन्ता ने हमें घेर लिया था। जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश को ऐसी गुलामी में जकड़ रखा था, उस पर हमें रह रह कर रोष आता था। इस पर हम चिन्ता, विचार और चर्चा करते हुए सोचा करते थे कि हमें क्या करना चाहिए ? विदेशी आक्रमण के परिणाम की कल्पना करना हमारे लिए कठिन न था। देश के नेताओं के स्वदेश की रक्षा को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव को धृष्ट के साथ ठुकरा दिया गया था। सरकार

की जो तय्यारी थी, उसको जानते हुए हम में से बड़े से  
 बड़ा आशावादी भी यह मानने को तय्यार न था कि जापान  
 के हमले को विफल बनाया जा सकेगा। जनता से तो आशा ही  
 क्या की जा सकती थी। वह अतिशय भीषण यातनाओं का  
 सामना करने को लाचार हो जाती। अंग्रेज सरकार द्वारा 'घर-  
 फूंक नीति' के अपनाये जाने पर तो मुसीबत और भी बढ़  
 जाती। इस सयक, सिर्फ एक यही हल हमारे पास था कि सुदृढ़,  
 सुसंगठित और सुशिक्षित सेना तय्यार की जाती। वह वर्तमान  
 विदेशी हकूमत से हिन्दुस्तान को छुटकारा दिलाने के साथ साथ  
 जापानियों की ज्यादतियों से उनकी रक्षा करती और अंग्रेजों के  
 स्थान में उन द्वारा अपनी हकूमत कायम किए जाने का विरोध  
 करती। आजाद हिन्द सेना के संगठन का यही लक्ष्य था। इसलिए  
 हमने सोचा कि क्यों न उसमें शामिल हुआ जाय ? मलाया में  
 हिन्दुस्तानियों के जान-माल और इज्जत की उसने जो रक्षा की  
 थी, वह उसमें शामिल होने का एक बड़ा कारण था। अत्यन्त  
 विकट मानसिक स्थिति में मैंने बहुत से दिन बिताये। एक ओर तो  
 अंग्रेजों के प्रति मेरी बफादारी का सवाल था और दूसरी ओर  
 मातृभूमि की पुकार थी। मैंने अन्त में आजाद हिन्द फौज में  
 शामिल होकर उसको ऐसी सुदृढ़, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित और सुनि-  
 यन्त्रित फौज बनाने का निश्चय किया, जो अपने को हिन्दुस्तान  
 के लिए न्यौछावर कर दे। मैं किसी भय या लालच से उसमें  
 शामिल न हुआ था। सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौज के

कमान होने का मुझे केवल ८० डालर वेतन हर मास मिलता था और उससे अलग रहने पर १२० डालर मिल रहा होता ।

विशुद्ध देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही मैंने आजाद हिन्द फौज का साथ दिया था । स्वदेश की आजादी के लिये मैं अपना खून बहाने को तैयार था । यर्मा, मलाया और हिन्दुस्तान में भी अपनी माता-बहिनों की इज्जत और निहत्थे लोगों के जान-माल की रक्षा करने के लिए भी मैंने उसका साथ दिया था । एक पवित्र उद्देश्य के लिए मैं उसमें शामिल हुआ था और मैंने कभी भी किसी पर उसमें शामिल होने के लिए जोर-जबरदस्ती नहीं की । किसी ने भी कभी ऐसा नहीं किया था । भरती सर्वथा स्वेच्छा से होती थी । इस बारे में दी गई गवाही सब झूठी है । किसी भी प्रकार की ज़्यादती में मेरा हाथ नहीं रहा और न मुझे उनका पता ही है । मैं शुरू से ही निःस्वार्थ श्रद्धा पर विश्वास रखता था और मैं ऐसे ही लोगों को चाहता था, जो स्वेच्छा से भारत माता के लिए खून बहाने को तैयार थे । इसीसे मोर्चे पर कूच करने के समय मैंने अपने अफसरों और आदमियों को सब कुछ समझा कर अनिच्छुक लोगों को अलग हो जाने की भी सलाह दी थी । मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अपने को असमर्थ समझने वाले अलग हो भी गये थे । न तो उनके साथ जोर-जबरदस्ती की गई, न घृणा का व्यवहार उनके साथ किया गया और न उनको किसी प्रकार की सजा दी गई । उनको रंगून में री-इन्फोर्समेंट कैम्प में पीछे छोड़ दिया गया था । मोर्चे पर पहुँचने पर मैंने ऐसा...

ही अवसर एक बार फिर दिया। यहां भी कुछ को रंगून लौटने का मौका दे दिया गया था। पोपा में पहुँचने पर तो मैंने लोगों से यहाँ तक कहा था कि जो अंग्रेजों की ओर जाना चाहें, वे अपने शस्त्र देकर उनकी ओर जा सकते हैं। मैं तो एक दिल और एक दिमाग के साथी चाहता था।

मेरे अन्तरंग मित्रों में कई अंग्रेज स्त्री-पुरुष हैं। अंग्रेजों के साथ हमारी दुरमनी नहीं है। गिरफ्तार किए हुए अंग्रेजों के साथ भी मैंने दोस्तों का-सा व्यवहार करने की सख्त ताईद की थी।

नवम्बर १९४४ के अन्त तक मैं सदर मुकाम में मिलिटरी सेक्रेटरी रहा। कुछ समय तक मैंने अमिस्टेसट चीफ आफ स्टाफ का भी काम किया। दिसम्बर में मेरे हाथ में पोपा में लड़ने वाली रेजीमेण्ट दी कमान दी गई थी। मैंने इस लड़ाई में आजाद हिन्द की स्वतन्त्र सरकार की नियमित रूप से सुसंगठित उस मेता के सिगाही की हैमियत से भाग लिया था, जिसने लड़ाई के मध्यतापूर्ण कानूनों के अन्तर विदेशी सत्ता के हाथों में मेरी मातृभूमि को आजाद करने की कुछ ठाना था। ऐसा करते हुए मेरा दावा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरा दावा है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुसार अपने देश की अधिक से अधिक सेवा की है। मेरा यह भी दावा है कि गुप्त युद्धबन्दियों की मारी अधिकारपूर्ण सहूलतें मिलनी चाहियें। पोपा पहाड़ी पर २२ अप्रैल १९४४ को आत्मसमर्पण करने में पड़िते मैंने अंग्रेज सेना के कमाण्डर को यह नोट लिखकर भेजा था कि हम केवल युद्ध-बन्दी के रूप में ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

हमने अपनी शर्त के अनुसार ही आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद हमारे साथ युद्ध-वन्दियों का-सा व्यवहार किया भी गया था। यदि हमारी शर्त स्वीकारनकी गई होती, तो हम बराबर लड़ते रहते और हमारी संख्या छः सौ होने से हम उस समय लड़ाई जारी रख सकते थे। हमारे पास शस्त्रास्त्र की भी कमी न थी और देह में खून की अन्तिम बूँद रहने तक हमने भारत माता की आजादी के लिये लड़ने का दृढ़ संकल्प किया हुआ था।

१३ फरवरी से १० मार्च १९४५ तक मैंने कर्नल शाह नवाजखां के स्थान पर डिविजनल कमाण्डर का भी काम किया। मुझे हम हैसियत से ६ मार्च को चार सिपाहियों के मामले की सुनवाई करनी पड़ी। उन पर कर्नल विल्लन ने शत्रु से मिलने, और सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करने का आरोप आजाद हिन्द फौज के कानून के अनुसार लगाया गया था। दोषी प्रमाणित होने पर उनको मृत्युदण्ड दिया गया। दुःख प्रगट करने पर उनकी और दूसरों की भी ऐसी सजायें माफ कर दी गई थीं। इतना भी दूसरों को सावधान करने के लिये ही किया गया था। सजा दे भी दी गई होती, तो भी मुझ पर उसमें सहायक होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने जो अपराध किया था, उसकी सजा आजाद हिन्द फौज के ही नहीं; बल्कि सभी देशों के फौजी कानून में मौत ही है। कानून से प्राप्त सत्ता के आधार पर ही मैंने पूरी जांच के बाद सजा दी थी।

आजाद हिन्द फौज को यद्यपि देश की आजादी प्राप्त करने अपने प्रारम्भिक उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकी;



फिर भी हम सबको यह सन्तोष है कि हम मलाया, बर्मा और दक्षिण-पूर्वी एशिया में हिन्दुस्तानियों के जान-माल और इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह सफल हुए। रंगून के क्रिश्चियन ऐसोसियेशन और बर्मा इण्डियन ऐसोसियेशन के सभापतियों ने इस घावे में मुझे जो तार भेजे हैं, वे इस बयान के साथ हैं, और वे इसके लिए खासे कृतज्ञ हैं।

### ३. लैफ्टिनेण्ट गुरुवचसिंह दिव्यन :

अपने वक्तव्य को सीधा-सादा बताते हुए श्री दिव्यन ने कहा कि देहरादून के सैनिक विद्यालय में मैंने सीखा था कि देश की सेवा सर्वोपरि है। वहां चैथबुड हाल में मोटे सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है कि “अपने देश की मान-प्रतिष्ठा, भलाई और सुरक्षा का सदा ही हर हालत में पहिला स्थान है। उसके बाद उनके सुख-सुभीते, सुरक्षा और भलाई का स्थान है, जो तुम्हारी फमान में हैं। तुम्हारी अपनी सुरक्षा और भलाई का स्थान सदा ही हर हालत में सबसे पिछे है।” सबसे मेरे विचार में अपने देश और अपने आदमियों का स्थान सर्वोपरि रहा है। फौज में रह कर मैंने सदा ही इस आदर्श के अनुसार देश की सेवा की है। मलाया और ईपोह में मैं अपनी यूनिट के साथ १२ मार्च १९४१ को आया था। जून १९४१ में आर्मी सिगनल स्कूल पूना में मुझे सिगनल सीखने के लिए भेज दिया गया था। पूर्व एशिया में युद्ध शुरू होने पर ५ दिसम्बर १९४१ को मैं जितरा में अपनी यूनिट में चला आया। इस क्षेत्र में जापानियों के साथ सबसे पहिली मुठभेड़ हमारी ही हुई थी। तीन दिन तक हमने उनकी रोक



सफाई के बछील—पण्डित जगहराल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू डा० केनरनाथ कायस्थ,

बन्धुमान मन्मथन के पिता जन्मि १९१९ म मर १९८८

रखा। उसके बाद हमारी फौज तितर-बितर हुई। मैंने और कप्तान हवीबुल रहमान ने ८० आदिमियों को बटोरा। जितरा और अलोर स्टार के पतन और यहां हुई मुठभेड़ का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि हम १४ दिसम्बर की शाम को कुथाला के दाह से किरतियों पर सवार होकर पेनांग आए। हमें पन्द्रह ही मिनट में पेनांग खाली करने के लिए कहा गया। १६ दिसम्बर की सबेरे हम निवांग तिबाल पहुँचे। यहां मुझे और हवीब को पुर्तगाली रक्षा का काम सौंपा गया। १६ दिसम्बर को हमें वहां से तालिंग और फिर ईरोह आने का हुक्म दिया गया। लड़ाई शुरू होने के दिन ८ दिसम्बर से मैंने एक बार भी भरपेट खाना न खाया था। आराम करना तो सम्भव ही न था। बीमार होने से अस्पताल भेजा गया और वहां से सिंगापुर पहुँचा दिया गया। मैंने अच्छा होने पर अपनी यूनिट में जाना चाहा। उसके लिए व्यवस्था होते होते युद्ध सिंगापुर तक आ पहुँचा। ११ फरवरी से सिंगापुर के समर्पण करने की अफवाहें सुनने में आने लगीं। बिदावरी कैम्प से सिंगापुर आते हुए एक स्थान पर हजारों हिन्दुस्तानी तिरंगे मँडे लिए हुए इकट्ठा थे। एक ब्रिटिश कर्नल को जब मैंने यह दिखाया, तब उसने कहा कि जब हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तब वे अपनी व्यवस्था क्यों न करें। १३ फरवरी को हमें सरकारी तौर पर बताया गया कि हमारे पांच सौ हवाई जहाज यहां पहुँच जायेंगे और पेनांग की ओर से अमेरिकन हमला कर रहे होंगे। कैसा कभी न हुआ और १५ फरवरी को कमाण्डिंग ऑफसर ने मुझे बुला कर कहा कि

सिंगापुर ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं यह सुन कर स्तब्ध रह गया। भारी हृदय और भीगी हुई आंखों से मैंने अपनी रिवाल्वर जमीन पर पटक कर अपने आदमियों से शस्त्र इकट्ठे करने को कहा। फरार पार्क में कर्नल हण्ट द्वारा कूजीवार और मोहनसिंह के हाथों में दे दिए जाने की घटना पर श्री बिल्लिन ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमें अंग्रेजों ने अत्यन्त भीषण और असहाय अवस्था में छोड़ दिया हो।

मोहनसिंह मेरा अत्यन्त स्नेही साथी था। हम दोनों एक ही यूनिट में थे। लम्बी मानसिक कशमकश के बाद मैंने उसको अपना जी० सी० ओ० स्वीकार किया। पिछली घटनाओं, पूर्वोक्त सुरक्षापंक्ति के अनुभव और संसार के सबसे बड़े नौसेना के अड्डे के घात की घात में पतन हो जाने से मैंने यह जान लिया कि अंग्रेज हिन्दुस्तान की जापानियों के आक्रमण से रक्षा नहीं कर सकेंगे।

मोहनसिंह का कान आसाग न था। ७५ हजार अफसरों और सैनिकों को सम्मालने की उसने कभी कल्पना भी न की थी। फिर, उन परिस्थितियों में जो संसार में कभी न घटी थी। जिस पराजित और निराशा मेना में अनैतिकता छा गई थी, उसमें नियन्त्रण और अनुशासन रखना इतना आसान न था। आजाद हिन्द फौज में स्वेच्छा से भरती होने के कारण राजनीतिक विचारों की स्वतन्त्रता देना जरूरी हो गया था। जापानी जिन पर सन्देह करते थे, उन अफसरों और आदमियों की उनके हाथों से रक्षा करनी पड़ती थी। हिन्दुस्तानी नागरिकों की भी रक्षा का

सवाल था। हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और मानवीय कानूनों का ध्यान रखते हुये यह सब करना था। जापानियों सरीखे शकी लोगों से निपटना भी आसान न था।

मलया में जापानियों की करतूतों और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली अंग्रेजी सरकार की असहाय स्थिति हमने आंखों से देखी थी। हिन्दुस्तान पर हमला होने पर उसकी हालत पर विचार करते ही मैं कांप जाता था। मैंने इस समय समझा कि डेढ़ शताब्दि में ब्रिटिश शासन ने मेरे अभागे देश का क्या हाल कर दिया है ? जब कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए हमारा शोषण किया है और हमारी भेनाओं से अपने साम्राज्य के सारे युद्ध लड़े हैं, तब उन्होंने हमें अपने देश की रक्षा तक के लिए समर्थ नहीं बनाया और हमें सदा गुलाम बनाए रखने के लिए नपुंसक भी बना दिया। यदि हमारा देश स्वाधीन होता और उसको अपनी रक्षा करने की तय्यारी करने दी गई होती, तो उसकी सीमा को लांघने का किसी ने विचार तक न किया होता। मोहनसिंह जिस आजाद हिन्द फौज का संगठन कर रहे थे, उसमें मुझे अपने देश के लिए एक नयी आशा दीख पड़ी। मैंने अनुभव किया कि यदि अब भी सुदृढ़ राष्ट्रीय सेना खड़ी की जा सके, तो वह विदेशी सत्ता से देश को स्वतन्त्र करने के साथ साथ विश्वासघात करने पर जापानियों का भी सामना कर सकेगी और पूर्वी एशिया में अपने देशवासियों की भी रक्षा कर सकेगी।—मुझे ऐसे—लगा, जैसे भारतमाता मुझे

## आजाद हिन्द सरकार और फौज की स्थिति

सफाई के गवाहों के बयान = दिसम्बर १९४५ को शुरू हुए। पहिले गवाह जापानी विदेशविभाग के साबुते ओहाता ने बताया कि २१ अक्टूबर १९४३ को अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी और उसके प्रति जापानी सरकार का व्यवहार संर्यथा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा समानान्तर सरकार का-सा था। इसी नाते जापानी सरकार ने उसकी सहायता की थी। जापानी सरकार के प्रकाशन-विभाग की ओर से अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के सम्बंध में २३ अक्टूबर १९४३ को प्रकाशित की गई विज्ञप्ति और तत्कालीन प्रधानमन्त्री जनरल तोजो के वक्तव्य की नकलें उपस्थित करते हुए गवाह ने बताया कि जापान सरकार के राजदूत की दैसियत से श्री हाचिया को आजाद हिन्द सरकार के यहाँ भेजा गया था।

इस बारे में जाँगती सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति भी अदालत में पेश की गई ।

दूसरे गवाह सुनीची मत्सुतो ने कहा कि मैं परराष्ट्रविभाग में उपमन्त्री के पद पर युद्ध की समाप्ति तक रहा । अन्य देशों के साथ हुई संधियों को देखने का काम जिस समिति के आधीन था, मैं उसका प्रधान था । अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की घोषणा मैंने अपने दफ्तर में देखी थी । इस सरकार को जर्मनी, इटली, कोशिका, मंचूको-चीन, थाईलैण्ड, फिलिपाइन और बर्मा की सरकारों ने स्वीकार किया था । ६ नवम्बर को टोकियो में हुए सम्मेलन में जनरल तोजो द्वारा दिए गए भाषण के समय मैं उपस्थित था । जिरह करने पर गवाह ने कहा कि टोकियो में मैं सुभाष बायू से मिला था । जापान सरकार ने उनको जर्मनी से लाने का प्रबंध किया था । जापान सरकार को यह मालूम था कि वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हैं । जापान के युद्ध-सम्बंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनकी सहायता प्राप्त करना आवश्यक समझा गया । वे आजाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति और आजाद हिन्द कौज के सितहसालार थे । अप्रैल १९४३ में वे टोकियो पहुंचे थे । श्री देसाई के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि जापानी सरकार के युद्ध-सम्बंधी उद्देश्यों में भारत को स्वतंत्र करना भी शामिल था ।

तीसरे गवाह जापानी सरकार के परराष्ट्रविभाग के उपमन्त्री श्री रेंजो सवादा ने बताया कि आजाद हिन्द सरकार के यहां जापानी राजदूत भेजने का निश्चय नवम्बर १९४४ में कर

लिया गया था। इसके अनुसार श्री हाचिया मार्च १९४५ में रंगून पहुंच गए थे। जिरह किए जाने पर गवाह ने कहा कि जापान सम्राट व सरकार की अनुमति पर ही श्री हाचिया को मैंने रंगून भेजा था। वहां पहुंचने की सूचना भी उसने मुझे दी थी। आजाद हिन्द सरकार के अस्थायी होने के कारण उनको कोई प्रमाण-पत्र देना आवश्यक न समझा गया था, किंतु श्री सुभाषचन्द्र बोस के आग्रह पर वह भेजा गया था। उस पर जापान के सम्राट के हस्ताक्षर थे। परिस्थितियां बिगड़ जाने से वह उनको मिल नहीं सका। लेकिन, इसके बिना भी वह अपना काम करते रहे। इसी हिसाब से वह आजाद हिन्द सरकार के परराष्ट्रमन्त्री से मिले और वह भी उनसे मिलने आया।

चाँधे गद्दाह आजाद हिन्द सरकार के यहां जापानी सरकार के राजदूत श्री तिरो हाचिया ने बताया कि मैं मार्च १९४५ में रंगून पहुंचा था। वहां आजाद हिन्द सरकार के परराष्ट्रमन्त्री कर्नल चैटर्जी से मिला था। २४ अप्रैल १९४५ को मैं रंगून से बंगकौक चला गया। इसी समय आजाद हिन्द सरकार भी बंगकौक चली आई थी। यहां आने तक मैं बंगकौक में ही रहा। मैं रंगून आते हुए कोई प्रमाण-पत्र अपने साथ न लाया था। मैंने आजाद हिन्द सरकार के परराष्ट्रमन्त्री को स्वयं सूचना दी थी कि मैं जापान सरकार का प्रतिनिधि मंत्री हूँ। तब तो मिला कि प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है; किन्तु मुझे वह मिला नहीं। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैं न तो प्रमाण-पत्र और न कोई दूसरा ही पत्र अपने साथ लाया था। मैंने कर्नल चैटर्जी



को मार्च १६४५ में रंगून पहुँचने के दो-तीन दिन बाद ही अपने वहाँ पहुँचने की सूचना दी और उनसे मिला। मैं श्री अय्यर से भी मिला। वे भी दो-तीन बार मेरे यहाँ आये। मैंने श्री सुभाष घोस से मिलना चाहा। मुझे कर्नल चैटर्जी ने बताया कि मेरे पास प्रमाण-पत्र न होने से वे मुझसे नहीं मिलेंगे। मैंने रंगून पहुँचने के चार-पाँच दिनों बाद ही प्रमाण-पत्र के लिये टोकियो तार दिया। मुझे तार मिला कि प्रमाण-पत्र भेजे जा रहे हैं। बंगकौक में भी मुझे मई-जून में तार मिला कि प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है। मैं श्री काकितसुबो और श्री ओद्वा के साथ रंगून से रवाना हुआ था। २१ नवंबर, अप्रैल २३-२४ अप्रैल को जापानी व्यापारियों ने रंगून खाली करना शुरू किया। जापानी सेनाओं की हलचलों या गतिविधि के साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध न था। श्री देसाई के प्रश्न पर गवाह ने कहा कि कर्नल चैटर्जी मुझसे बंगकौक में भी मिले थे। इसलिये मैं समझता हूँ कि आजाद हिन्द सरकार भी वहाँ चली आई थी।

पाँचवें गवाह मेजर जनरल सादारी कृताकृष्ण ने कहा कि आजाद हिन्द फौज के बारे में मुझे १९४३ में जानकारी मिली थी। आजाद हिन्द सरकार की भी मुझे जानकारी थी। श्री सुभाषचन्द्र घोस से मैं जुलाई १९४३ में रंगून में मिला था। इम्फाल में आजाद हिन्द फौज स्वतन्त्र रूप से लड़ी थी। उसका लक्ष्य हिन्दुस्तान की आजादी था। पहली छापामार रेजीमेण्ट जनवरी १९४५ में रंगून आ गई थी। नवाजल्लों इसके फ़ायदों पर। फरवरी या मार्च १९४४ में उसने मोर्चे पर

फूच की। गवाह ने तयशा बनाकर इस रेजीमेन्ट की युद्धक्षेत्र में  
 जो स्थिति थी, उसे विस्तार के साथ बताया। यह तय हुआ था  
 कि हिन्दुस्तान के विजित प्रदेश आजाद हिन्द सरकार के  
 आधीन कर दिये जायेंगे। वहाँ की शासन-व्यवस्था उसी के  
 आधीन रहेगी। हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश करने के अवसर  
 के लिए जापान सरकार और आजाद हिन्द सरकार की ओर  
 से पृथक् पृथक् घोषणा-पत्र तैयार किए गए थे। एक पर  
 लैफ्टिनेण्ट-जनरल कादावे के और दूसरे पर श्री सुभाषचन्द्र बोस  
 के हस्ताक्षर थे। जापानी घोषणा-पत्र में लिखा गया था कि  
 उनकी लड़ाई अंग्रेजों के साथ है, भारतीयों के साथ नहीं।  
 जो भी प्रदेश या युद्ध-सामग्री जापानी अधिकार में आयगी,  
 वह सब आजाद हिन्द फौज को सौंप दी जायगी। दूसरे  
 घोषणा-पत्र में लिखा गया था कि आजाद हिन्द फौज हिन्दुस्तान  
 की आजादी के लिए लड़ रही है। जापानी सेना द्वारा विजित  
 प्रदेश हमें सौंप दिये जायेंगे। सरकारी दफ्तर की जिरह पर  
 गवाह ने कहा कि इम्फाल पर आक्रमण करने की योजना  
 जनवरी १९४४ में तैयार कर ली गई थी और आक्रमण मार्च  
 में किया गया था। आजाद हिन्द फौज की चार डिविजन थी।  
 प्रत्येक में आठ हजार सैनिक थे। शुरू में इम्फाल के मोर्चे पर  
 दस हजार सैनिक थे। बाद में उनकी संख्या बढ़ती रही।  
 छापामार रेजीमेण्ट नं० १, २, ३ के अलावा अन्य कई फौजें  
 भी लड़ाई में शामिल हुईं। जापानियों ने हिन्दुस्तानी सैनिकों  
 के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया। उनके मेहनत-मजदूरी

का काम भी नहीं लिया गया। जो आजाद हिन्द फौज में भरती नहीं होते थे, उनके साथ युद्धवन्दियों का-सा व्यवहार किया जाता था। उनकी डाक पर भी किसी प्रकार की देखरेख नहीं थी। रंगून से वे ब्राह्मकास्ट भी करते थे। दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करते थे। दक्षिणी फौज के इनचार्ज फील्ड मार्शल तेरांची ने जनरल फावाड़े को १९४३ की शरद ऋतु में यह आदेश दिया था कि विजित प्रदेश और अधिकृत युद्ध-सामग्री आजाद हिन्द फौज के आधीन कर दी जाय। मैंने श्री मुभाषचन्द्र घोस की घोषणा का अनुवाद और जापानी घोषणा की मूल प्रति देखी थी। ये जनवरी १९४४ में तय्यार की गई थी। सफाई के चकील श्री देसाई के जिरह करने पर गवाह ने फिर कहा कि कप्तान शाह नवाज हाकाफालन के मोर्चे पर मार्च १९४४ में आए थे। वह इन्काल मोर्चे के ही अन्तर्गत था। अप्रैल १९४४ में आजाद हिन्द फौज की नं० २ रेजीमेण्ट पलेल में थी। आजाद हिन्द फौज के हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश करने पर अप्रैल १९४४ में जापानी सरकार और श्री मुभाषचन्द्र घोस ने कर्नल शाह नवाज खां को बधाई का संदेश भेजा था।

सफाई के छठे गवाह थे आजाद हिन्द सरकार के प्रचार-मन्त्री श्री एस० ए० अय्यर। आपने बताया कि १९४१ में मैं बंगलौर में था। जापानी युद्धघोरणा के बाद मैंने बर्मा के रास्ते हिन्दुस्तान आने का प्रयत्न किया। लेकिन, यह सीमा बन्द कर दी गई थी। मध्य जून १९४२ में बंगलौर में हुए सम्मेलन में मैं भी उपस्थित था। पूर्वी एशिया में सभी देशों के हिन्दुस्तानी

प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। मैं दर्शक के रूप में इसमें उपस्थित हुआ था। बंगकौक सम्मेलन में आजाद हिन्द संघ कायम किया गया। मुझे उसका प्रकाशन-विभाग सौंपा गया। फरवरी १९४३ तक बंगकौक में मैं यह काम करता रहा। ३ मार्च को मैं सिंगापुर आ गया। यहां मैं संघ के प्रधान श्री रासबिहारी बोस से मिला। उससे पता चला कि संघ का सदर मुकाम सिंगापुर में लाया जा रहा है। मैं नेताजी श्री सुभाष-चन्द्र बोस को पहिले से जानता था। वे २ जुलाई १९४३ को सिंगापुर आये थे। ४ जुलाई को हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। श्री रासबिहारी बोस ने इसमें कहा कि मैं टोकियो से सुभाष बाबू के रूप में एक सौगात लाया हूँ और उनके हाथ में संघ की बागडोर सौंपता हूँ। तब दर्प में की गई करतलध्वनि से सभास्थान गूँज उठा। नेताजी ने उसमें यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि मैं शीघ्र ही आजाद हिन्द सरकार की स्थापना करना चाहता हूँ। इस पर चारों ओर से हर्ष-ध्वनि हुई। २१ नवम्बर १९४३ को एक और प्रतिनिधि-सम्मेलन सिंगापुर में हुआ। संघ की रिपोर्ट पढ़ी जाने के बाद नेताजी ने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा की। ह-पँध्वनि से सबन गूँज गया। सरकार के मंत्रियों के नामों की घोषणा करने के बाद सुभाष बाबू ने हिन्दुस्तान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उनके बाद मंत्रियों ने हिन्दुस्तान और नेताजी के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध नियमित रूप से युद्ध की घोषणा की गई। मुझे इस सरकार में भी प्रचार

और प्रवासन विभाग के मंत्री का वामसौंपा गया। आजाद हिन्द संघ के संगठन से सरकार का सारा काम चलता था। अदालत में पेश की गई घोषणा और मंत्रियों की नामावलि को गवाह ने ठोक ब्रताया। मलाया में इस सभका स्वागत किया गया था। अपने देश की आजादी के लिये लड़ने के साथ-साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा भी अनुभव करनी शुरू की। इस सरकार की ओर से मलाया के हिन्दुस्तानियों को राष्ट्रीय ढंग पर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य तथा दवा-दारु आदिक भी संघ की ओर से प्रबन्ध किया गया। अराजकता से हिन्दुस्तानियों के जानमाल की रक्षा की गई। संघ ने लोगों से सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। जून १९४४ तक ऐसे लोगों की संख्या २३२३६२ तक पहुँच गई थी। सरकार ने चन्दा भी इकट्ठा किया। रंगून में अप्रैल १९४४ में आजाद हिन्द का राष्ट्रीय बैंक भी खोला गया। ५३४३६४६ डालर और १८ सेण्ट चंदे में जमा हुए थे। आभूषण आदि के रूप में ८६३११ डालर इकट्ठा हुये थे। दुष्ट से पहिले डालर की कीमत रुपये से अधिक ही थी। श्री दीनानाथ बैंक के डाइरेक्टर और मैं चेयरमैन था। मन्त्री होने से मुझे मालूम है कि फौज में भरती घिलकुल स्वेच्छा से होती थी। हमारे पास स्वेच्छा से भरती होने वाले इतने लोग रहते थे कि हम शस्त्रास्त्र के अभाव में उनको सैनिक शिक्षा नहीं दे सकते थे। सुभाष बायू के सिंगापुर आने के दो-तीन मास बाद ही शासन-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए भी एक स्कूल खोला गया था। जापानी सरकार और आजाद हिन्द सरकार के सम्बन्ध परस्पर मैत्री

“हमारा संघर्ष” नाम का पैम्फलेट मैंने देखा, पर पढ़ा न था। सेना में भरती होने के लिये की गई ज्यादातियों का मुझे कुछ भी पता नहीं। जापानियों के उसके गठन में भाग लेने की भी मुझे जानकारी नहीं है। जापान सरकार द्वारा आजाद हिंद सरकार के स्वीकार किये जाने की घोषणा स्वयं नेताजी ने की थी। गजट में भी इसे प्रकाशित किया गया था। सरकार की नीति और निर्णयों को संघ के मन्त्री कार्य में परिणत करते थे। रेडियो के ब्राडकास्ट में जापानियों का कुछ भी दखल या नियंत्रण न था। हिन्दुस्तान को चावल भेजने का प्रस्ताव हिन्दुस्तान की जनता और सरकार की जानकारी के लिये सिंगापुर रेडियो से जुलाई या अगस्त १९४३ में किया गया था। यमर्मा के किसी भी बन्दरगाह से वह भेजा जा सकता था। यमर्मा में चावल की कमी न थी। सफाई के बकील के पूछने पर श्री अच्यर ने कहा कि जुलाई १९४३ में जनरल तोजो सिंगापुर आकर नेताजी से मिले थे।

अबदमान में आजाद हिन्द सरकार के चीफ कमिशनर लैफ्टिनेण्ट कर्नल ए० डी० लोकनाथन सफाई के सातवें गवाह थे। आपने कहा कि मैं सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। बंगकोर सम्मेलन में ११० प्रतिनिधि उपस्थित थे और ६०-७० प्रस्ताव पास हुए थे। अपने जान, माल और सम्मान की रक्षा करने के लिये संगठित होना सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव था। फौज के संगठन करने और राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों के पालन करने का भी निश्चय किया गया था। जापानियों के

संरक्षण और सहायता के प्रश्न पर श्री रासबिहारी बोस और कप्तान मोहनसिंह में मतभेद पैदा हो गया। श्री रासबिहारी का मुकाब जापानियों की ओर था और कप्तान मोहनसिंह सर्वथा स्वतन्त्र रहकर समानता के नाते काम करना चाहते थे। जापानियों के हस्तक्षेप के कारण कप्तान मोहनसिंह ने आजाद हिन्द फौज को भंग करने का निश्चय किया और अपनी गिरफ्तारी से पहले वे इस आशय का आदेश का एक सीलबंद लिफाफे में बंध करके रख गये थे। दिसम्बर १९४२ के बाद मैं बिदादरी में फौज के सदर मुकाम में था। मैं मेडिकल विभाग का अध्यक्ष था। सुभाष बाबू को मैं जानता था। उनके जुलाई १९४३ में सिंगापुर आने पर मैं उनसे मिला। आजाद हिन्द सरकार की स्थापना के समय मैं उपस्थित था। मैं मन्त्रिमण्डल में भी था। नवम्बर १९४३ में सुभाष बाबू टोकियो गये। १९४४ में हमारी सरकार रंगून आ गई। अण्डमान और निकोबार के आजाद हिन्द सरकार के आधीन किये जाने, २१ मार्च १९४४ को पोर्ट ब्लेयर में उसके लिये विशेष समारोह मनाये जाने और उसमें जापानी अफसरों के भी उपस्थित रहने का बहान करते हुये आपने कहा कि 'धीरे धीरे' की दृष्टियत से वहाँ का शासन मेरे हाथों में सौंप दिया गया था। मुझे पांच साथियों के साथ श्री सुभाषचन्द्र बोस ने वहाँ भेजा था। मेरे सहायक मेजर आलवी थे, जो वहाँ के शिक्षामन्त्री बनाये गये थे। लेफ्टिनेण्ट रोमासिंह अर्थमन्त्री और लेफ्टिनेण्ट इकबाल पुलिस विभाग के अध्यक्ष थे। १९४४ के दिसम्बर मास तक मैं वहाँ रहा। मेजर आलवी मेरे

स्थान में नियुक्त किये गये। अष्टमान का नाम 'शहीद द्वीप' और निकोबार का नाम 'स्वराज्य द्वीप' रख दिया गया था। फौज में स्वेच्छा से भरती की जाती थी। कभी जोर-जबरदस्ती नहीं की गई। इंग्लैण्ड और अमेरिका के दुरुद्ध नियमित रूप से युद्ध की घोषणा की गई थी। इस संघसे मलाया के हिन्दुस्तानियों को बहुत बल मिला। रंगून में आत्मसमर्पण करने से पंद्रह दिन पहिले वहाँ का सारा इलाहा हमारे आधीन था। उसमें नेताजी के आदेश के अनुसार कानून और व्यवस्था हमने ही कायम रखी थी। जापानियों ने जब रंगून पर अधिकार किया था, तब दस हजार हिन्दुस्तानी मारे गये थे। इसको रोकने और चीनी, बर्मा तथा हिन्दुस्तानी आदि सभी के जान-माल की रक्षा करने का भार हम पर था। मलाया और बर्मा में नागरिकों में से फौज के लिये भरती की गई थी।

सरकारी वकील की जिरह पर श्री. लोकनाथन ने कहा कि अष्टमान और निकोबार के बारे में घोषणा टोकियो से की गई थी और मैं सुमाप यावू से अधिकार-पत्र लेकर वहाँ गया था। जापान सरकार का पत्र भी मुझे साथ ले जाने को दिया गया था। मैं प्रतिमास अपनी रिपोर्ट कोई और प्रबन्ध न होने से जापानियों की मार्फत भेजा करता था। पहिले मुझे वहाँ का चीफ कमिश्नर और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। स्कूलों के लिये जापान सरकार से रुपया उधार लिया जाता था। अनुमान से ३० से ३३ तक स्कूल खोले गये थे। वहाँ की आन्तरिक व्यवस्था पर प्रतिमास तीन हजार तक खर्च किया



जाता था। पोर्ट ब्लेयर में मार्च १९४४ में समारोह किया गया था। पुलिस का महकमा हमारे हाथ में न दिये जाने से हमने अन्य महकमे भी अपने हाथ में नहीं लिये। जब यह महकमा देने को जापानी अधिकारी तय्यार हुये, तब मुझे नेताजी का उनको मिलने का तार मिला। उन्होंने यहां के समाचार जानने के लिये मुझे बुलाया था। गुप्तचरी के लिये जापानी पुलिस का महकमा अपने हाथ में रखना चाहते थे। वहां से भेजी गई रिपोर्टों पर कुछ सुवाल पूछने के बाद सरकारी वकील ने पूछा कि क्या आजाद हिन्द फौज में भरती करने के लिये रिश्वत का सहारा लिया जाता था? श्री लोकनाथन ने कहा कि नहीं। इसी प्रकार इसी निमित्त से कंसन्ड्रेशन कैम्प में ले जाये जाने, मारपीट करने, खड़े रखने आदि की ज्यादतियों के काम में लाये जाने से भी आपने इनकार किया मारपीट की और कहा कि एक घटना मुझे मालूम हुई थी। उसकी जांच की गई थी। २४ अप्रैल १९४४ में पन्द्रह दिन तक रंगून शहर पर हमारा अधिकार रहा। सुभाष बाबू के रंगून से विदा होने पर मुझे बर्मास्थित आजाद हिन्द फौज का सिपहसालार बना दिया गया था। सुभाष बाबू के जाने और अंग्रेज सेनाओं के आने तक रंगून की सारी व्यवस्था हम लोगों के हाथों में रही।

सफाई के आठवें मग्राह रंगून के लकड़ों के व्यापारी और आजाद हिन्द बैंक के डाइरेक्टर श्री दीनानाथ थे। आपने कहा कि मैं आजाद हिन्द संघ का सदस्य था। बैंक के चेयरमैन थी ऐस० ए० अय्यर थे और डाइरेक्टर थे—एस० एस० चट्टोप,;

एच० आर० बेताई ए० ऐस० माथा, कर्नल अलगप्पन और मैं। रंगून में नेताजी फण्ड कमेटी, भी कायम की गई थी। रंगून बैंक में और सरकार के अर्थविभाग के यहाँ भी जमा किया जाता था। बर्मा में पन्द्रह करोड़ से अधिक और मलाया में लगभग पाँच करोड़ चन्दा जमा किया गया था। बैंक की रंगून शाखा में ३०-४० लाख तक जमा रहता था। अँग्रेजों ने जब बैंक बन्द किया तब आजाद हिन्द फौज का उसमें ३५ लाख रुपया जमा था, ५० बर्गमील क्षेत्रफल और १५ हजार आबादी की जियाबाड़ी रियासत में आजाद हिन्द सरकार की हकूमत थी। वहाँ एक चीनी की बड़ी मिल भी थी। उसकी सारी आमदनी सरकार को मिलती थी। आजाद हिन्द सरकार के निर्णयों को पूरा करने का काम आजाद हिन्द संघ करता था। प्रत्येक शाखा में अनेक विभाग थे। इनमें अर्थविभाग, रंगरूढ-विभाग, आन्दोलन विभाग, स्वास्थ्य-विभाग हवाई हमला सुरक्षा विभाग, महिला विभाग और बालचर-विभाग मुख्य थे। जो लोग अपनी जायदाद छोड़ कर भाग गये थे, उनकी जायदाद की रक्षा का काम भी मुख्य था। बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बर्मा में हिन्दुस्तानियों के जानमाल की हिफाजत करने का भी काम किया गया। जापानी फौजी पुलिस जरा से भी सन्देह या सहाने पर हिन्दुस्तानियों को गिरफ्तार करती और तड़क करती थी। इससे भी उनकी रक्षा की गई।

जिरह करने पर आपने कहा कि यदि जापानी किसी की जायदाद बगैरः जब्त करना चाहते थे, तो उसकी भी आजाद

हिन्दू सरकार रक्षा करती थी। अप्रैल १९४४ में एक रंसद बोर्ड फौज की जरूरतें पूरी करने के लिये बनाया गया था। श्री ए० हवीय इसके प्रधान थे और सर्व श्री खन्ना, वेताई, विद्यानी, राधवन दाद, सहगल, सरकार, मैं, अर्थमंत्री थे संघ के प्रधान और संघ के प्रधानमन्त्री इसके सदस्य थे। जून १९४४ में मैंने सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। रंगून में बैंक की रजिस्ट्री को गई थी और उसके हिस्सेदार भी थे। ५० लाख की पूंजी थी। लोगों को और सरकार को रुपये पर व्याज दिया था। सरकार का रुपया अर्थमन्त्री के नाम पर जमा किया जाता था। फौज का खाता अलग था। बैंक के खुलते ही अप्रैल १९४४ में यह खाता खोला गया था। सारा रुपया जापानी नोटों में था। अंग्रेजी नोट और सिक्के भी थे। ये ५०-६० हजार के करीब के थे। लोगों का ३०-४० लाख तक रुपया जमा रहता था। अर्थमन्त्री के नाम पन्द्रह लाख से एक करोड़ तक रुपया जमा रहता था। दस से तीस लाख तक हर मास अर्थमन्त्री के नाम से रुपया उठाया जाता था। सबसे बड़ी रकम उसके नाम पर एक घार सय करोड़ तक पहुँच गई थी। फौज के नाम पर सबसे बड़ी रकम तीस लाख तक की थी। दूर स्थानों से कुछ रकमें सीधे अर्थ-विभाग को भेज दी जाती थी। बर्मा में जनवरी १९४४ से अप्रैल १९४४ के बीच १५ करोड़ से अधिक रुपया चन्दे में जमा हुआ था। मैं १ जून १९४५ तक रंगून में रहा। उसके बाद मैं गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान लाया गया। अंग्रेजों के रंगून आने पर जय बैंक बन्द किया गया उससे पहिले ५ मई को आजाद हिन्द फौज का

३५ लाख रुपया उसमें जमा था। ७-८ मई को हाइरेक्टरों की सभा में मैनेजर ने सारा हिसाब पेश किया था। १६ मई को बैंक बंद कर दिया गया था। हमने यह ऐलान कर दिया था कि जो चाहे बैंक से अपना रुपया उठा ले और मैनेजर को इस धारे में पूरा अधिकार दे दिया गया था। आजाद हिन्द फौज के लोग फिर भी अपना रुपया बैंक में भजते रहे। उनके लिये दूसरा कोई धारा न था।

जियाबादी रियासत के कागजात मैंने नहीं देखे। श्री परमानन्द नाम के एक सज्जन उसके मालिक थे। वह मालिक थे या मैनेजर,—यह मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं। पर, उसने ही उसको आजाद हिन्द सरकार के हाथों में दिया था। नेताजी की अपील पर एक सभा में उसने इसके देने की घोषणा की थी। उसको कुछ समय के लिये रसदमन्त्री बनाया गया था। सरकार का एक प्रतिनिधि उस रियासत का प्रबन्ध करता था और चीनी मिल की सारी आमदनी सरकार के नाम पर बैंक में जमा की जाती थी।

नये गवाह शिवसिंह ने कहा कि मैं आजाद हिन्द फौज में अगस्त १९४३ से अप्रैल १९४५ तक रहा था। मैं वहां एक सैनिक स्कूल का अध्यक्ष था। वहां की आबादी १५ हजार के लगभग थी। वहाँ एक मुर्गीखाना और एक सैनिक अस्पताल भी था। आहत और निष्क्रिय लोगों के लिये भी वहाँ आश्रय घर बनाये गये थे। चीनी कल और 'आजाद हिन्द दल' का भी बड़ा दफ्तर वहाँ था। लैफ्टिनेन्ट विटलराय इस दल के मुखिया थे।

श्री घोष पी० हल्ड्यू० डी० के अध्यक्ष थे। इस प्रदेश से जापानियों या बर्मियों को कोई वास्ता न था। बर्मी व जापानी सरकार में गलतफहमी पैदा होने पर हमारी सरकार उसकी रफा-दफा करती थी। अधिकृत क्षेत्र के नामजद गवर्नर जनरल चैटर्जी का हेडक्वार्टर यहाँ ही था। जिरह करने पर श्री शिवसिंह ने कहा कि जनवरी १९४१ में मैं ईपोह में युद्ध-बंदी बनाया गया था। अपनी फौज और सरकार कायम होने पर अगस्त १९४२ में मैं उसके साथ हो गया। जंगल में अंग्रेजों द्वारा अकेले छोड़ दिये गये फौजियों के भले के लिये मैंने ग्राइफास्ट किया था कि वे सुरक्षित स्थान में आ जाय। मैंने उनसे जापानियों का साथ देने को नहीं कहा था। मार्च १९४२ में सिंगापुर में मैं मोहनसिंह से मिला था। ईपोह से कुआलालम्पूर, सैगोन और बिदादरी, आदि भेजे जाने, जून १९४२ में बंगकौक सम्मेलन में शामिल होने, वहाँ से सिंगापुर जाने और सितम्बर १९४२ में सिंगापुर आने का वर्णन करते हुये आपने कहा कि फौज में शामिल हो जाने पर भी मैंने तब तक उसके लिये काम नहीं किया, जब तक कि जापानी सरकार ने हमारी फौज और सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं कर लिया था। अक्टूबर १९४४ में अराकान और सिंगलाहौन कैम्प में भेजे जाने के बाद १९४३ के जनवरी मास में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल गिल के सभी साथी गिरफ्तार कर लिये गये थे। एक महीने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। सितम्बर १९४३ में मैं आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ। उसकी जो थोड़ी-बहुत सेवा मैंने की, उसका वर्णन

मैं तब करूंगा, जब मुझ पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जायगा। यफ्तान मारुन को आज्ञा द हिन्द फौज ने गिरफ्तार किया था। जियावाड़ी, वहाँ की फौज और सरकारको हवाई हमले आदि से बचाने के लिये मैंने चालाकी से काम लिया और बर्मा लोगों में यह फैला दिया कि वहाँ कोई फौज बगैर नहीं है। केवल अस्पताल ही है। मैंने कोई समाचार अंग्रेजों को नहीं दिये न मैंने हिन्दुस्तान को भाग निकलने की कोशिश की और न मुझे उनसे एक हजार रुपया ही मिला। जियावाड़ी रियासत और चीनी मिल का परमानन्द मैंने जर था। वहाँ एक महल भी है और उसके राजा अब भी हिन्दुस्तान में जीवित हैं। जियावाड़ी बर्मा में है। जून १९४४ में बर्मा में जापानियों का अधिकार था। आजाद हिन्द सरकार के साथ यह तय हो गया था कि जिस जायदाद के हिन्दुस्तानी मालिक उसको छोड़ कर भाग गये हैं वह उसको सौंप दी जायगी। सफाई के वकील के पूछे जाने पर श्री शिवसिंह ने कहा कि सेगौन में मुझे कर्नल सेंटो ने बतलाया था कि जापान समस्त पूर्वी एशिया की आजादी के लिये लड़ रहा है। उसमें हिन्दुस्तान भी शामिल है।

भारत सरकार के कामनवेल्थ रिलेशन्स विभाग के श्री नन्द ने बताया कि युद्ध से पहिले हिन्दुस्तानियों की संख्या बर्मा में १०१७८२५, मलाया में ८ लाख, थाईलैण्ड में ३५००० हिन्द चाहना में ६००० हांगकांग में ४७४५, डच ईस्ट इण्डोच में २७००६, फ्रेंच हिन्द चीन में ६००० और जापान में ३०० थी। जिरह में आपने बताया कि जापानी युद्ध-घोषणा के बाद केवल

५४ हिन्दुस्तानी जापान में रह गये थे । अन्य देशों से कितने हिन्दुस्तानी चले आये थे—इसका कुछ भी पता नहीं ।

जापान सरकार से प्राप्त किये गये कुछ कागजों में जमुना क्षेत्र के फौजी सदर मुकाम के लैफ्टिनेण्ट कर्नल ई० के० ने पेश किये । उसने जनरल इसनेहोवर और जर्मन रेडियो के कुछ प्रोडकास्ट भी पेश किये, जो शिमला में दर्ज किये गये थे ।

सफाई के अन्तिम और दसवें गवाह कप्तान आर० एम० अरशाद ने अपने लम्बे बयान में बताया कि अंग्रेजों द्वारा किये गये आत्मसमर्पण के समय में सिगापुर में था । फरेर पार्क में कर्नल इण्ट द्वारा किये गये आत्मसमर्पण, मेजर फूजीयारा के आपराध और कप्तान मोहनसिंह की आजाद हिन्द फौज के लिए की गई अपील का विस्तार से उल्लेख करने के बाद आपने बताया कि उस समय युद्धबन्दी बनाये गये हिन्दुस्तानियों की संख्या ४५ से ५० हजार तक थी । जुलाई १९४२ के अन्त में आजाद हिन्द फौज में मैं शामिल हुआ था । इस मामले में अभियुक्त बनाये गये तीनों अफसरों को मैं जानता हूँ । आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के समय मेरे सामने कई सवाल पैदा हुये । अपनी शिक्षा और बाद में अपने फौजी जीवन के कारण मैं राजनीति से दूर रहा । मैं गहरी चिन्ता में पड़ गया । अनजान लोगों से इस बारे में चर्चा करने में कुछ संकोच था । लेकिन मैं इस बारे में खूब गहरी चर्चा करना चाहता था । सिगापुर में माउण्ट प्लेसेण्ट पर मैं कप्तान मोहनसिंह के सदर मुकाम के पास ही रहता था । कप्तान सहगल के साथ मेरा बारह-तेरह वर्ष पुरानी परिचय था । मिलीज

नहीं, सभी हिंदुस्तानियों की है। उसे कप्तान मोहनसिंह भंग नहीं कर सकते। अफसर सब, कप्तान मोहनसिंह के साथ थे। श्री रासबिहारी बोस ने फौज के सदर भुसाम में आकर अपने हस्ताक्षरों से निकाला गया कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारी का हुक्म पढा। कार्यसमिति के अधिकांश सदस्यों ने भी इस पर स्तीफे दे दिये।

हमने अपने को युद्ध-बंदी मानना शुरू कर दिया, पर जापानी सहमत न हुये। उन्होंने कहा कि हमने तुमको आजाद कर दिया है। बिना किसी अपराध के हम तुमको गिरफ्तार नहीं कर सकते और न हमारी दृष्टि में 'फौज ही अमी भग हुई है। अफसरों और श्री रासबिहारी बोस में अनेक बार चर्चा हुई। कभी कभी कर्नल इवा कुछ भी हाजिर रहते थे। जापानियों के व्यवहार पर हमने अपना असन्तोष प्रगट किया और बगकौर के प्रस्तावों को मंजूर करने पर जोर दिया। एक बार तो हमने बेतन लेने से भी इनकार कर दिया। कुछ समय बाद कुछ रद्दोबद्दल करके फौज को जारी रखने का निश्चय किया गया। दो विभाग बनाये गये और दोनों के बीच अलग अफसर नियुक्त किये गये। भरती सर्वथा स्वेच्छा में करने और पब्लिश भरती हुये लोगों को भी अलग होने का अवसर देने का निश्चय लिया गया। अंग्रेज सेना के ढग पर फौज के कई विभाग बनाये गये। फौज के लिये जोर-जबरदस्ती किये जाने की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है।

कप्तान शाह नवाज खाँ को भी जापानियों के प्रति सन्देह



था। वे भी कनज इवा कुरु के साथ होने वाली चर्चा के समय उपस्थित रहते थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को टोकियो से बुलाने पर उन्होंने जोर दिया। जुलाई १९४३ में वे सिंगापुर आ गये। २१ अक्टूबर १९४३ को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई। सुभाष बोस 'राष्ट्रपति' बनाये गये और अगस्त से उनको फौज का सिव्हासालार भी बना दिया गया। अनिच्छुक लोगों से उन्होंने यह कहते हुए फौज से अलग हो जाने को कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा के विरुद्ध मेरी कमान में रहे। १९४४ के शुरू में आजाद हिन्द सरकार का दफ्तर रंगून आ गया। फरवरी में पहिली डिविजन का सहर मुकाम भी रंगून में आ गया। इसी डिविजन के कुछ और यूनिट भी यहां आ गये। अधिकृत प्रदेश श्री शासन-व्यवस्था के लिये संगठित किए गये 'आजाद हिन्द डल' और सिंगापुर तथा रंगून में उनकी शिक्षा के लिये स्थापित किये गये स्कूलों का उल्लेख करने के बाद गवाह ने कहा कि मार्च-अप्रैल १९४४ में मैं इन्काल के मोर्चे पर गया था। यहाँ अधिकृत प्रदेश पर हमारा अधिकार था। इस प्रदेश में प्रवेश करने पर नेताजी और जापानी सेनापति की घोषणायें पढ़ी गईं। उनमें कहा गया था कि विजित प्रदेशों पर आजाद हिन्द सरकार का अधिकार रहेगा। मैं मणिपुर की ओर भी गया था। अप्रैल में मुझे मांडले बुला लिया गया। जुलाई में फिर इन्काल भेजा गया। डिविजन नं० १ के कमांडर मेजर एम० जेड० कियानी अधिकृत प्रदेश की शासन-व्यवस्था

कर रहे थे। विशनपुर के कुछ क्षेत्र पर हमारा अधिकार था। मोर्चे से पलेल तक कोहिमा खिचिजन में लगभग १५ हजार वर्गमील का यह क्षेत्र था।

रंगून के खाली किये जाने, सुभाष बाबू के वहां से विदा होने, अफसरों के साथ उनकी अन्तिम चर्चा होने, कर्नल लोकनाथन के सेनाध्यक्ष बनाये जाने और हिन्दुस्तानियों के जान-माल एवं सम्मान की रक्षा करने तथा मित्र-सेनाओं के सामने युद्ध-बन्दी के रूप में आत्म-समर्पण करने के नेताजी के आदेश की चर्चा करने के बाद कप्तान अरशाद ने कहा कि २४ अप्रैल को जापानियों ने रंगून से अपनी सारी सेनाएँ हटा ली थीं और बर्मा सेना भी वहां नहीं थी। केवल आजाद हिन्द फौज के पांच-छः हजार फौजी वहां रह गये थे। मैंने शहर की सभ्य व्यवस्था संभाल ली। बर्मा सरकार का प्रबानमंत्री तो रंगून में था, किन्तु उसके पास पुलिस बगैर नहीं थी। मैं उसके पास गया। मैंने उसको अपनी सारी व्यवस्था समझाई और उसने हमें अपना काम जारी रखने को कहा। दूसरे दिन उसने अपने चीफ पुलिस अफसर को मेरे पास भेजा, जिसके साथ मैंने शहर की व्यवस्था के बारे में बातचीत की। चावल के डिपो तथा अन्य गोदामों को भी जापानी मुला ही छोड़ गये थे। शहर में अशान्ति होने की भी आशंका थी। हमने अपने रातरो तैनात किये। बर्मा-मन्त्रिमण्डल के सामने भी मैंने अपनी व्यवस्था का व्यौरा पेश किया। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। २५-२६ अप्रैल को मुझे पता चला कि सेरटूस जेस में सबसे बड़े अफसर रादर

ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के विंग कमाण्डर ऐल० हडसन भी हैं। मैं तुरन्त उनके पास गया। सत्र कार्य का व्यौरा उनको बता कर मैंने उनके सामने अपने और आजाद हिन्द फौज के आत्मसमर्पण करने की बात कही। उन्होंने हमें अपना कार्य जारी रखते हुये रोज सवेरे मिलते रहने के लिये कहा। चर्मा डिफस अर्मी भी एक आदमी मुझ से मिला। आजाद हिन्द फौज के धारे में मैंने उसको बताया कि हमारा इरादा रंगून की विभाजित करने और अंग्रेज सेना के आने पर उसके सामने आत्मसमर्पण करने का है। उसने कहा कि हमारा भी यही इरादा है और हमारा अंग्रेज सेना के साथ सम्बन्ध है। मैं उसको हडसन के पास ले गया। उसने उस पर मरोसा न करके लिखित प्रमाण पेश करने को कहा। लेकिन, वह ऐसा कोई प्रमाण-पत्र पेश न कर सका। हडसन के कहने पर हमने अपना काम जारी रखा। रंगून के खाली किये जाने पर भी मित्र हवाई जहाज आकाश में आते और धम धरसाते थे। मैंने हडसन से इसकी शिकायत की। उसने कहा कि क्या किया जाय और कैसे मित्र सेना के कमाण्डर को इसकी सूचना दी जाय? मैंने उनको एक क्रांसमीटर ला दिया। वे उसका उपयोग न कर सके।

३ मई को मुझे पता चला कि भिंगलाखान के कैम्प कमाण्डर ने एक अंग्रेज हवाई जहाज को संकेत करके नीचे उतार लिया है। यह स्थान रंगून से १२ मील पर है। मैंने उसको हडसन के पास ले जाने का आदेश दिया। हडसन से मुझे पता चला कि ४ मई को रंगून पर घातका हमला होने को था। उसको रोकने

के लिये आजाद हिन्द फौज का एक अफसर उस हवाई अफसर  
 के साथ रंगून नदी के मुहाने पर भेजा गया। वहाँ हवाई बेड़े को  
 संकेत से बताया गया कि रंगून खुला शहर है। हडसन  
 के साथ हुये पत्र-व्यवहार में से अनेक पत्र पेश करते हुए गवाह  
 ने आगे कहा कि ४ मई को लाउडर की कमान में अंग्रेज सेना  
 रंगून में उतरी। ११ मई को उसका पत्र मिलने पर मैं उसके पास  
 गया। अपने सारे कार्य का परिचय देते हुये मैंने कहा कि हम  
 धीरे-धीरे युद्ध-बन्दी के आत्म-समर्पण करने को तैयार हैं। उसने  
 शस्त्रास्त्र सौंप कर सैनिकों को अपने कैम्पों में ही रहने का  
 आदेश दिया। दूसरे दिन कर्नल लोकनाथन के साथ फिर मैं  
 उसके पास गया। हमें उसने युद्ध-बन्दी बनाने से इनकार करते  
 हुए कहा कि हिन्दुस्तान लौटने तक उनको आजाद हिन्द फौज  
 में ही रहना होगा। लेकिन सबको सेण्ट्रल जेल और इनसीन  
 जेल में आ जाना होगा। जेल पर "आई० एन० ए० कैम्प" का  
 बोर्ड भी लगा दिया गया था। जेल पर हमारा ही पहरा था। हमें  
 कहा गया था कि भीतरे किसी भी प्रकार की रोक-टोक न होगी।  
 कर्नल लोकनाथन ही कमाण्डर रहेंगे और वे ही सारी व्यवस्था  
 करेंगे। विल्ले भी इसलिये उतारजे होंगे कि उनको मित्र-सेना से  
 माध्यता नहीं दी है और उनको लगाने पर मित्र-सेना के अफसरों  
 का सम्मान न करेगी। इससे कुछ असान्ति पैदा होने का भय है।  
 १३ मई तक ऐसा ही क्रम रहा जब कि आजाद फौज की पहिली  
 टुकड़ी हिन्दुस्तान भेजी गई। हमने लाउडर के कहने पर सब  
 सन्धारित्र इकट्ठे कर दिये और पहरे देना भी बन्द कर दिया।



खाल किले में—मुखेश सिंहासिंह, फतेसिंह तथा अन्य सपरवा।

दूसरे दिन लाउडर ने मेरे बंगले पर आकर टांगयांगयान में, पहरा जारी रखने को कहा। रंगून से ७० मील पर यह हिन्दुस्तानी बस्ती थी और वहां पहरा हटाते ही दो हत्याएं हो गई थीं। हमने वहां मित्रसेनाओं के पहुंचने तक पहरा दिया।

जिरह किये जाने पर कप्तान अरशाद ने कहा कि हमें वेतन जापान की ओर से न दिया जाकर आजाद हिन्द संघ में दिया जाता था। पहिली बार वेतन हमें त्रितम्वर में दिया गया था। आजाद हिन्द फौज के पहिली बार भंग किये जाने पर जब हमने वेतन लेने से इनकार किया, तब श्री रासबिहारी घोस ने कहा कि यह वे अपने पास से दे रहे हैं। इसके लेने पर उन पर कोई ज़िम्मेवारी नहीं आयेगी। जापानियों का युद्ध-बंदियों के प्रति व्यवहार अक्रान्ता न था। वे अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की भी परवा न करते थे। लेकिन, उन्होंने कोई जुल्म या ग्यादती नहीं की। अनेक प्रश्नों के 'नहीं' में उत्तर देते हुये कप्तान अरशाद ने कहा कि आजाद हिन्द फौज में भरती सर्वथा स्वैच्छा से होती थी। कप्तान मोहनसिंह को गिरफ्तार करने का मतलब जी. ओ. सी. के पद से हटाना था। मुझे मालूम नहीं कि उनको सिंगापुर से कहां ले जाया गया। अप्रैल १९४४ में हम मणीपुर पहुंचे थे। मणीपुर में जम्मू-इम्फाल-रोड पर हमारी फौज लड़ रही थी। पलेल पर हम हमला कर रहे थे। उसको हम ले नहीं सके। यहां से हमने पीछे हटना शुरू किया। अधिष्ठित प्रदेश के सम्बन्ध में रिपोर्टें और हिदायतें बराबर आया-जाया करती थीं।

१ मई १९४५ को रंगून पर अधिकार करने की घोषणा बर्मा डिफेंस आर्मी ने की थी; किन्तु यह ठीक न थी।

कप्तान आर० एम० अरशाद के लम्बे वयान के साथ १३ दिसम्बर को सफाई के गवाहों की गवाहियां समाप्त हो गईं। आजाद हिन्द फौज की भांसी की रानी रेजीमेण्ट की कप्तान डाक्टर लक्ष्मी और दो जापानी अफसरों की गवाहियां सफाई पक्ष की ओर से पेश नहीं की गईं। जापानी अफसर हिन्दुस्तान लाये जा चुके थे।

सरकारी वकील ने अपना वक्तव्य देने के लिये अदालत से मोहलत मांगी। सफाई के वकील श्री वेसाई ने कहा कि उन को इसमें आपत्ति नहीं है, उनके वक्तव्य के बाद मोहलत दी जाय, तो ठीक रहे। किन्तु वे अपना वक्तव्य मौखिक ही देंगे। उसकी लिखित प्रति वे अदालत में पेश न कर सकेंगे। अदालत १७ दिसम्बर के लिये उठ गई।

## आजादी के लिये युद्ध का अधिकार

१७ और १८ दिसम्बर १६४५ को सफाई में दिया गया श्री भूलाभाई देसाई का लम्बा वक्तव्य हमारे इतिहास का एक अमर पृष्ठ बन गया है। इस घण्टों तक दिया गया धाराबाही मौखिक वक्तव्य श्री देसाई की प्रतिभा, योग्यता और विद्वता का सूचक तो था ही, किन्तु उसमें पराधीन तथा पदचलित राष्ट्रों के आजादी के लिये युद्ध करने के अधिकार की भी जबरदस्त पहस की गई थी। इसी से उसका महत्व इतना बढ़ गया है कि उसका उल्लेख चिरकाल तक किया जाता रहेगा।

श्री भूलाभाई देसाई ने कहा, कि सरकार की ओर से इस अदालत के सामने पेश की गई गवाहियों को ऊपरी तौर पर देखने से पता चलता है कि अभियुक्तों पर दो अभियोग लगाये गये हैं। पहिला अभियोग सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का और दूसरा हत्या करने या उसमें सहयोग देने का है। वस्तुतः प्रमुख



और एकमात्र अभियोग सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का ही है। हत्या का अभियोग इसी के अन्तर्गत है। किसी पर सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाये जाने के बाद उस पर उस युद्ध में गोली दागने के अभियोग का हर बार अलग से उल्लेख करना हास्यास्पद है। उन बातों पर, जो उक्त अभियोग के प्रमाणस्वरूप कही गई हैं, मैं पहिले बहस करूँगा। बाद में यह भी सिद्ध करूँगा कि हत्यासम्बन्धी अभियोग सर्वथा निर्मूल है। जिन चार व्यक्तियों को गोली से उड़ा देने की बात कही गई है, उनके सम्बन्ध में प्राप्त दस्तावेजों से केवल इतना ही पता चलता है कि उन पर मामलों चलाया जाकर उन्हें प्राणदण्ड की सजा केवल सुनाई ही गई थी। मुहम्मद हुसैन की सजा के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। इस सिलसिले में, उपस्थित किये गये प्रमाणों से मैं यह सिद्ध कर दूँगा कि चार व्यक्तियों में से केवल एक ही को प्राणदण्ड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह भी कभी कार्यान्वित नहीं हुई। यही इस अभियोग का वास्तविक स्वरूप है, जिसका अदालत के सामने लाका खीचना मेरे लिये आवश्यक है।

सब घटनाओं पर विस्तार से बहस करने के पहिले मैं एक-दो बातों की ओर अदालत का ध्यान खीचना जरूरी समझता हूँ। फौजी अदालत के सामने साधारण तौर पर पेश होने वाले मामलों से यह मामला असाधारण कोटि का है। उसके सामने साधारणतया व्यक्तिगत रूप से कर्त्तव्य पालन करने में त्रुटि करने अथवा अनुरासन भंग करने के

अपराधों की ही सुनवाई होती है। मैं यह साहस के साथ कहता हूँ और स्वतंत्र मेरे इस कथन का समर्थन करता है। यह केवल तीन व्यक्तियों का मामला नहीं है, जिन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया है। सरकारी गवाहियों से ही यह प्रकट है कि अदालत में 'जिन तीन' व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है, वे एक बाकायदा संगठित सेना के, जिसने सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, सदस्य थे। अतः इस मामले के रूप में न केवल कुछ व्यक्तियों के कार्यकलाप का, अपितु समूची आजाद हिंद सेना के विधान और मानमर्यादा का निर्णय होने जा रहा है। साथ ही आज अदालत के सामने यह प्रश्न भी उपस्थित है कि एक गुलाम कौम को अपनी भुक्ति के लिये युद्ध लड़ने का अधिकार है कि नहीं ? मैं अन्तराष्ट्रीय विधान विरोधियों के सर्वमान्य विचारों को पेश करके यह सिद्ध करूँगा कि कोई भी राष्ट्र अथवा उस राष्ट्र का कोई भाग ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है, जब उसको अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए युद्ध करने का पूरा अधिकार हो जाता है। इस मामले के सम्बन्ध में एक और बात भी उल्लेखनीय है, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। इसके लिए स्वभावतः काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है। सार्वजनिक तथा सरकारी दृष्टिकोणों से भी अनेक बड़े बड़े लोग भी, जिनमें भारत के वायसराय से लेकर अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं, इस मामले के पक्ष और विपक्ष में राय जाहिर कर चुके हैं।

इस मामले के सम्बन्ध में अब तक जो बातें मालूम हो सकी हैं, उनको सिलसिलेवार थोड़ी में अदालत के सामने

मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। बाद में उनपर मैं कानूनी दृष्टि से सहस्र करूँगा। अन्यथा उपलब्ध प्रमाणों को, जो लगभग चार सौ सफों में भरे पड़े हैं, यहां विस्तार के साथ उद्धृत कर मैं अदालत को व्यर्थ फट देना नहीं चाहता। मैं केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ही पेश करूँगा। दिसम्बर १९४१ में जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं, जो इस अदालत के सामने विवाद का विषय बन गई हैं। १९४२ फरवरी १९४२ को ब्रिटिश फौजों ने सिंगापुर में जापानियों के हाथों में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके दो दिन बाद १७ फरवरी को फरेर पार्क में, जो घटना घटी, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाद की घटनाओं में आजाद हिन्द फौज की स्थापना का महत्व बहुत अधिक है, जो १९४२ के सितम्बर मास में स्थापित की हुई थी। दिसम्बर १९४२ में यह भंग कर दी गई और उसके नेता कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद की घटनाओं में दुबारा आजाद हिन्द फौज की स्थापना के लिये किये गये प्रयत्न विशेष महत्व रखते हैं। २३ जुलाई १९४३ को श्री सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर पहुंच गये और उन्होंने आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। इसी समय यहां एक बृहत्तर पूर्वी एशिया की परिषद् हुई, जिसमें सुदूर पूर्वीय देशों के विभिन्न स्थानों से हिन्दुस्तानी आजाद हिन्द संघ ( इण्डियन नेशनल लीग ) के प्रतिनिधि होकर आये थे। इस परिषद् में स्वीकृत प्रस्तावों में से एक यह था कि आजाद हिन्द की एक अस्थायी सरकार स्थापित की जाय।

२१ अक्टूबर १९४३ को अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा की गई, जिसको मैं इस मामले की फार्वार्ड में, सुविधा की दृष्टि से, "अस्थायी सरकार" कहूंगा। अस्थायी सरकार की स्थापना के बाद ही उसके मन्त्रियों ने वफादारी की शपथ ली। इसी सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। आजाद हिन्द फौज ने इसी सरकार के आधीन अपना कार्य आरम्भ किया। बाद की घटनाओं में तीन सप्ताह से महत्त्व की हैं। अस्थायी सरकार का सिंगापुर से रंगून को प्रस्थान पहिली घटना है। बर्मा से भारत की सीमा अर्थात् कोहिमा तक आजाद हिन्द फौज का कूच करना, फिर पीछे हटना तथा ब्रिटिश सेनाओं का रंगून पर कब्जा हो जाने पर उत्पन्न हुई स्थिति शेष घटनायें हैं, जो अत्यन्त महत्त्व की हैं। प्रस्तुत मामले के सम्बन्ध में यही चन्द निर्विवाद घटनायें हैं, जो इस अदालत के लिये विचारणीय हैं। इन सब घटनाओं का सर्वप्रथम निष्कर्ष, जिसे स्वीकार करने के लिये मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ, यह निकलता है कि अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना और घोषणा विधिवत् हुई थी। मेरे मत से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस विषय पर जितनी चार जिरह हुई है, उसमें इसके विरुद्ध स्पष्ट रूप से कोई भी संकेत नहीं मिला। अदालत से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करते समय अस्थायी सरकार के घोषणापत्र एवं अन्य प्रमाणों को अवश्य याद रखा जाय। इसी लिये मैं सब से पहिले इस घोषणा-पत्र की ओर, जिसकी

मूल प्रति यहां उपस्थित की गई है, आंदोलन का ध्यान रखेंगे।

इसके बाद श्री भूलाभाई देसाई ने आजाद हिन्द सरकार के घोषणा-पत्र की निम्न अंश पढ़ कर सुनाये—“सन् १९५० में अंग्रेजों ने भारतीय जनता को बलपूर्वक निःशस्त्र कर आतंक तथा क्रूरता से उनको गुलामी में जकड़ दिया। कुछ दिनों तक भारतीय जनता दबी पड़ी रही। सन् १९६५ में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद से लेकर प्रथम महायुद्ध के दिनों तक भारतीयों ने प्रचार कार्य, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, आतंकवाद, तोड़फोड़ तथा सशस्त्र क्रांति से अपनी खोई हुई स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया। इन सभी दिशाओं में वह असफल रही। अंत में सन् १९५० में, जब कि बार-बार की अपनी असफलता ने असंतुष्ट भारतीय जनता स्वाधीनता प्राप्ति के नये साधनों की खोज में व्यस्त थी, महात्मा गांधी असहयोग और सर्वनय अवज्ञा आन्दोलन का नया अस्त्र लेकर आगे बढ़े। अंत में बाद महायुद्ध के श्रीगणेश का अवसर उपस्थित होने के साथ ही साथ भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के निमित्त आन्दोलन छड़ने के लिये आवश्यक भूमिका तैयार हो गई। इस युद्ध काल में जर्मनी अपने मित्रों की मदद से हमारे शत्रु पर कठोर प्रहार करता रहा है और इससे भी कठोरतम प्रहार पूर्वी एशिया स्थित जापान हमारे शत्रु पर अपने मित्रों की मदद से करता रहा है। अतः ही भारतीयों को अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिये यह स्वर-अवसर प्रतीत हो रहा है। आधुनिक इतिहास में

आज पहली ही बार प्रवासी भारतीयों में भी राजनीतिक जागृति पैदा हुई और वे सब एक संगठन-सूत्र में बँध गये। भारत स्थिति अपने देशवान्धवों की भावनाओं के साथ केवल उनकी भावना में एक-रूप हो गई है, अपितु वे उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कर स्वाधीनता-प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। खास कर पूर्वी एशिया में २० लाख से अधिक भारतीय एक सुदृढ़ संगठन सूत्र में बँध गये हैं।”

यहाँ पर कुछ रुककर श्री मूलाभाई ने कहा कि “इस उद्घरण को पेटा करने का यह अभिप्राय है कि यह सरकार ऐसी सरकार नहीं थी, जिसे आप अथवा मेरा विरोधी पक्ष विद्रोहियों का दल अथवा असफल व्यक्तियों का मुन्ड कह सके।” इसके बाद श्री देसाई ने घोषणा-पत्र में से फिर पढ़ना शुरू किया कि “ब्रिटिश सरकार ने कपट नीति से भारतीय जनता को तबाह कर और लूट खसोट से उन्हें भूखे मारकर अपने प्रति भारतीय जनता की भद्रा को खो दिया है। अब उसका अस्तित्व अनिश्चित सा बन गया है। ऐसी सरकार तथा उसके साथियों की भारतभूमि से जड़ उखाड़ फेंकने के निमित्त आन्दोलन छेड़ना एवं उसका संचालन करना अस्थायी सरकार का कर्तव्य होगा। आजाद हिन्द की ऐसी स्थायी सरकार की, जो भारतीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती हो तथा उसकी विश्वासपात्र हो, स्थापना करना इस अस्थायी सरकार का दूसरा कर्तव्य होगा। ब्रिटिश सरकार तथा उसके मित्रों का तत्काल संसट देने के बाद और जब तक भारत में स्थायी आजाद हिन्द

सरकार की स्थापना नहीं हो जाती, यह अस्थायी सरकार भारतीय जनता को विश्वास में लेकर देश का शासनभार संभालती रहेगी। यह अस्थायी सरकार प्रत्येक हिन्दुस्तानी के प्रति वफादार रहेगी और इस सरकार के प्रति वफादार रहना प्रत्येक हिन्दुस्तानी का फर्ज होगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्र्य, समान अधिकार तथा एक-सा सुअवसर प्रदान करने का वह जिम्मा लेती है। समूचे देश के सुख और समृद्धि के लिये, बिना किसी भेदभाव के दृढ़ता के साथ प्रयत्नशील रहने की हम घोषणा करते हैं। भगवान् के नाम पर, हमारे उन पृथ्वी के नाम पर, जिन्होंने एक-राष्ट्रीयता के सूत्र में हमें गांध दिया है तथा उन शहीदों के नाम पर जो वीरता और आत्मोत्सर्ग की परम्परा की बसीयत हमारे लिये छोड़ गये हैं; हम भारतीय जनता से अपील करते हैं कि वह हमारे मण्डे के नीचे एकत्रित होकर भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये लड़े।"

इस घोषणा-पत्र पर अस्थायी सरकार के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। अस्थायी सरकार की स्थापना का उद्देश्य क्या था तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वह किन तरीकों से काम लेना चाहती थी, यह बताने के लिये ही मैं इस दस्तावेज की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। अदालत के सामने उपस्थित मामले से, इस बात का कि यह सरकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल रही, कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात यह सिद्ध हुई है कि आजाद हिन्द सरकार एक संगठित सरकार थी। इस बात को प्रमाणित करने के लिये अधिक बहस

की जरूरत नहीं है। इस अस्थायी सरकार के मन्त्रियों के सुपुर्द जो विभिन्न विभाग थे तथा मेरे द्वारा अभी अभी उद्धृत दस्तावेज के अंत में जो अंकित हैं, उनका उल्लेख गवाहों ने अदालत के सामने दिये गये अपने बयान में किया है। गवाहों द्वारा यह भी बताया गया है कि आजाद हिन्द संध अस्थायी सरकार की शासन-परिपद् के नाते कार्य करती थी तथा उसने उन भारतीयों की रक्षा की, जो उसके प्रति वफादार रहे, युद्धजन्य परिस्थितियों में भी यथासम्भव प्रयत्न किया। गवाही में 'जो आंकड़े दिये गए हैं, उनसे यह भी सिद्ध होता है कि जून १९४४ में केवल मलाया में २३००० व्यक्तियों ने इस अस्थायी सरकार के प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी। इस संख्या को उद्धृत करने का यही अभिप्राय है कि यह अस्थायी सरकार विद्रोहियों का दल अथवा असफल व्यक्तियों का झुण्ड नहीं था, जैसा कि सम्भवतः आप या मेरे विरोधी उपहासपूर्वक समझ बैठेंगे। ऐसे झुंझाव को मैं झूठा साबित कर देना चाहता हूँ। २० लाख व्यक्ति उसके प्रति आस्था रखते थे, जिनमें से २ लाख ३० हजार व्यक्तियों ने केवल मलाया में उसके प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी।

तीसरी बात, जो अदालत के सामने सिद्ध हुई है, वह यह है कि अस्थायी सरकार को धुरी राष्ट्रों की मान्यता मिल गई थी। मैं यह बात संक्षेप में केवल इस लिये कह रहा हूँ कि कानून और लक्ष्य की दृष्टि से यह अनावश्यक है कि मान्यता विशेष प्रकार की अथवा विशिष्ट संख्या तक की सरकारों द्वारा



ही मिलनी चाहिए। मान्यता या स्वीकृति स्वयमेव एकमात्र प्रमाण है, जिससे अतिरिक्त अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकार को अपने वांछित उद्देश्य के लिए युद्ध-घोषणा करने का अधिकार है और युद्ध-घोषणा करने का अधिकार रखने वाली सरकार की सेना युद्ध-विषयक अन्तर्राष्ट्रीय विधान से बंध जाती है।

जहाँ तक अस्थायी आजाद हिन्द सरकार को जर्मनी और इटली की स्वीकृति प्राप्त होने की बात है, जिसका कोई भवाल ही नहीं उठता और न उठाया ही गया है, किन्तु पूर्वी एशिया की उन दिनों की कुछ सरकारों के सम्वन्ध में यह आक्षेप किया गया है कि वे जापान के प्रभुत्व में होने के कारण उससे प्रभावित थीं। कम से कम मैं इस बात की सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। यदि हम ऐसा समझ कर चलें कि जापान के पास साम्राज्य होता, यानी उसके द्वारा विजित प्रदेश स्वाधीन न होकर उसी की प्रभुता में रहते, तो भी आजाद हिन्द सरकार को उनसे प्राप्त होने वाली मान्यता के महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यह प्रश्न बाकी रह जाता है कि क्या केवल किसी सरकार को मान्यता मिल जाने से वह वाकायदा ऐसा राज्य बन जाती है, जो अपनी प्रजा की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये युद्ध-घोषणा एवं प्रत्यक्ष युद्ध करने की अधिकारी हो जाती है। अतः मुख्य प्रश्न है किसी भी सरकार का वाकायदा 'राज्य' की स्थिति को पहुँचने का। इस प्रकार के राज्य की युद्ध-घोषणा ही उसके अस्तित्वका स्वयंसिद्ध

प्रमाण है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि किन्हीं दो स्वतन्त्र राज्यों को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है तथा युद्ध-संचालन की दृष्टि से उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य का औचित्य स्वयं युद्ध से ही सिद्ध होता है। इस पर यह पूछा जा सकता है कि एशिया, जर्मनी तथा अन्यान्य स्थानों पर युद्ध अपराध के मुकदमे क्यों चलाये जा रहे हैं ? वास्तव में इन मुकदमों से इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि उचित युद्ध-संचालन के लिये किये गये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। सभ्य संसार के युद्ध-नियमों के अनुसार युद्ध का संचालन करने के साथ ही कुछ खास नियमों के विरुद्ध कार्य करते समय, जिन्हें अब "युद्ध-अपराध" कहने की प्रथा चल पड़ी है, कुछ व्यक्ति पकड़े गये हैं। केवल इस प्रकार के युद्ध-अपराध के लिये ही आप मुकदमे चला सकते हैं और वास्तव में चला भी रहे हैं। इससे यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि सभ्य युद्ध-संचालन के कार्यों के बारे में, जिनमें परमाणु बम का प्रयोग भी सम्मिलित है, हस्तक्षेप करने का किसी म्यूनिसिपल ट्रिब्यूनल को अधिकार नहीं है।

श्री भूलाभाई ने आगे कहा कि चौथी बात जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ और जो सप्रमाण सिद्ध हो चुकी है, वह यह है कि अस्थायी सरकार के पास सुसंगठित सेना थी, जिसके अपने विरोध पदक तथा अन्य चिन्ह थे। इसके संचालन के लिये भी वाक्यादा अफसर नियुक्त किये गये थे। सर्वप्रथम ने इन बातों को प्रमाणित कर मेरे समय की वचत की है।

अनेकानेक दस्तावेजों से उसने यह सिद्ध कर दिया है कि आजाद हिन्द फौज वाकायदा संगठित की गई थी। अब्बल तो उसका संचालन आजाद हिन्द फौज के कानून से होता था। सरकारी वकील के ज़िरह के समय किये गये सवालों से जो घात मैं समझ सका हूँ, वह यह है कि इस फौज के कानून के अनुसार कोई सम्बन्धी कुछ सजाओं में उन्हें आपत्ति है। ऐसा सोचते समय वह यह भूल जाते हैं कि ब्रिटिश भारत में इण्डियन आर्मी एक्ट भी उसी प्रकार अमल में लाया जाता है। यह सही है कि लैफ्टिनेण्ट नाग ने अदालत में कहा था कि कोड़ों की सजा के बारे में जो विधान इण्डियन आर्मी एक्ट के अन्तर्गत है, उसके अतिरिक्त भी कुछ विधान आजाद हिन्द फौज के लिये बना लिये गये थे। कुछ ही दिन पहिले इण्डियन आर्मी एक्ट के अन्तर्गत शारीरिक सजा की ४५ वीं धारा में जो अंश जोड़ दिया गया है, उसको विरोधी पक्ष सम्भवतः भूल गया है। मैं १९११ के इण्डियन आर्मी एक्ट की ४५ धारा का वह पदकर सुनाता हूँ। वह इस प्रकार है कि (१) "ऐसा कोई भी व्यक्ति या सेनाधिकारी, जिसको यह एक्ट लागू होता है; ५ वीं सेना में काम करते समय अपराधी पाया गया, (बी) किसी अन्य मौके पर धारा संख्या ३१ के "डी" नियम को भंग करने का अपराधी ठहराया गया अथवा (सी) किसी समय अन्य प्रकार से ब्रिटिश भारत में इस कानून के अनुसार दोषी पाया गया हो, तो फौजी अदालत उसे कोड़ों की सजा दे सकेगी। इस धारा से

फौजी अदालत किसी भी अपराधी को कानूनन अधिक से अधिक तीस कोड़ों की सजा दे सकती है।

यह सही है कि युद्ध-काल में यह धारा अमल में नहीं लाई गई, किन्तु ऐसा समझना कि भारतीय कानून व्यवस्था में इस प्रकार की धारा कभी यी ही नहीं, भारी भूल है। भारत रक्षा विधान और उससे सम्बन्धित आर्डिनेन्सों में तो भारतीय सेना के अपराधी व्यक्ति को कोड़ों की सजा देने का निश्चित रूप से का उल्लेख किया गया है। १९४३ के ३७ वें आर्डिनेन्स से इण्डियन आर्मी एक्ट की इस त्रुटि को दूर किया गया है। तात्पर्य यही है कि यदि आजाद हिन्द फौज के अनुसार समय समय पर दी गई शारीरिक सजायें आपकी दृष्टि में अर्धैष है, तो इस अवधि में इण्डियन आर्मी एक्ट के अंतर्गत दी गई इसी प्रकार की सजायें भी अर्धैष होनी चाहिये। वास्तव में बात ऐसी नहीं है।

एक बात और जो असंदिग्ध रूप से सिद्ध हुई है, वह यह है कि अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की घोषणा का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वाधीनता प्राप्त करना था। बर्मा तथा मलाया के भारतीयों के जान-माल एवं मान-सम्मान की युद्धजन्य संकटकाल में यथासम्भव रक्षा करना उसका दूसरा उद्देश्य था, जो कुछ अंशों में गौण है।

पांचवीं बात जो स्वीकार नहीं की गई है, किन्तु जो अदालत में संप्रमाण उपस्थित की गई है, वह यह है कि जापान सरकार ने आजाद हिन्द सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रदान किये थे, उसने जियावाड़ी प्रदेश के लगभग १५० वर्गमील क्षेत्र

पर कब्जा कर लिया था और उसने चार से छः मास तक मणीपुर और विष्णुपुर के प्रदेशों पर शासन किया था । अण्डमान और निकोबार के सम्बन्ध में सबूत पत्र के गवाह लेफ्टिनेंट नाग ने निश्चित रूप से बताया है कि जापान सरकार ने दोनों द्वीप आजाद हिन्द सरकार को दे दिये थे । जापान की सरकार ने धाकायदा इसकी घोषणा की थी, जो एक दस्तावेज के रूप में अदालत में सिद्ध हो चुका है । इस दस्तावेज में जनरल तोजो का वह वक्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि जापान सरकार आजाद हिन्द सरकार को अण्डमान एवं निकोबार के द्वीपों को प्रदान करना चाहता है । यह घटना ५ नवम्बर १९४३ को हुई थी ।

भारत की स्वाधीनता के सम्बन्ध में जापान के प्रधान मंत्री जनरल तोजो को टोकियो में हुए बृहत्तर पूर्वी एशियाई सम्मेलन में हुए भाषण को उद्धृत करके श्री देसाई ने कहा कि इस घोषणा के अनुसार आजाद हिन्द सरकार की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर के हाथों में जापानी अधिकारियों ने दोनों द्वीप समारोहपूर्वक सौंप दिए थे । उनके शासन के वास्तविक स्वरूप और विस्तार के विषय में सबूत और बयान पत्र में थोड़ा मतभेद है । मंहत्व की बात उनका आजाद हिन्द सरकार के हाथों में दिया जाना है, न कि उस परिस्थिति में यहां की गई शासन-व्यवस्था । उदाहरण के लिए किसी घर की बिक्री और खरीद की बात लीजिए । किसी घर के बिक्र जाने पर भी उस पर बिक्रेता का प्रत्यक्ष अधिकार होने में कुछ समय लग सकता है । कर्नल



अश्वत्थामा पृष्ठ दृश्य — मत्स्य के नदील म्म दिलीपमिह, मर नेजवहादुर मन् ५०  
 नेहन्, मर नवर्णो देहचन्द, अरिष्टम प्रच्छेदयाम ।

लोकनाथन ने जिरह के समय यह साफ तौर पर बार-बार स्वीकार किया है कि इनकी शासन-व्यवस्था जापानियों ने पूरी तरह अस्थायी सरकार को नहीं दी थी। यह सिद्ध हो चुका है कि उनका शासन अपने हाथों में लेने के लिए ही कर्नल लोकनाथन वहां पहुंचे थे। यह सही है कि वे वहां की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था अपने हाथ में न ले सके। वे केवल शिक्षा और न्याय-विभाग का ही काम अपने हाथों में ले सके; किन्तु इनके सम्बन्ध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है उनका नया 'नामकरण', 'शहीद' और 'स्वराज्य' शब्दों से किया गया था।

अब मैं जियाबाड़ी के प्रश्न पर बहस करूंगा। जियाबाड़ी ५० वर्गमील का एक प्रदेश है और वहां की आबादी १५,००० है। वहां चीनी का एक मिल था। वहां की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था आजाद हिन्द सरकार के कार्यकर्त्ता करते थे, जो आजाद हिन्द दल के सदस्य थे। आजाद हिन्द दल द्रष्टव्य व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन था, जिसे आजाद हिन्द सेना के अधिकार में आने वाला प्रदेश शासन-व्यवस्था के हेतु सौंप दिया जाता था। शिवसिंह तथा अरशाद ने जो बयान दिये हैं, उनकी सच्चाई की जांच की आवश्यकता उनकी जिरह के समय सरकारी वकील को प्रतीत नहीं हुई।

अदालत के समक्ष यह भी सिद्ध हो गया है कि आजाद हिन्द फौज के वर्मा की सीमा पार कर भारत पहुंचने पर एक घोषणा पढ़ी गई थी, जिसके दो हिस्से थे। एक पर आजाद हिन्द फौज के अध्यक्ष के तथा दूसरे पर दक्षिण-पूर्वी फ्रान्स के

आज्ञानुसार कावाचे के हस्ताक्षर थे। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जापानी सेनाओं के हस्तगत किया गया भारत का प्रदेश शासन-व्यवस्था के लिए आजाद हिन्द फौज को सौंप दिया जायगा। जिस समय जापानी सेनाये और आजाद हिन्द फौज मण्डीपुर और बिष्णुपुर के हल्कों में लड़ रही थी, उस समय १५००० वर्ग मील के इन स्थानों पर आजाद हिन्द सरकार के आजाद हिन्द दल का ही शासन था।

आजाद हिन्द सरकार के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करते समय उसकी, साधन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी विचार करना उचित होगा। अदालत के समक्ष इस बात के प्रमाण दिए जा चुके हैं कि इस अस्थायी सरकार को २० करोड़ रुपये दान से प्राप्त हुए थे और इस रकम से इस सरकार और उसकी फौज का खर्च चलाया जाता था। दीनानाथ ने, जो आजाद हिन्द बैंक के डाइरेक्टरों में से थे, इस सम्बन्ध में अदालत के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यर्मा और मलाया के बीच, उस अवधि में २० करोड़ रुपये की सम्पत्ति आजाद हिन्द फौज के अधिकार में आ गई थी। जियावाड़ी की आय इसके अलावा थी। यर्मा तथा मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार फिर से फायम होने पर वे सभी दस्तावेज, जो अस्थायी सरकार के अधिकार में थे, पूर्णतया सुरक्षित पाए गए। अवश्य ही यह आश्चर्यजनक है। सद्यतन पक्ष की ओर से अराधमान और निकोबार की तत्कालीन शासन-व्यवस्थासम्बन्धी जो मासिक रिपोर्ट पेश की गई हैं, उनसे भी इस बात का पता चलता है। मैं जोर देकर कहूंगा कि



आजाद हिन्द सरकार वस्तुतः एक सुसंगठित सरकार थी। सरकारी वकील केवल आधे ही दस्तावेज अदालत के सामने पेश कर सके हैं। इन पेश किए गए प्रमाणों से ज्ञात होता है नि रंगून के पतन के बाद यह बैंक बंद कर दिया गया और उसकी जायदाद, जो ३५ लाख रुपये की थी, ब्रिटिश-अधिकार में चली गई। मेरे समस्त कथन का यही तात्पर्य है कि आजाद हिन्द सरकार के पास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन-सम्पत्ति थी।

इसके बाद श्री भूलाभाई देसाई ने सुप्रसिद्ध टिकट-संपादक डगलस आर्मस्ट्रांग द्वारा सम्पादित एवं लन्दन से प्रकाशित होने वाले 'स्टैम्प कलेक्टिंग' नामक साप्ताहिक के १० नवम्बर १९४५ अंक के पृष्ठ १३६ कालम-१ में प्रकाशित एक लेख को प्रमाणस्वरूप उद्धृत करना चाहा। सरकारी वकील के अपत्ति करने पर भी श्री देसाई ने इसको पढ़कर बताया कि आजाद हिन्द सरकार ने अपने टिकट और मोहरें भी तैयार कर ली थीं। इस लेख का शीर्षक था—“इम्फाल के टिकट जो कभी जारी नहीं हुए।”

श्री भूलाभाई देसाई ने आगे कहा कि सबूतों से ज्ञात होता है कि अस्थायी आजाद हिन्द सरकार का अपना सिविल तथा सैनिक गजट था। इन तथ्यों के आधार पर जो कानूनी प्रश्न में उपस्थित करना चाहता हूँ, वह यह है कि जिन परिस्थितियों में आजाद हिन्द सरकार की स्थापना हुई तथा जिन में वह काम कर रही थी, उनमें उसे युद्ध करने का पूरा अधिकार था और भारत की मुक्ति के लिये ही उसने युद्ध किया था। अदालत के समक्ष

पेश करने को नहीं कह सकते, जैसी कि गधारण नागरिक अपराधों के सम्बन्ध में पेश करने को कहा जाता है। श्री देसाई ने फिर व्हिटन के कथन को उद्धृत किया कि “राष्ट्र-संघ तक कुछ प्रसंगों पर युद्ध के वैधानिक होने की बात स्वीकार करता रहा है। अवश्य ही आक्रमणात्मक लड़ाई के प्रति वह स्पष्ट रूप से विरोध प्रकट कर चुका है। इसी लिये १६००-०१ में १४ वें लुई द्वारा स्टैमबर्ग पर तथा १६१३ में इटली द्वारा कोर्फू पर किये गये सशस्त्र आक्रमण को ‘युद्ध’ नहीं कहा जा सकता। उक्त आक्रमणों के शिकार होने वाले राष्ट्रों ने कोई युद्ध-घोषणा नहीं की थी।” इसी प्रकार के कई अन्य ऐतिहासिक उदाहरण व्हिटन ने दिये हैं। तात्पर्य यह है कि आजाद हिन्द सरकार द्वारा की गयी युद्ध घोषणा पूर्णतया वैधानिक थी। दूसरी बात यह कि युद्धविषयक अन्तर्राष्ट्रीय विधान को आप अपरिवर्तनशील नहीं मान सकते। यह तो ऐसा विधान है कि जिसका मानव-संस्कृति के विकास के साथ बराबर विकास होता रहा है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय विधान उस अवस्था पर पहुँच गया है कि उसके अनुसार यदि सम्पूर्ण संसार के लिये स्वाधीनता और प्रजातंत्र का कोई अर्थ है, तो विदेशी शासन से छुटकारा पाने के हेतु किया गया कोई भी युद्ध पूर्णतया न्यायोचित हो जाता है। यदि यह जान लिया जाय कि भारतीय सैनिक जर्मनी, इटली और जापान से मिटेन की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये लड़ें, किन्तु आजाद हिन्द सरकार दूसरे देशों की, जिनमें इंग्लैंड भी सम्मिलित है, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए न लड़े; तो यह

न्याय का गला घोटना ही होगा। इसी कारण हम कहते हैं कि इस विशिष्ट युद्ध का औचित्य सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी लिये आप इस मामले के अभियुक्तों से सफाई पेश करने को कह नहीं सकते। हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि अभियुक्तों ने सभ्य युद्धसंचालनसम्बन्धी नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। मैं इसी एक बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ। इसी लिये मैं यह कहता हूँ कि इस अदालत के सामने पेश किये गये मामले का स्वरूप वस्तुतः बहुत ही संकुचित है।

किसी जमाने में यह जोखी विचारधारा प्रचलित थी कि केवल स्वतन्त्र या बड़े राष्ट्र को ही युद्ध-घोषणा करने का अधिकार है। इससे गुलाम जातियों की स्वतन्त्रता का प्रश्न तो ज्यों का त्यों बना रहता है। स्वाधीनता के लिये ये जातियाँ कभी भी युद्ध-घोषणा कर नहीं सकती। इसीलिये आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधान में ऐसी गुलाम जातियों के संगठित होने तथा सैन्य-संगठन द्वारा युद्ध करने का अधिकार मान लिया गया है। इस युद्ध के समय ऐसी सेना द्वारा किये गये कार्यों के लिये उक्त सेना के किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत रूप से म्युनिसिपल कानून के अनुसार मामला चलाया नहीं जा सकता। यह बात अथ मान-सी ली गयी है कि युद्ध-रत दोनों दलों का स्वतन्त्र होना या स्वतन्त्र राष्ट्र अथवा बड़ा राष्ट्र मान लिया जाना-सगस आवश्यक नहीं है। किसी स्वतन्त्र राष्ट्र और उसके अधीन रहने वाली जाति के बीच भी 'युद्ध' छिड़ सकता है। शीघ्र-युद्ध

के बाद से उसके द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों का स्वरूप किसी स्वतन्त्र राष्ट्र के कार्यों के समान ही माना जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधान की विभिन्न पुस्तकों के उदाहरण देते हुए देसाई ने अन्त में 'ब्रिटिश ईयर बुक आफ इण्टरनेशनल ला' के सन् १९३७ के संस्करण के १८ वें पृष्ठ के एक अंश का हवाला देते हुए कहा कि "सच बात तो यह है कि यदि आजाद हिन्द फौज अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो गई होती, तो अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार उसे एक सफल क्रान्ति का नाम दिया जाता तथा उसके द्वारा स्थापित सरकार को कानून-सम्मत सरकार मान लिया जाता । सफल क्रान्ति के पूर्व तो युद्ध की ही स्थिति होती है और यही मेरे मामले से सम्बन्ध रखने वाली महत्वपूर्ण बात है । यदि मैं यह सिद्ध कर सकूँ कि आजाद हिन्द फौज युद्ध कर रही थी, तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार उसे वे ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जो किसी भी स्वतंत्र देश की सेना को प्राप्त होते हैं । १८६० में दक्षिण इटली में इटालियन देशभक्त गैरियाल्डी द्वारा इटली की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया था । ग्रेट ब्रिटेन को इस मामले में तटस्थता की नीति का अवलम्बन करना था । इस सम्बन्ध में इंग्लैंड की तत्कालीन सम्राज्ञी को उसके सलाहकार सर जान हाडिंग द्वारा दी गई सलाह की ओर श्री देसाई ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया । सर जान की राय में इटली के राजा के विरुद्ध गैरियाल्डी की युद्ध-घोषणा संव्या नियमसंगत थी तथा उसको या उसके सेनाधिकारियों को हर्कू नहीं कहा जा सकता था । वे वाकायदे

युद्ध कर रहे थे तथा ब्रिटिश 'नौसैनिक अधिकारियों' ने 'उन्हें स्वीकृति या मान्यता प्रदान की थी।

स्पैनिश अमेरिकन उपनिवेशों द्वारा किये गये विद्रोहों का उल्लेख करते हुए श्री देसाई ने कहा कि "अपनी स्वाधीनता-प्राप्ति के निमित्त अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने सम्बन्धी औपनिवेशिक राष्ट्रों के अधिकारों को ब्रिटिश सरकार भी स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।" १९३७ में हुए स्पेन के गृहयुद्ध के सम्बन्ध में १४ अप्रैल १९३७ को कामन्स सभा में इंग्लैण्ड के तत्कालीन विदेश-सचिव मि० एन्थोनी ईडन तथा राइट आनरेबल मि० चर्चिल द्वारा स्पेन के सरकारविरोधी दल अर्थात् प्रजातन्त्र-वादी दल के समर्थन में दिये गये भाषणों का महत्वपूर्ण अंश पढ़ कर सुनाने के बाद श्री देसाई ने निम्नलिखित, किन्तु स्पष्ट भाषा में बोलते हुए एक गुलाम कौम के आजादी के लिये युद्ध करने के अधिकार का प्रश्न। उपस्थित किया आपने कहा कि पफादारी का प्रश्न यहां लागू नहीं होता। कानूनी बन्धनकारी विरफाल तक नहीं रखी जा सकती। यदि ऐसा हो, तो कोई भी गुलाम देश कभी भी आजादी हासिल नहीं कर सकेगा। यह कथन कि युद्धघोषणा करने वाली सेना या सरकार के अधिकार में कुछ प्रदेश होना चाहिये, गत महायुद्ध में असत्य सिद्ध हो चुका है। इन दिनों लन्दन आकर बसने वाली फ्रेंच, डेच या युगोस्लाविया की सरकार के पास एक ईश्वर भी जगह नहीं। किसी ने उन्हें अपने देशों की स्वाधीनता-प्राप्ति के निमित्त लड़ने से मना नहीं किया। वह बात सही है कि लन्दनस्थित विदेशी सरकारों को

अपने देशों की स्वाधीनता को खोये हुये कुछ दिन हुए थे. जबकि हम १५० वर्षों से पराधीन हैं। फिर भी स्वाधीनता प्राप्त करने का हमारा अधिकार वैसा ही अबाधित होना चाहिये, जैसा कि इन सरकारों का था। हम भारतीय हैं। इसलिये हमारे प्रति पक्षपात की दृष्टि से देखना न्यायसंगत नहीं है। अपने इस कथन को और स्पष्ट करते हुए श्री देसाई ने कहा कि जब फ्रांस में मैक्सिमिलियन फौजें फ्रांस की स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये लड़ रही थीं, तब मार्शल वेतांकी सरकार उस देश पर अधिकृत रूप से शासन कर रही थी। बाद में वह जर्मनों से मिल गई। इससे आप समझ जायेंगे कि मैक्सिमिलियन फौजें स्वदेश की स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये तत्कालीन फ्राँच सरकार के विरुद्ध लड़ रही थीं। यदि ये फौजें अपने उद्देश्य में असफल हो जातीं, तो अवश्य ही उनकी विरोधी फ्राँच-सरकार ने उन्हें विद्रोही सम्बोधित कर गोली से उड़ा दिया होता। फील्ड मार्शल आइसेनहोवर ने इन सेनाओं को अभयदान दिया था। उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति समूह अपने देश की मुक्ति के लिये अपनी ही सरकार के विरुद्ध लड़ता है, तो उसे वे समस्त अधिकार मिलने चाहियें, जो सैनिकों को प्राप्त रहते हैं। जनरल आइसेनहोवर ने ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन के रेडियो से इस विषयक स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा था कि जो भी कोई मैक्सिमिलियन फौजों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, उसकी हम खबर लिये बिना न रहेंगे। इसी प्रसंग में भारत उपमन्त्री मि० हण्डर्सन के पार्लमेंट में दिये गये एक वक्तव्य की ओर अदाखत का ध्यान खींचते हुये श्री देसाई ने कहा कि मि० हण्डर्सन

ने भी अन्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि सघाट के विरुद्ध युद्ध करना गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता ।

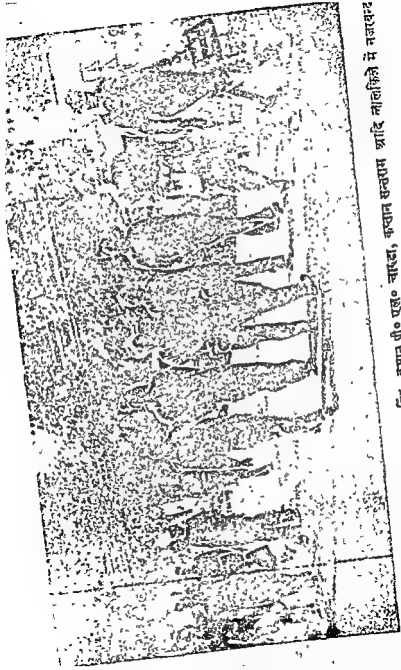
इसके बाद श्री देसाई ने बकादारी के मुख्य प्रश्न पर धर्म की । आपने सिंगापुर में किये गये आत्म-समर्पण के बाद आजाद हिन्द फौज के निर्माण के इतिहास का सिद्धान्तोक्त कर रहे हुए कहा कि कप्तान एम० आर० अरशाद ने ट्रिब्यूनल ठीक ही कहा है कि जब अंग्रेजों ने हमें जापानियों के हाथों में सौंप दिया, तब हमारी बकादारी सिवाय हमारे देश के किसी और के प्रति नहीं रह सकती थी । इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान की भिन्न भिन्न परिस्थितियों का विवेचन करते हुये आपने कहा कि इंग्लैण्ड में बकादारी की शपथ जब राजा और देश के प्रति ली जाती है, तब इस देश में वह सिर्फ राजा के प्रति ली जाती है । जब हम स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये राजा के विरुद्ध लड़ते हैं, तब बकादारी का सवाल उठ ही नहीं सकता । अपनी आत्मा को बेचे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने को किसी अन्य के प्रति बकादारी रोकती है । ऐसी स्थिति में हम सदा गुलाम ही बने रहेंगे । अंग्रेजों ने जिन युद्धयन्त्रियों को जापान के हाथों में दे दिया था, उनके सामने परिस्थितियों ने राजा और देश में से किसी एक को चुनने का प्रश्न पैदा कर दिया था । इस सचार्ड को यों ही आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता ।

सरकारी पक्ष की ओर से यह कहना बहुत भरी पात होगी कि आजाद हिन्द सरकार और फौज जापानियों की कठपुतली

ने राजा की अपेक्षा देश को तरजीह दी और दोनों में से देश के प्रति की गई वफादारी की शपथ को प्रधानता दी। इस ऐतिहासिक उदाहरण में राजभक्ति और देशभक्ति के बीच पैदा होने वाले द्वन्द का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इस घोषणा के अनुसार दोनों देशों में पांच वर्षों तक युद्ध चला और १७८१ में वर्तमान स्वतन्त्र अमेरिका की स्थापना हुई और वह इतना शक्ति-सम्पन्न बन गया कि उसने गत महायुद्ध में सभ्यता को विनाश से बचा लिया। यदि इस उदाहरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो न्याय को सर्वथा ही तिजांजलि दे डालनी होगी।

आजाद हिन्द सरकार के घोषणापत्र की अमेरिका के घोषणापत्र के साथ तुलना और फरेर-पार्क की घटना तथा भारत की तत्कालीन परिस्थिति का उल्लेख करते हुये श्री वेसाई ने कहा कि अमेरिकियों ने १७७६ में जो कुञ्ज किया, वही करना आजाद हिन्द फौज के लिये भी न्यायसंगत ही था। इसके बाद आपने राष्ट्रगति द्रमैन और श्री चर्चिल की कुछ दिन पहले की गई वे घोषणायें उद्धृत की, जिनमें कहा गया है कि ईश्वर ने सबको एक-सा पैदा किया है। वे सब एकान्वरूपसे आजादी और सुख-समृद्धि के अधिकारी हैं। यदि इसमें कोई सरकार बाधा पैदा करती है, तो जनता का अधिकार है कि उसको खत्म कर दे। सुप्रसिद्ध अमेज़-विधानवेत्ता, मि० वेटेल की १६१७ में प्रकाशित "ला आफ़ नेशन" पुस्तक का उद्धरण भी पेश किया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने आधीन कमजोर राष्ट्र की रक्षा न कर सके, तो पराधीन राष्ट्र स्वयं स्वतन्त्र हो





आदि लालकिले में नजरबन्द  
कप्तान पी० एल० चारदा, कप्तान सन्ताराम  
मेजर चरणसिंह, कप्तान पी० एल० चारदा, कप्तान सन्ताराम  
मेजर चरणसिंह, कप्तान पी० एल० चारदा, कप्तान सन्ताराम

सकता है। आस्ट्रिया का लारेन शहर इसी आधार पर वहां के  
 ड्यूक से सर्वथा स्वतन्त्र हो गया था। ठीक यही स्थिति आजाद  
 हिन्द फौज की थी। युद्धबन्दी के लिये ऐसा कोई भी वनवन शेष  
 नहीं रह जाता, जो उसको अपने देशकी आजादी के लिये लड़ने  
 से रोक सके। युद्धबन्दी शत्रु की सेना में भरती न होकर उसके  
 लिये मेहनत-मजूरी का काम तो कर ही सकता है। इस लिये  
 इस बारे में आजाद हिन्द फौज और जापानी फौज के दारस्परिक  
 सम्बन्ध को भुलाना नहीं चाहिये। नाग, बन्चनसिंह और  
 अरशाद आदि की गवाहियों के लम्बे उद्धरण पेश करते हुये और  
 पहिली आजाद हिन्द फौज के भंग करने तथा उस समय जापानियों  
 के साथ हुये मतभेद का विस्तार के साथ उल्लेख करते हुये  
 श्री देसाई ने कहा कि वे अपने देश की आजादी के लिये जापान  
 के साथ भी लड़ने को तय्यार थे। उसके वायदों की सच्चाई पर  
 भरोसा करके ही उस के साथ उन्होंने दोस्ती की थी। अपने इस  
 कथन के समर्थन में श्री देसाई ने लैफ्टिनेन्ट कर्नल लोकनाथन  
 की गवाही के भी अनेक अंश उद्धृत किये और वंगकौक  
 सम्मेलन के तेरहवें प्रस्ताव का वह अंश भी उद्धृत किया, जिसमें  
 कहा गया था कि आजाद हिन्द फौज का उपयोग हिन्दुस्तान में  
 विदेशी शासन का अन्त करके उसकी स्वाधीनता की प्राप्ति तथा  
 उसमें सहायक होने वाले कार्यों के लिये ही किया जायगा।  
 कर्नल नाग की गवाही से एक और उद्धरण उपस्थित करके  
 श्री देसाई ने कहा कि यह भी सिद्ध हो चुका है कि आजाद हिन्द  
 फौज के सभी अफसर हिन्दुस्तानी थे और जापानियों की

बाहरी देखरेख होने पर भी अन्दरूनी मामलों में वह संबंध स्वतन्त्र थी। यह कहना भयंकर भूल है कि फौज में युद्ध-बन्दी बने रहने की अपेक्षा अधिक आराम था। कम से कम मृत्यु का भय तो फौज में कम न था। अभियुक्तों ने अफसर की हैसियत से और श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भी बार-बार यह कहा था कि कोई भी सैनिक कभी भी फौज से अलग हो सकता है। भरती इतनी खेच्छा से होती थी कि भरती होने वालों को अत्यधिक संख्या में शस्त्रों के अभाव के कारण प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस स्थिति में जोर-जुल्म या बल-प्रयोग की आवश्यकता ही क्या थी? अपने इस कथन को समर्थन में श्री देसाई ने अनेक गवाहों की गवाहियां पेश की और विस्तार के साथ उनकी मीमांसा की। श्री धारगलकर की गवाही को सन्देहपूर्ण बताने के लिये श्री देसाई ने उसका विवेचन किया और कहा कि अभियुक्तों पर जोरजबरदस्ती करने, बलप्रयोग करने या धमकी देने का अभियोग लगाना निराधार है। सद्युक्त पक्ष के गवाहों की गवाहियों के आधार पर आपने यह सिद्ध किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या करने अथवा उसमें सहयोग देने के अभियोग प्रमाणित नहीं किये जा सकते हैं। सरकारी वकील ने यह मान लिया है कि जय युद्धबन्दियों पर अत्याचार किये गये, तब न तो अभियुक्त उपस्थित थे और न उनका उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध ही था। इन तयाकथित अत्याचारों का विश्लेषण करके आपने कहा कि वे तो अनुशासन-भंग के लिये दी गई सिर्फ सजायें ही थीं। सरकारी गवाह नं० १० अहमद

नवाज ने अपने पर किये गये. जिस 'अत्याचार' का वर्णन किया है. वह बहुत ही हास्यास्पद है। यह अत्याचार यह था कि उसको गोबर और सोड़ा पेश से खाद तय्यार करने को कहा गया था। अनुशासन भंग की सजाओं को आजाद हिन्द फौज में भरती होने के लिये किया गया बल-प्रयोग बताना उपहासास्पद है, जो कि पढ़ाये हुये तोते की तरह बताया जा रहा है। इत्यादि उसमें सहयोग देने के अपराधों का उपस्थित सामग्री के आधार पर सिद्ध कर सकना असम्भव है। अभियुक्तों को सन्देह का लाभ तो मिलना ही चाहिये। चार व्यक्तियों के गोली से उड़ाने के बारे में तो आजाद हिन्द फौज की प्राइमाफेमी रिपोर्ट मिलती है. किंतु मुहम्मद हुसैन के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण उल्लेख नहीं है। इस बारे में पेश की गई गवाहियां विश्वास के योग्य नहीं हैं। जिस दिन लैफ्टिनेण्ट डिह्लन की उपस्थिति में गोली से मुहम्मद हुसैन को मृत्युदण्ड देने की बात कही गई है, उस दिन वे बीमार थे। इसी आशय का उस दिन ६ मार्च १९४५ का उनका एक पत्र भी श्री देसाई ने पढ़ कर सुनाया। गुलाम मुहम्मद, गंगाशरण, अह्लादिया आदि गवाहों के कथनों की मीमांसा करते हुये श्री-देसाई ने कहा कि चार व्यक्तियों को सजा केवल सुनाई ही गई थी। वह कभी भी कारमान्वित नहीं की गई। श्री देसाई ने अह्लादिया यथा जागीरीराम की गवाहियों के बारे में कहा कि उनको लिखा पढ़ाकर पेश कर दिया गया है। चक महत्वपूर्ण मुद्दा श्री देसाई ने यह उपस्थित किया कि कि सबूत पत्र के गवाह यह कहने से सर्वथा असमर्थ हैं कि वे छार व्यक्ति निश्चित रूप से

कौन थे ? हत्या के अभियोग में निश्चित व्यक्ति का पता देना आवश्यक है। फर्नेल किटसन और गुलाम मुहम्मद ने माना स्वीकार किया है कि कप्तान सहगल ने उनको युद्धवन्दी मानने की शर्त के स्वीकार किये जाने पर ही आत्मसमर्पण किया था। इसलिये उनको युद्धवन्दी मान कर रिहा कर देना चाहिये।

अन्त में आपने वैधानिक प्रश्न उपस्थित करते हुए सारे ही अभियोग को अधैधानिक बताया। प्रान्तीय सरकार की अनुमति के बिना फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। प्रिवी काउंसिल के एक फैसले के आधार पर आपने कहा कि जो अपराध सब अभियुक्तों ने मिलकर किया है, उसी के लिये सम्मिलित मुकद्दमा चलाया जा सकता है। हत्या या उसमें सहयोग देने के अभियोग इस दृष्टि से सर्वथा अवैध है। अपनी सारी बहस का सिंहावलोकन करने के बाद श्री देसाई ने जोरदार शब्दों में कहा कि तीनों अभियुक्तों के सर्वथा निर्दोष होने का ऐलान अदालत को करना चाहिये। आप ने यह भी कहा कि यदि सरकारी वकील कोई नया मुद्दा पेश करें, तो मुझे उसका लिखित उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

जज एडवोकेट ने इस पर कानूनी आपत्ति की और श्री देसाई की इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया कि सरकारी वकील को यह आदेश दिया जाय कि वे कोई नया मुद्दा अपनी बहस में पेश न करें। सरकारी वकील की मांग पर अदालत की कार्यवाही २२ दिसम्बर के लिये मुलबंदी कर दी गई।

## देशभक्ति की विजय

सरकारी वकील ने २२ दिसम्बर को अपना लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ सुनाया। सरकारी वकील ने सब अभियुक्तों को सब अभियोगों में दोषी ठहराते हुये कहा कि प्रचुर गवाहियों से यह दिखाया जा चुका है कि अभियुक्तों ने जो कुछ भी किया, वह स्वार्थ की भावना से नहीं; अपितु देशभक्ति की भावना से ही प्रेरित होकर किया था। उन्होंने बुद्धिमत्ता की हो या वे यहकावे में आ गये हों, किन्तु उन्होंने देश की सेवा की भावना से ही यह सब किया। कानूनी दृष्टि से यह बचाव भले ही न हो, किन्तु अभियुक्तों को दोषी माने जाने पर इस पर न्यायदृष्टि से विचार अवश्य किया जा सकता है। सजा के लिये अदालत के हाथ बंधे हुये हैं और कम से कम जो सजा दी जा सकती है, वह है आजीवन कारावास। लेकिन, अदालत यदि यह समझे कि उसके सामने पेश की गई गवाहियों के आधार पर सजा कम की जा सकती है, तो वह अपनी सम्मति लिख कर सजा की पुष्टि करने वाले अधिकारी के पास विचार के लिये भेज सकती है। सरकारी वकील के वक्तव्य में तीस हजार से कुछ अधिक ही शब्द थे और उसको पढ़ने में उनको चार घण्टे लगे।

सरकारी वकील ने तीनों अभियुक्तों को आजाद हिन्द फौज की भरती करने, फाज को संगठित करने और सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के आदेश जारी करने का अपराधी बताते हुये कहा कि वे सब १ सितम्बर १९४२ को आजाद हिन्द फौज में भरती हुये थे। उन्होंने दूसरों को भी सम्राट के प्रति अपनी वफादारी को तिलांजलि देने के लिये भड़काया था और उन्होंने सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना स्वयं स्वीकार किया है। जुल्म-ज्यादती, बल-प्रयोग और धमकी के अभियोग को सिद्ध करने के लिये गवाहियां उद्धृत करने में सरकारी वकील ने एक पण्डा ले लिया और अपने पक्ष के समर्थन में श्री रासबिहारी बोस की लिखी हुई 'हमारा संघर्ष' पुस्तिका भी प्रस्तुत की। अभियुक्तों के भाषणों से, सरकारी वकील ने कहा कि यह प्रगट है कि उनको इन जुल्म-ज्यादतियों का पता था और उनसे बचने के लिये युद्ध-अन्वितियों से फौज में भरती होने को कहा जाता था।

आजाद हिन्द सरकार की स्थापना को स्वतः ही अपराध बताते हुये सरकारी वकील ने कहा कि युद्ध जिस उद्देश्य से लड़ा गया, वह भी सर्वथा नगण्य है। उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, कार्य स्वतः ही एक अपराध है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को जब तक किसी देश का विधान स्वीकार न कर ले, तब तक उसको बचाव के लिये पेश नहीं किया जा सकता। ताजिरात हिन्द की ७६वीं धारा में जिस कानून का उल्लेख है, उसका मतलब ब्रिटिश भारत में प्रचलित कानून से है। युद्ध-रत राष्ट्र के लिये आवश्यक है कि देश का कुछ भाग उसके आधीन हो, उसका अपना शासन हो

और युद्ध-सम्बन्धी नियमों के अनुसार युद्ध का संचालन किया गया हो। इस मामले में न तो कन्ति होकर कोई सरकार ही कायम हुई थी और न कोई गृह-युद्ध ही हुआ था। यह लड़ाई दो राष्ट्रों के बीच नहीं हुई थी। पहिले कानूनन स्थापित हुई सरकार ने विरोधियों को युद्ध-रत राष्ट्र नहीं माना था। उनके हाथ में अपने राष्ट्र या देश का ऐसा कोई भी भाग न आया था, जिसमें उन्होंने अपना शासन कायम था होता और जिसे वे अपना बता सकते।

इंग्लैण्ड और अमेरिका के विधान में बड़ा अन्तर यह है कि इंग्लैण्ड के विधान पर अन्तर्राष्ट्रीय विधान हावी नहीं हो सकता और अमेरिका के विधान पर वह हावी हो जाता है। इस लिये अमेरिका का उदाहरण यहां लागू नहीं हो सकता। आजाद हिन्द सरकार को ब्रिटिश सरकार की मान्यता मिले बिना युद्ध-रत राष्ट्र की सुविधायें या कानूनी अधिकार मिल नहीं सकते।

आजाद हिन्द सरकार को जागी बताते हुये सरकारी वकील ने कहा कि उसके पास न तो एक इंच भूमि थी और न वह कोई कर या टैक्स ही वसूल करती थी। वह तो तय अस्तित्व में आने वाली थी, जब जापान ने हिन्दुस्तान को जीत कर उसके हाथों में दे दिया होता। जापान ने अपना मतलब गांठने को उसे अन्य सरकारों से मान्यता दिला दी थी। यह इतिहास से सिद्ध है कि हिन्दुस्तान को जीतने के बाद जापान ने क्या किया होता? उसके वायदों की वास्तव में कुछ भी कीमत न थी। जापान को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी विजित प्रदेश



पारे देश में विजली की तरह फैल गया और चारों ओर हव, उत्साह तथा उल्लास की लहरें दौड़ गईं ।

कनैल शाह नवाजखां ने रिहाई के बाद ठीक ही कहा था कि "हमारी रिहाई देश की विजय है, जिसकी संयुक्त मांग के सामने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं । हमने अपने को देश की आजादी के लिये न्यौछावर करने की शपथ नेताजी के सामने ली थी । हमारी वह शपथ आज भी वही कायम है । हमने संयुक्त और महान् राष्ट्र की आजादी के ऊँचे ध्येय से युद्ध का श्रीगणेश किया था और उसके लिये हमारी वह लड़ाई अब भी जारी रहेगी । देश के बाहर हमने यह लड़ाई शास्त्रास्त्रों और गोलाबारूद से लड़ी थी । अब हम उसी पवित्र ध्येय के लिये इस लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से जारी रखेंगे । हिन्दु-मुस्लिम-एकता को सुदृढ़ बनाना हमारा मिशन होगा ।"

कनैल शाह नवाजखां के ये शब्द आजाद हिन्द फौज के वीर सैनिकों में नेताजी द्वारा उनमें मरी गई अदम्य भावना के द्योतक हैं । इम्फाल के बीचों से पराजित होकर लौटने पर भी यह भावना मुर्झाई नहीं, अपितु अजेय बनी हुई है । वह बिन-दूनी रात चौगुनी फल-फूल रही है और चारों ओर फैल रही है ।

जय हिन्द ।

इनकलाव जिन्दावाद

आजाद हिन्द जिन्दावाद ।

## हमारे एजेण्ट

बम्बई—जयहिन्द बुक डिपो, सी० पी० टैंक ।

न्यावर—श्री भंवरलाल आर्य, आर्य न्यूजपेपर एजेन्सी ।

ग्वालियर—श्री एम० घी० जैन एण्ड प्रदर्स, बड़ा सराफा ।

शेखावाटी (सीकर)—सीकर ट्रेडिङ्ग कम्पनी ।

फराची—सिन्धु बुक स्टोर्स, महात्मा गांधी रोड और राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति ।

शामली ( मुजफ्फर नगर )—कमला खादी भण्डार ।

अलवर—राजस्थान पुस्तक भण्डार ।

भरथना (इटावा)—श्री प्यारेलाल गुप्ता 'आज्ञाद' ।

लाहौर—हिन्दी भवन और पंजाब ग्राम सेवा भण्डार ।

रायपुर—राष्ट्रीय विद्यालय बुक डिपो ।

देहरादून—साहित्य सदन, पुरानी कोतवाली ।

अम्बाला शहर—भारत पुस्तक भण्डार ।

कोटा—मोहन न्यूज एजेन्सी । भिवानी—शर्मा प्रदर्स ।

इन्दौर—नवयुग साहित्य सदन और दयानन्द मिशन ।

अम्बाला छावनी—अरविन्द कला मन्दिर ।

नाथद्वारा—श्री आर० एन० कपूर । लाहौर—जनरल स्टोर ।

मिकन्दराबाद और हैदराबाद—नेशनल न्यूज एजेंसी ।

परभणी—हिन्दी पुस्तक भण्डार ।

घरेली—प्रेम पुस्तक भण्डार । जोधपुर—किताब घर ।

मेरठ—लाइट हाउस । मैनपुरी—आर्य साहित्य मन्दिर ।

तिनसुखिया (आसाम)—श्रीकृष्ण खादी भण्डार ।

भरतपुर—आर्य मदर्स एण्ड कम्पनी ।

इलाहाबाद—विश्ववाणी कार्यालय, साउथ मलाका ।

थोकानेर—श्री गंगादास कौशिक, रेलवे स्टेशन रोड ।

नजीबाबाद (बिजनौर)—श्री महेन्द्रकुमार अग्रवाल ।

मुर्जा सिटी—श्री कन्हैयालाल शर्मा, न्यूज एजेण्ट ।

कोठवार—श्री दुर्गाप्रसाद भारतभूषण ।

कलकत्ता—कमला स्टोरस, अपर्गचितपुर रोड ।

रक्सौल—श्री मदनमोहन गुप्ता, विश्राम कुटीर ।

काशीपुर ( नैनीताल )—श्री शेरसिंह, बुक्सैलर ।

दमोह—श्री नन्दीलाल डालचन्द जैन ।

मुजानगढ़—श्री श्याम धुक् डिपो ।

अलमोड़ा—पन्त स्टोर, माला ।

जयलपुर—श्री के० सी० नेमा, आवर हाई स्कूल ।

सरदारशाहर—श्री महालचन्द हनुमानमल मोड़क और

मोहनलाल जैन, ज्ञान मन्दिर ।

नागपुर—श्री राममूर्ति मिश्र, सुभाषचन्द्र रोड ।

अलीगढ़—मौडन पब्लिशिंग हाऊस ।

गोरखपुर—हलचल साहित्य मन्दिर ।

रिवाड़ी—भारतीय साहित्य सदन ।

लखनऊ, कानपुर तथा आगरा आदि बड़े शहरों में प्रायः सभी पुस्तक विक्रेताओं के यहां पुस्तकें मिलेंगी ।

## “आजादी के लिये युद्ध”

हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास में आजाद हिन्द फौज का मोर्चा यदि सुनहरी अध्याय है, तो उसके मुकदमे में श्री भूलाभाई देसाई द्वारा की गई वहस एक अमर पृष्ठ है। अंग्रेजी में इसको लेकर कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। प्रान्तीय भाषाओं में भी इसका विशेष सम्मान हुआ है। यह वहस हिन्दी में लगभग साढ़े चार-पांच सौ पृष्ठों में पूरी होगी। इसके लिये पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने पर हम इसको अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं। मूल्य इसका लगभग ३।।-४) होगा। जो सज्जन प्रकाशित होने पर इसको खरीदना चाहें, वे अपना आर्डर अपना नाम और पता लिख कर हमें भेज दें। पेशगी दाम आदि न भेजें। यथेष्ट प्रोत्साहन मिलने पर पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय करते ही इसकी सूचना हम सबको यथासमय दे देंगे।

भारवाड़ी पब्लिकेशन्स, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली (१)

## ज य हि न्द

( यम्बई संस्करण )

मूल्य २)

अनेक चित्र—

पृष्ठ १५०

दो संस्करण समाप्त हो कर तीसरा  
भी हाथों हाथ विक रहा है।

“जयहिन्द युव डिपो”—सी० पी० टैंक—यम्बई ४

साहित्य सम्राट्

स्वर्गीय पं० नारायणप्रसाद 'वेताव'

की

अमर रचनायें :—

१. रामायण	२)
२. महाभारत	१।)
३. कृष्ण सुदामा	१।)
४. पत्नी प्रताप	१)
५. शंख की शरारा	।।)
६. मीठा जहर	।।।)
७. प्रासपुंज	२)
८. पिगलंसार	१।)
९. 'वेताव' रचित	१।।)
१०. नारायण शतक	≡)

मिलने का पता :—

१—भानु प्रिंटिंग वर्क्स, धरमपुरा, देहली ।

२—'कमल' कार्यालय, देहली ।